चौथी दुनिया

www.chauthiduniya.com

हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

1986 से प्रकाशित | 28 नवंबर – 04 दिसंबर 2016 | नई दिल्ली | हर शुक्रवार को प्रकाशित | Postal Regn. No. DL (ND)-11/6139/2015-17, RNI No. DELHIN/2009/30467

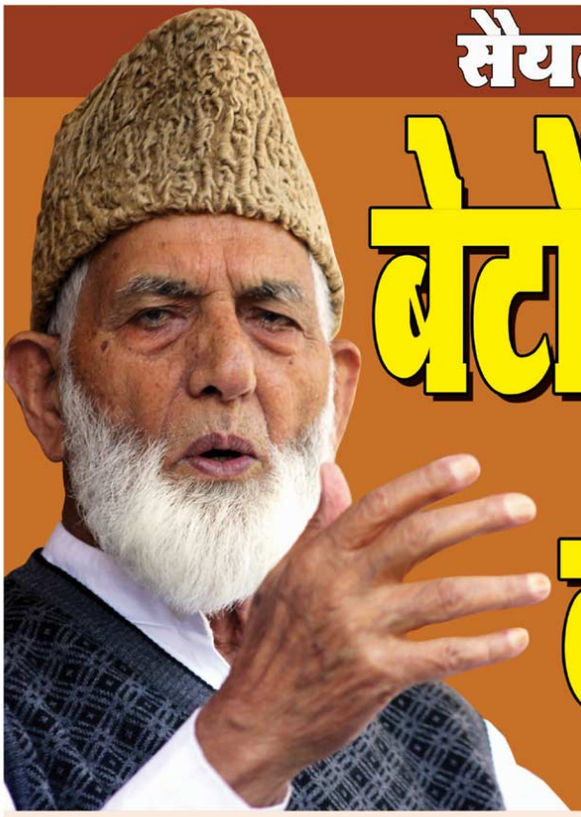

सैयद अली शाह गिलानी

बेटों को जवान होते नहीं देख पाए

सैयद अली शाह गिलानी हुर्रियत के नेता हैं. गिलानी साहब ताउम्र कश्मीर की अवाम के अधिकारों के लिए लड़ते रहे. कई बार जेल गए, नज़रबंद भी हुए, पुलिस की लाठियां भी खाई, ये उनके जीवन का एक पहलू है जिसे सारी दुनिया जानती है. लेकिन उनके जीवन का एक मानवीय पहलू भी है, जिसके बारे में दुनिया अनजान है. वो एक नरम दिल इंसान हैं. उनके सीने में भी धड़कता हुआ दिल है. वो एक पिता भी हैं. घर के आंगन में बच्चों के साथ न खेल पाने की कसक भी है. लेकिन सियासत और संघर्ष में अली शाह गिलानी का जीवन ऐसा उलझा कि अपने परिवार को समय ही नहीं दे पाए, जिसका उन्हें मलाल है. चौथी दुनिया के प्रधान संपादक संतोष भारतीय ने पहली बार गिलानी साहब के अंदर के उस इंसान को तलाशा, जो अपनी ज़िंदगी में अपने बच्चों के बचपन को न देख पाने, बच्चों को बड़ा होते हुए न देख पाने, बच्चों की शरारतों को न देख पाने की कसक को अपने दिल में ख़ामोशी के साथ बंद किए अपने मक़सद के लिए लड़ाई लड़ता रहा.

संतोष भारतीय

पिछली बार जब मैं कश्मीर गया था, तो गिलानी साहब से मिलने की कोशिश की थी, लेकिन पुलिस ने मिलने नहीं दिया था. हालांकि पुलिस के आईजी को हम बता कर आए थे कि हम गिलानी साहब से मिलने जा रहे हैं और उन्होंने कहा था कि ज़रूर मिलिए, कोई दिक्कत नहीं होगी. लेकिन शायद उन्होंने ही वहां फोर्स भेज दिए और बहुत ज्यादा फोर्स भेज दिए, जिसने गिलानी साहब के घर को और उस रास्ते को रोक दिया. मैं उस बार नहीं मिल पाया. मिलने का समय तीन बजे का था.

इस बार फिर मैंने कोशिश की और मैं गिलानी साहब के घर फिर पहुंचा. वक्त वही तीन बजे का था. मुझे सिर्फ़ 15 मिनट का समय गिलानी साहब ने दिया था. मैंने सोचा 15 मिनट में ही मैं जितनी बात कर सकता हूं, उतनी बात करूंगा और चूंकि पुलिस ने मुझसे कहा था कि मैं मोबाइल न ले जाऊं, तो मैं मोबाइल गाड़ी में छोड़कर गिलानी साहब के पास गया. एक लंबा सा अहाता है, जिसमें एक गलियारा है, गलियारे के बाद गिलानी साहब के कमरे तक एक सीमेंट का रास्ता है. बाईं तरफ़ छोटा सा लॉन है और उसके बाद वो बैठक शुरू होती है, जहां गिलानी साहब से लोग जाकर मिलते हैं. मैं उस बैठक में पहुंचा और मैंने सामने ख़ाली कमरा पाया. उस कमरे के भीतर मैं और मेरे साथ गए हारून रेशी बैठ गए. थोड़ी देर में गिलानी साहब के छोटे बेटे नसीम और उनके कुछ सहयोगी भी आकर सोफे पर बैठ गए. गिलानी साहब अंदर से आए और उस कुर्सी पर बैठ गए, जिसपर वो अक्सर बैठते हैं. मैंने शुरुआती दुआ-सलाम के बाद उन्हें अपना परिचय दिया और पिछली बार न मिलने की वजह बताई, तो उन्होंने कहा कि हां आप पिछली बार आए थे. मैं मिलना भी चाहता था, लेकिन सरकार ने आपको नहीं आने दिया, तो अब क्या किया जा सकता है? गिलानी साहब से मेरी लगभग बीस मिनट की बातचीत हुई, जिसका रिश्ता इतिहास से, कश्मीर के लोगों की तकलीफ़ (जैसा कि वो समझते हैं) से और अभी के कश्मीर के हालात से था. इन सारी चीज़ों पर वो लगभग बीस मिनट तक हमें समझाते रहे. जब वो समझा रहे थे, मैं उनके चेहरे की तरफ़ देख रहा था, तो मुझे लगा कि इस शख़्स ने सारी ज़िंदगी सिर्फ़ और सिर्फ़ सियासत की है. क्या सियासत के अलावा इनके मन में कभी कुछ और नहीं आया? वे बोल रहे थे और मेरे हाथ नोट्स ले रहे थे, लेकिन मेरा दिमाग़ कह रहा था कि मैं इनसे ये ज़रूर पूछूं कि क्या इनके मन में कोई कसक बाक़ी रह गई है? पहला सवाल मैंने यह पूछा कि इस समय आपकी उम्र क्या है? तो उन्होंने कहा 87 साल और तब मुझे लगा कि इस शख़्स से उन चीज़ों के बारे में ज़रूर पूछना चाहिए, जो शायद लोग नहीं पूछते होंगे. अचानक मैंने गिलानी साहब से पूछा कि सर आपके मन में कहीं कुछ ऐसी कसक तो नहीं रह गई है कि मैं ये करता तो ज्यादा अच्छा रहता, वो करता तो ज्यादा अच्छा रहता, या दूसरे लफ़्ज़ों में, सियासत के अलावा आपके मन में क्या-क्या चल रहा था? जैसे कई लोगों के मन में होता है कि मैं सिनेमा में होता और एक्टिंग करता, तो बहुत अच्छा रहता. किसी के मन में होता है कि मैं बहुत अच्छा म्यूज़ीशियन बनता. मैंने उनसे पूछा कि ऐसी कौन सी चीज़ें उनके मन में रह गई हैं? क्योंकि 87 साल का मतलब एक पूरी दुनिया होती है. तो इसमें ऐसी कौन सी चीज़ पॉलिटिक्स के अलावा रह गई, जो पॉलिटिक्स की वजह से नहीं हो पाई? क्या आपने अपने बच्चों को पूरा वक्त दिया? मैं यह पूछ रहा था और गिलानी साहब इन सवालों से थोड़े से असहज तो नहीं हुए, लेकिन थोड़े ज्यादा मानवीय हो गए और शायद मेरा आख़िरी वाक्य कि क्या आपने अपने बच्चों को पूरा वक्त दिया, उन्हें कुछ असहज कर गया. उन्होंने पहले मेरी तरफ़ देखा फिर अपने बेटे नसीम की तरफ़ देखा, जो वहां बैठे हुए थे. बोले, हां ये चीज़ें मेरे मन में रही तो हैं. आगे उन्होंने कहा कि यह मेरा दूसरा लड़का है. इससे बड़ा नईम है, वो डॉक्टर है और ये भी डॉक्टर हैं, लेकिन फिलॉसिफी में. ये 11 महीने के थे, जब इनकी मां का देहांत हो गया. इनकी मां के देहांत के बाद एक ख़ातून, जो हमारे यहां टीचर के तौर पर रह रही थीं, इन्होंने अपना सारा बचपन बांदीपोरा में उनके साथ रह कर काटा, बल्कि बचपन ही नहीं, ये यूनिवर्सिटी तक बांदीपोरा में ही रहे. जब गिलानी साहब ये कह रहे थे, तब मुझे उनके चेहरे की रंगत और आंखों की रंगत में कुछ कसक दिखाई दी और मैंने उनसे पूछा कि इन्होंने आपके साथ बचपन नहीं गुज़ारा, इसका मतलब आपके मन में एक कसक है कि बच्चों का बचपन आप नहीं देख पाए. ये कैसे बड़े हुए, कैसे चोट खाई, कैसे खेले, कैसे लड़े-झगड़े, कैसे चीज़ें मांगीं.

मैं उनके चेहरे की तरफ़ देख रहा था, तो मुझे लगा कि इस शख़्स ने सारी ज़िंदगी सिर्फ़ और सिर्फ़ सियासत की है. क्या सियासत के अलावा इनके मन में कभी कुछ और नहीं आया? वे बोल रहे थे और मेरे हाथ नोट्स ले रहे थे, लेकिन मेरा दिमाग़ कह रहा था कि मैं इनसे ये ज़रूर पूछूं कि क्या इनके मन में कोई कसक बाक़ी रह गई है?

गिलानी साहब ने एक सेकेंड का पॉज रखा और मेरी ओर देखकर बोले, हां मैं जाता था बांदीपोरा, इन्हें देखता था, मुलाक़ात करता था, लेकिन इस सारी अवधि में ये वहीं रहे. इन्होंने अपना बचपन उन ख़ातून के साथ ही गुज़ारा. मैंने पूछा कि क्या ऐसा इसलिए कि घर में कोई संभालने वाला नहीं था? आप व्यस्त थे बहुत सारी चीज़ों में, शायद सियासत में. गिलानी साहब ने कहा, नहीं-नहीं, उन ख़ातून ने इनको बड़े प्यार से रखा और उन्होंने मुझसे कहा था कि जब ये एमए कर लें, तब आप इनको अपने घर ले जाएं, तब तक मैं इनकी देखभाल करूंगी. फिर मैंने अचानक गिलानी साहब से पूछा कि जब बीच में गैप रहता था, इन लोगों से मिलने के बाद तो आपको ये दोनों बच्चे कितना याद आते थे? गिलानी साहब ने बिना रुके जवाब दिया, याद तो आती थी, हर वक्त याद आती थी. अब मैंने उनसे पूछा कि याद तो आते ही होंगे, आपके बच्चे हैं. लेकिन एक याद होती है कि याद आई और आप चल दिए, वहां पर बच्चों से मिलने के लिए और एक याद होती है कि पता कर लिया कि ख़ैरियत से हैं या नहीं हैं. किस तरह की याद थी आपकी? अब गिलानी साहब गहरी नज़रों से मुझे देख कर बोले, नहीं-नहीं-नहीं, जब याद आती थी, तो चले जाते थे, लेकिन मसरूफ़ियत (व्यस्तता) तो रहती थी. इसलिए बार-बार नहीं जाया जा सकता था, लेकिन जब गहरी याद आती थी, तो मैं चला जाता था. फिर मैंने पूछा कि पॉलिटिक्स में आने के

(शेष पृष्ठ 2 पर)

कश्मीरियों के सपनों का हिन्दुस्तान अभी मरा नहीं है | P-4

भारत इज़राइल समझौता मनमोहक लेकिन ख़तरनाक | P-5

अवाम की मुश्किलें बरकरार | P-6

बेटों को जवान होते नहीं देख पाए

पृष्ठ 1 का शेष

बाद ऐसा हुआ होगा, जब बच्चे बड़े हो गए होंगे, तब आप पॉलिटिक्स की वजह से इन्हें वक्त नहीं दे पाए होंगे. गिलानी साहब ने सर हिलाते हुए कहा, हां बिल्कुल, अक्सर मसरूफ़ियत रहती थी.

अब मुझे लगा कि थोड़ा सवाल बदलना चाहिए, तो मैंने उनसे पूछा कि आपको इसका थोड़ा भी मलाल नहीं है कि इन दोनों बच्चों को जितना वक्त देना चाहिए था, आप नहीं दे पाए? आपको ऐसा नहीं लगता कि जैसे आप सिखाते वैसे ये सीखते, जैसे आप ढालते वैसे ये ढलते? ये वैसे नहीं बन पाए. अगर आपका डायरेक्शन होता, तो शायद कुछ अच्छा बनते. तो गिलानी साहब ने कहा, मैं आपको क्या बताऊं, ये खुद ही पढ़ते रहे और खुद ही देखते रहे कि हमारे अब्बा क्या कर रहे हैं? इसमें उस सिचुएशन का असर है. इन्होंने यह समझा और अब ये कहते हुए कि अब्बू ने एक स्टैंड लिया है, जम्मू-कश्मीर के बारे में या सियासत के बारे में. उसपर ये दृढ़ता से डटे रहे हैं, इसका इनको अहसास है और इनकी ख्वाहिस भी है. इनका मशवरा भी है और ये कहते भी हैं कि जब सारी उम्र आप एक स्टैंड पर रहे हैं, अब आख़िरी दौर में भी आपको उसी के ऊपर दृढ़ता से डटे रहना चाहिए. इन दोनों बच्चों का हमेशा यही मशवरा होता है. मैंने गिलानी साहब से सियासत को लेकर सवाल पूछा कि जब आप इतने दिन पॉलिटिक्स में रहे हैं, तो आपके कई डिसाइड-पल्स (शिष्य) रहे होंगे, जिन्होंने आपके साथ काम किया होगा, साथी होंगे, जिन्होंने कंधे से कंधा मिलाकर काम किया होगा. उनमें से किसके ऊपर आपको नाज़ है और किसके ऊपर गुस्सा है, किसने सही काम नहीं किया? गिलानी साहब ने जवाब दिया, जितने भी साथ रहे, उन्होंने काम किया, अच्छा काम किया. अब मुझे लगा कि मैं गिलानी साहब से पूछूं और मैंने पूछा भी कि ये तो पॉलिटिकल स्टेटमेंट हो गया. ऐसा होता है न कि आदमी बहुत अच्छा है, इसने बहुत अच्छा काम किया, काश ये वाला अच्छा करता, तो उसमें एक मोहब्बत होती और बहुत सारे लोग हैं, जिन्होंने किया, अगर ये कर लेता, तो ये चीज़ नहीं बिगड़ती. ऐसे लोग ज्यादा नहीं होते, पांच-छह-सात साथी, जिनको आपने सिखाया होगा, जिनको अपना हुनर दिया होगा, लड़ने का जज्बा दिया होगा, सपने देखने की ताक़त दी होगी. उस लिहाज़ से कुछ लोगों के बारे में

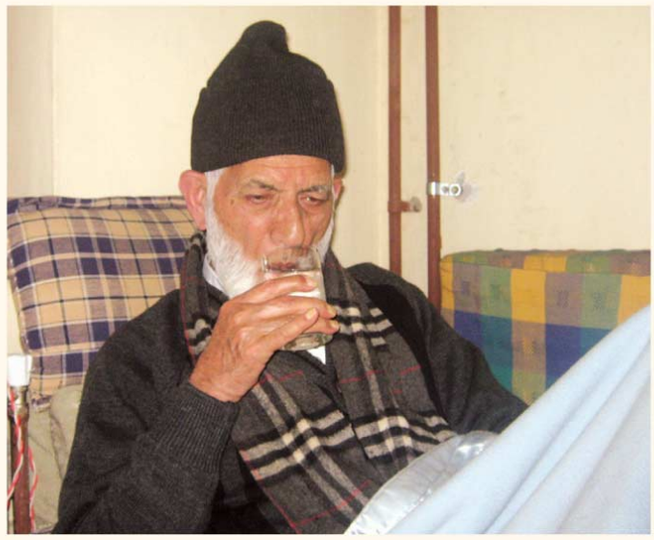

हमें बताया गया है (क़ुरान की एक आयत पढ़कर सुनाते हैं और फिर उसका तर्जुमा करते हैं), अल्लाह-ताआला क़ुरान में फ़रमाता है कि तुम्हे एक दूसरे के साथ मोहब्बत रखनी चाहिए और दूसरों की जो ग़लतियां, कमियां और कोताहियां देखो, तो उनको दरगुज़र (माफ़) करना चाहिए. उनके साथ कोई बदले की भावना नहीं रखनी चाहिए. अल्लाह-ताआला ने फ़रमाया है कि देखो मैंने तुम्हारे पास एक पैगंबर भेजा है और यह बहुत नरम दिल है. अगर यह सख्त दिल होता, तो आप इसके इर्द-गिर्द शहद की मक्खियों की तरह न रहते, लेकिन ये नरम दिल है, इसलिए आप इनके इर्द-गिर्द रहते हैं और फिर इनको मैंने भी कहा है कि आप अपने साथियों को माफ़ किया करें.

बताइए, थोड़ा एनलाइज कीजिए. गिलानी साहब ने बहुत छोटा जवाब दिया, नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल इसकी ज़रूरत नहीं है. मैंने ज़िद की कि आप इसको एव्वाइड क्यों कर रहे हैं? इसपर गिलानी साहब ने कहा कि एव्वाइड इसलिए, क्योंकि हमारा जो दीन है, दीन कहते हैं, निज़ाम को, सिस्टम को, वो हमको इजाज़त नहीं देता कि किसी की कमज़ोरियों को उभारा जाए. मैंने मुस्कुरा कर पूछा, पर कमज़ोरियों पर गुस्सा तो आता ही होगा आपको? गिलानी साहब ने मेरी तरफ़ देखा और शायद थोड़ा समझाने के अंदाज़ में कहा कि नहीं गुस्सा क्यों आता है? हमें बताया गया है (क़ुरान की एक आयत पढ़कर सुनाते हैं और फिर उसका तर्जुमा करते हैं), अल्लाह-ताआला क़ुरान में फ़रमाता है कि तुम्हे एक दूसरे के साथ मोहब्बत रखनी चाहिए और दूसरों की जो ग़लतियां, कमियां और कोताहियां देखो, तो उनको दरगुज़र (माफ़) करना चाहिए. उनके साथ कोई बदले की भावना नहीं रखनी चाहिए. अल्लाह-ताआला ने फ़रमाया है कि देखो मैंने तुम्हारे पास एक पैगंबर भेजा है और यह बहुत नरम दिल है. अगर यह सख्त दिल होता, तो आप इसके इर्द-गिर्द शहद की मक्खियों की तरह न रहते, लेकिन ये नरम दिल है, इसलिए आप इनके इर्द-गिर्द रहते हैं और फिर इनको मैंने भी कहा है कि आप अपने साथियों को माफ़ किया करें. माफ़ी ही नहीं, बल्कि अल्लाह-ताआला से आप इनके लिए मग़फ़िरत की दुआ मांग लिया करें और फिर जब मशवरा करने के बाद आप किसी बात को तय कर लें कि ये बात सही है और इसपर अमल करना चाहिए, तो फिर उसपर अमल करें और अल्लाह पर भरोसा रखें. ज़ाहिरी सहारों पर भरोसा न रखें. अल्लाह पर भरोसा करो, तो वह तुम्हारी मदद करेगा. हमारी यह कोशिश रहती है कि ऐसे हालात के लिए हमें जो तालिम दी गई है, उसपर हम अमल करें. मुझे लगा, मेरे सवालों को गिलानी साहब टाल रहे हैं, तो मैंने उनसे पूछा, अपनी ताक़त और कमज़ोरियों के बारे में बताइए.

गिलानी साहब ने इसका भी बड़ा छोटा जवाब दिया और कहने लगे कि इंसान में कमज़ोरियां होती हैं, ये कोई नई चीज़ नहीं है. क़ुरान में बताया गया है कि हमने इंसान को बहुत कमज़ोर पैदा किया है, इंसान कमज़ोर होता है. मैंने अपनी समझ से गिलानी साहब को थोड़ा कुरेदने की कोशिश की कि आपके अंदर अपनी एक ताक़त है और मुझे लगता है कि आपमें जो लड़ने का माद्दा है, वो शायद आपकी ताक़त है. अंदर से आपको कहीं से ताक़त मिलती है, क्योंकि आदमी सोचता ज़रूर है कि चलो बहुत लड़

(शेष पृष्ठ 3 पर)

चौथी दुनिया
हिंदी का पहला साप्ताहिक अखबार

वर्ष 08 अंक 39
28 नवंबर- 04 दिसंबर 2016

RNI-DELHIN/2009/30467

संपादक
संतोष भारतीय

संपादक समन्वय
डॉ. मनीष कुमार

एडिटर (इंवेस्टिगेशन)
प्रभात रंजन दीन

सहायक संपादक
सरोज कुमार सिंह (बिहार-झारखंड)
सरयू भवन, वेस्ट बोरिंग केनाल रोड,
हरीलाल स्वीट्स के निकट, पटना-800001
फोन: 0612 3211869, 09431421901

मैसर्स अंकुश पब्लिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड के लिए मुद्रक व प्रकाशक रामपाल सिंह भदौरिया द्वारा जागरण प्रकाशन लिमिटेड डी 210-211 सेक्टर 63 नोएडा उत्तर प्रदेश से मुद्रित एवं के- 2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001 से प्रकाशित

संपादकीय कार्यालय
के-2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001
कैंप कार्यालय एफ-2, सेक्टर -11, नोएडा, गौतमबुद्ध नगर उत्तर प्रदेश-201301

फोन न.
संपादकीय 0120-6451999, 6450888
विज्ञापन व प्रसार 022-65500786, +91-8451050786, +91-9266627379
फैक्स न. 0120-2544378

पृष्ठ-16++ (बिहार-झारखंड, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड)

चौथी दुनिया में छपे सभी लेख अथवा सामग्री पर चौथी दुनिया का कॉपीराइट है. बिना अनुमति के किसी लेख अथवा सामग्री के पुन: प्रकाशन पर क़ानूनी कार्रवाई की जाएगी.

समस्त क़ानूनी विवादों का क्षेत्राधिकार दिल्ली न्यायालयों के अधीन होगा.

दिल्ली का बाबू

दिलीप चेरियन

मोदी क्या चाहते हैं

अगले वित्त वर्ष से बाबू अपनी परफॉरमेंस रिपोर्ट ऑनलाइन फाइल कर सकते हैं. कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) ने सेवा नियमों में बदलाव कर के इसकी अनुमति दी है. यह अनुमति प्रधानमंत्री के उस निर्देश के बाद दी गई है, जिसमें उन्होंने जल्दी पदोन्नति और अधिक से अधिक पारदर्शिता की बात की थी.

यहां यह भी निर्णय लिया गया है कि यदि अधिकारियों का वार्षिक निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट (एपीएआर) निर्धारण वर्ष के 31 दिसम्बर तक तैयार नहीं होता है, तो उनका मूल्यांकन उनके एक साल के समग्र रिकॉर्ड और आत्म मूल्यांकन के आधार पर किया जा सकता है.

इस संबंध में विभाग ने कैडर को नियंत्रित करने वाले सभी अधिकारियों को पत्र लिखा है, जिसमें गृह मंत्रालय (भारतीय पुलिस सेवा के लिए), पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन (भारतीय वन सेवा के लिए), सार्वजनिक उपक्रम विभाग (केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए) और वित्तीय सेवा विभाग (सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, वित्तीय और बीमा कंपनियों के लिए) शामिल हैं.

स्थापना अधिकारी राजीव कुमार द्वारा लिखित पत्र में ये उम्मीद जाहिर की गई है कि पिछले निर्देशों का पर्याप्त अनुपालन किया गया होगा और विभाग वित्तिय वर्ष 2017-18 से अनिवार्य ऑनलाइन फाइलिंग करने की स्थिति में होंगे. इसमें ये भी कहा गया है कि सरकार अब सभी 36 केंद्रीय सिविल सेवा के अधिकारियों के लिए ऑनलाइन फाइलिंग की सुविधा सुनिश्चित करेगी.■

असामान्य पोस्टिंग

भले ही यह अजीब लगे लेकिन ज़ाहिरी तौर पर कानून संगत है. भारतीय वन सेवा (आईएफओएस) अधिकारी सौरभ कुमार को

भारत के मास्को के दूतावास में काउंसलर नियुक्त किया गया है. उनकी नियुक्ति तीन साल के लिए हुई है. वह एक अन्य गैर-भारतीय विदेश सेवा अधिकारी पी मोहंती, जो इंडियन आर्डिनेंस फैक्ट्रीज सर्विस से संबद्ध थे, की जगह लेंगे.

सूत्रों का कहना है कि नियमों के मुताबिक किसी भी ग्रुप-ए सेवा के अधिकारी को भारतीय विदेश मिशनों में नियुक्त किया जा सकता है. ऐसा देश में आईएफएस अधिकारियों की भारी कमी के कारण होता है. भारत में 600 करियर राजनयिक हैं, जो विदेश मंत्रालय में हैं और 162 भारत के विदेश मिशनों में सेवारत हैं. वर्त्तमान में भारतीय विदेश सेवा में 8 से 15 अधिकारियों को लिया जाता है.

हालांकि, इसका एक और कारण भी है. कई भारतीय मिशनों मे कूटनीति से इतर कई अन्य विशेषज्ञता की जरूरत होती है. उदाहरण के लिए, आईएएस या अन्य ग्रुप-ए सेवा के अधिकारियों, जिनका वित्त मंत्रालय या वाणिज्य मंत्रालय में काम करने अनुभव होता है, को भारतीय विदेश मिशनों में व्यापार, अर्थव्यवस्था और वाणिज्य से संबंधित कार्यों के लिए नियुक्त किया जाता है. कुमार की नियुक्ति मास्को में होगी जो अभी रक्षा मंत्रालय में उप सचिव के पद पर काम कर रहे हैं.

वो एकमात्र ऐसे भारतीय वन सेवा के अधिकारी हैं, जिन्हें विदेशी पोस्टिंग मिली है. 1984 बैच के आईएफओएस अधिकारी संजय कुमार, क्लाइमेट पार्लियामेंट, लंदन में एक कार्यकारी निदेशक के रूप में कार्यरत हैं.■

बाबू बनाम बाबू

राजनीतिक झगड़ों से भरे केरल में वहां की नौकरशाही के बीच झगड़ा शुरू हो गया है. राज्य की भ्रष्टाचार निरोधक एजेंसी पर शीर्ष के बाबुओं पर कथित भ्रष्टाचार का निशाना बनाने का आरोप लगाया गया है. इसने मुख्यमंत्री पिनारयी विजयन को साफ़ तौर पर एक मुश्किल स्थिति में डाल दिया है. हालांकि सतर्कता और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (वीएसीबी) ने अदालत के आदेश पालन किया है, लेकिन जिन अधिकारियों पर छापे मारे गए हैं वे अतिरिक्त मुख्य सचिव टॉम जोस और के.के. अब्राहम हैं. पुलिस महानिदेशक (राज्य अपराध रिकार्ड ब्यूरो) एन शंकर रेड्डी को भी सतर्कता विभाग की जांच का सामना करना पड़ रहा है. हालांकि इसमें एक नया मोड़ यह है कि खुद सतर्कता निदेशक जैकब थॉमस पर भी पोर्ट विभाग और केरल परिवहन विकास वित्त निगम की पहले की नियुक्तियों के दौरान अनियमितताओं और सेवा नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाया गया है. आरोपी अधिकारियों ने मुख्यमंत्री से शिकायत की है कि जिस तरह से वीएसीबी ने जांच की, उससे जैकब थॉमस के गलत उद्देश्यों का पता चलता है.

मुख्यमंत्री के लिए यह एक दुविधा का विषय है, क्योंकि सतर्कता विभाग में थॉमस की नियुक्ति मुख्यमंत्री का फैसला था. थॉमस अपनी प्रतिष्ठा के अनुरूप हर पार्टी के शक्तिशाली राजनेताओं के खिलाफ काम कर रहे हैं.■

बेटों को जवान होते नहीं देख पाए

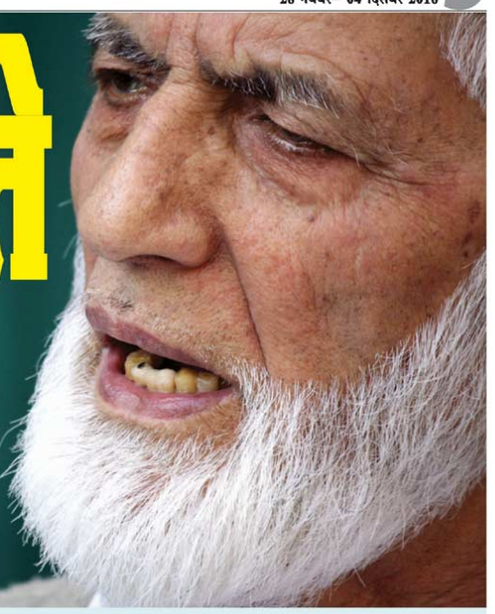

पृष्ठ 2 का शेष

लिए, थोड़ा आराम करें, थोड़ा दुनिया में घूमें, बच्चों के साथ रहें, पर वो आप नहीं करते हैं. आप लगातार सोचते रहते हैं और लड़ते हैं. क्या आपको गुस्सा ज्यादा आता है? कमज़ोरी में एक गुस्सा भी है. फिर गिलानी साहब ने मुझे घूमा दिया. बहुत संक्षेप में बोले, मुझे बहुत कम गुस्सा आता है. हमेशा यह कोशिश रहती है कि दरगुज़र (माफ़) किया जाए. मैंने उन्हें और कुरेदा, अच्छा बताइए गुस्सा आता है, तो आप क्या करते हैं? मतलब अल्लाह को याद करते हैं या पानी पीते हैं या कुछ और करने लगते हैं? गिलानी साहब ने जवाब दिया, अल्लाह-ताआला को ही याद करते हैं कि हम पर रहम कर.

मैंने फिर बात बदली. कौन सा मौसम अच्छा लगता है? गिलानी साहब बोले, यहां कश्मीर में हमेशा मौसम अच्छा रहता है. मेरा अगला सवाल था, आपका पसंदीदा मौसम कौन सा है? जाड़ा पसंद है, गर्मी पसंद है या बरसात? गिलानी साहब का फिर वही छोटा सा जवाब, सर्दियों में थोड़ी तकलीफ़ होती है, चेस्ट ख़राब हो जाता है. मैंने इस पर पूछा, ये तो अभी होता है, पहले तो नहीं होता होगा? उन्होंने जवाब दिया नहीं, पहले ऐसा नहीं होता था, लेकिन कुछ समय से (1997 से) मुझे पेसमेकर लगा हुआ है. मैंने गिलानी साहब से पूछा कि चांदनी रात कितनी पसंद है, चांद, चांदनी रात, रौशनी? गिलानी साहब का जवाब था, अल्लाह-ताआला ने जो हुस्न दिया है, इंसानों को या इस सरज़मीं को, वो तो हमेशा ही पसंद आता है. वो नेमत (उपहार) है, अल्लाह-ताआला की तरफ़ से और उसका फ़ायदा भी उठाना चाहिए. अब शायद मैंने गिलानी साहब के मन की बात पूछी.

क्या आपको शायरी बहुत पसंद है? आपने कई शेर अभी कहे इस बातचीत के दौरान अपनी बात कहने के लिए और दूसरे इक़बाल क्यों आपको इतने पसंद हैं? क्योंकि दोनों बार आपने इक़बाल साहब के शेर इस्तेमाल किए. गिलानी साहब ने कहा, यहां मैंने लिखा भी है (किताबों की तरफ़ इशारा करते हुए). दो किताबें लिखी हैं और तीसरी लिख रहा हूं. इक़बाल इसलिए पसंद हैं, क्योंकि इक़बाल ने इस्लाम की रूह को समझा है. मैं बग़ैर किसी लाग-लपेट, बिना किसी बनावट के आपसे कहूंगा कि जिस तरह इक़बाल ने इस्लाम की रूह को समझा, बड़े-बड़े आलिमों (ज्ञानीयों) ने उस सच्चे इस्लाम की रूह को नहीं समझा है. इसलिए हमें इक़बाल पसंद हैं. जिस्म को समझना बड़ा आसान है, लेकिन किसी चीज़ की रूह को समझना और फिर उसे अपने कलाम (कविता) में दर्शाना, उसको पेश करना, ये बहुत बड़ा कारनामा है, बहुत बड़ा हुनर है. तो ज़ाहिर है मुझे पूछना था और मैंने पूछा भी कि ऐसे और कितने शायर हैं, राइटर हैं, जिन्होंने आपके ऊपर अपनी छाप डाली हो, असर डाला हो. अब गिलानी साहब ने मुस्कुराते हुए, समझाते हुए कहा, एक तो इक़बाल हैं, दूसरे सैयद मौलाना मौदूदी (र). उन्होंने भी क़ुरान और दीन की रूह को समझा है और समझाया है, बड़े आसान तरीक़े से. उन्होंने समझाया है कि इस्लाम क्यों है, इस्लाम की ख़ूबियां क्या हैं, इस्लाम के मुक़ाबले में जितने भी इज्म हैं, निज़ाम हैं, उनमें क्या-क्या कमज़ोरियां हैं. कम्यूनिज्म में, सोशलिज्म में, कैपिटलिज्म में, सेक्युलरिज्म में, ये जो दूसरे इज्म हैं, उनमें क्या-क्या कमज़ोरियां हैं और उनके मुक़ाबले में इस्लाम में क्या-क्या ख़ूबियां हैं. इन्होंने बड़ी तफ्सील के साथ ये समझाया है, इसलिए उनके साथ भी बहुत मोहब्बत है. इक़बाल के साथ भी बहुत मोहब्बत है. मेरे एक मुरब्बीस (संरक्षक) रहे हैं मौलाना मौसूदी, वो अब हमारे बीच नहीं हैं, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे. हालांकि उनके साथ सियासी मतभेद थे, लेकिन चार साल उन्होंने मेरी तरबीयत की है (यानि मुझे शिक्षा दी है). चार साल मैं उनके साथ रहा हूं. उनकी ख़ूबियां, उनका कैरेक्टर और उनकी सादगी ने मुझे बहुत प्रभावित किया. अब मैंने सवाल पूछा, हालांकि वो थोड़े अलग थे आपसे.

गिलानी साहब ने जवाब दिया. हां, वो शेख़ अब्दुल्ला के प्रभाव में थे. बस यही एक उनकी कमज़ोरी थी, बाक़ी उनकी ख़ूबियां बहुत ज्यादा हैं. चार साल के दौरान, चार साल की अवधि तो बड़ी अवधि है न? मैं आपसे कहूंगा कि उस चार साल में मैंने कभी नहीं देखा कि उन्होंने किसी की ग़ीबत (पीठ पीछे शिकायत) की हो. हालांकि उनके बहुत दुश्मन थे. उनको मालूम भी था कि लोग उन्हें 'सूतगुजरु' भी कहते हैं. लेकिन कभी भी उन्होंने किसी के बारे में कोई ग़ीबत नहीं की कि फलां ऐसा है या फलां ऐसा है. चार साल में मैंने कभी नहीं देखा और सादगी तो उनमें बहुत ज्यादा थी.

मैं गिलानी साहब को देख रहा था और मुझे लगा कि उनसे पूछूं कि श्रीनगर के अलावा उन्हें कौन सी जगह पसंद है और मैं ये अपेक्षा कर रहा था कि वो स्विट्जरलैंड का या जर्मनी का या लंदन का नाम लेंगे. इसलिए मैंने सवाल को थोड़ा और साफ़ किया कि दुनिया में कहीं भी, जहां आप घूमे हैं, श्रीनगर तो आपको सबसे अधिक पसंद है ही, ये जन्नत है. ज़ाहिर है ये जन्नत है, ये बात अलग है कि आज ये जन्नत नहीं रही. यहां की सरज़मीं के अलावा और कौन सी जगह है. मान लीजिए, अगर आपको च्वॉइस मिलती कि श्रीनगर के अलावा कहीं और रहना है, तो कहां रहते? गिलानी साहब इस पूरी बातचीत में पहली बार हंसे और हंसते हुए बोले कि केरल में. अब मुझे आश्चर्य हुआ. मैंने पूछा केरल में कैसे? गिलानी साहब ने कहा कि मैं वहां दो बार गया हूं, बहुत अच्छे लोग हैं वहां के, मौसम भी अच्छा है, बहुत ज्यादा सादगी है केरल में. जब भी केरल के लोग यहां आते हैं, हमें बहुत ख़ुशी होती है. बड़े अच्छे लोग हैं, सादा लोग हैं, कम्युनल नहीं हैं. अब तो बीजेपी वाले वहां जा रहे हैं, वहां भी कम्युनलिज्म का बीज बोया जा रहा है. लेकिन वहां के लोग बड़े अच्छे हैं. मैंने अचानक पूछ लिया कि महबूबा मुफ्ती से आपकी मुलाक़ात हुई इधर हाल-फिलहाल में? तो उन्होंने जवाब दिया हां, जब मेरी बेटी गुजरी थी, तो उस वक्त ताज़ियत के लिए, मातमपुरसी के लिए आई थीं. अब मैंने पूछा कि इसके अलावा महबूबा मुफ्ती को समझने का मौक़ा नहीं मिला कि कैसी लड़की हैं, कैसा दिमाग़ है उनका? इसका जवाब थोड़ा लंबा दिया गिलानी साहब ने. उन्होंने कहा कि अंदाज़ा था और मैंने लिखा भी है किताबों में कि ख़ातून जो होती हैं, उनका दिल नर्म होता है, किसी का ग़म और दुःख देखती हैं, तो उनका दिल बहुत जल्दी पसीज जाता है. लेकिन महबूबा के बारे में ये चीज़ ग़लत साबित हुई है. यहां की ज़मीन पर जितना ख़ून बहा है और बिना किसी वजह के बुरहान शहीद हुआ, उसके जनाज़े में दो लाख लोगों ने शिरकत की और 40 बार उसकी नमाज़-ए-जनाज़ा पढ़ी गई, इस्लामाबाद में, साउथ में, सोपियां में, कारगील में, कहलगांव में. पुलवामा से और अनंतनाग से भी लोग वहां जाने लगे. उनके पास कोई हथियार नहीं था, जैसे कि मैंने कहा, लेकिन फौज ने, पुलिस ने लोगों को वहां जाने नहीं दिया. अगर वहां वे जाते, तो क्या फ़र्क़ पड़ता? दो लाख लोग तो पहले से ही वहां मौजूद थे. कोई फ़र्क़ नहीं पड़ता. लेकिन जाते वक्त उनपर गोलियां चलाई गईं. महबूबा को देखना चाहिए था कि वे लोग वहां जनाज़े में शिरकत के लिए जाना चाहते थे, तो उनपर गोलियां चलाने का क्या जवाज़ (औचित्य) था? उनका कत्ल करने का क्या जवाज़ था? पैलेट गनों से उनको बिनाई (आंख की रौशनी) से महरूम करने का क्या जवाज़ था? मैं चाहता था, मेरी ये तमन्ना थी, मेरी ख्वाहिश थी और मेरा ये जज्बा था कि उनको उसी वक्त इस्तीफ़ा देना चाहिए था. ये बिना वजह की क़त्ल-ओ-ग़ारतगरी (ख़ून-ख़राबा) देखना, इसके लिए जवाज़ नहीं बनता था उनके पास कि वो सत्ता की कुर्सी पर विराजमान रहें. नहीं, उन्हें इस्तीफ़ा देना ही चाहिए था. वो ख़ातून नहीं रहीं, बल्कि समझ लीजिए बेहिस (असंवेदनशील) हो गई हैं वो, कोई दिल नहीं है उनके पास. तो मैंने पूछा कि क्या वो बिना दिल की चीफ मिनिस्टर हैं? गिलानी साहब का साफ़ जवाब था कि हां, बिना दिल की, बिल्कुल बिना दिल की. अब मैंने उनसे राजनीतिक सवाल पूछा कि आज की सरकार के लिए आपकी क्या नसीहत है? आज सियासत को, ज़िंदगी को, नफ़रत को, मुहब्बत को देखने के बाद अगर आपको कोई चार या पांच चीज़ें आज की सरकार से कहनी हो, तो क्या कहेंगे? सरकार को क्या करना चाहिए? गिलानी साहब ने बहुत साफ़गोई से कहा, यहां जो सरकार है, यहां की जो हिंद-नवाज़ (प्रो-इंडिया) पार्टियां हैं, उनके बारे में हमारा ये आइडिया है और हमारी ये ज़रूरत भी है और चाहत भी है कि इन्हें इस ख़ून-ख़राबे को देखकर अपने पदों से त्यागपत्र दे देना चाहिए और ख़ासतौर से इस हुकूमत को त्यागपत्र दे देना चाहिए. इसके बग़ैर इनका कोई इलाज नहीं है और इनके पास ऐसा कोई तर्क नहीं है, इस कुर्सी पर बैठने का. यानी पुलिस इनके पास है, इनके कंट्रोल में है, सीआरपीएफ इनके कंट्रोल में है, हर मुख्यमंत्री यूनिफाइड कमांड का चेयरमैन होता है, तो इनमें ये ताक़त क्यों नहीं रही कि उनको रोकें कि तुम्हारे हाथों से क़त्ल हो रहा है, तुम्हारे हाथों से ये ख़ून बह रहा है, तुम्हारे हाथों से ये ज़ुल्म हो रहा है. तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? मैं तो आपके साथ नहीं रहूंगा. चाहे फ़ारूक़ अब्दुल्ला हों, उमर अब्दुल्ला हों, तारिगामी साहब हों या कोई और हो, इन सबको कर्रा साहब ने जैसा नमूना दिखाया, इन्हें उस पर अमल करना चाहिए. इस मामले में तारिक़ कर्रा साहब ने जो किरदार दिखाया वो क़ाबिल-ए-तारीफ़ है. उन्होंने कहा कि हमारे जवानों को क़त्ल किया जा रहा है, मैं इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं. उन्होंने पार्लियामेंट के मेम्बरशिप से इस्तीफ़ा दे दिया, पार्टी से भी इस्तीफ़ा दे दिया. उन्होंने एक अच्छा कैरेक्टर दिखाया सारे लीडर्स को. लेकिन नेशनल कांफ्रेंस या कांग्रेस के ये लोग, जो सत्ता के पीछे दौड़ रहे हैं, इनको इंसानियत के साथ कोई मोहब्बत नहीं है. या अपने क़ौम पर जो ज़ुल्म हो रहा है, उसका इनको कोई एहसास नहीं है.

मैंने उनसे कहा कि ईद के दिन मैं और मेरे दो साथी कर्रा साहब के साथ थे. शाम को उन्होंने बुलाया था. हमलोग डेढ़ घंटे तक वहां थे, इशारा तो इन्होंने उसी समय ही दे दिया था कि मैं बहुत ज्यादा दूर पीडीपी के साथ नहीं चलूंगा. मैं कुछ सोच रहा हूं, तो उस समय लगा तो था कि शायद वो साथ नहीं रहेंगे, पर इस्तीफ़ा दे देंगे, इसका अंदाज़ा नहीं था. गिलानी साहब ने कहा कि हां उन्होंने बहुत अच्छा किया. लेकिन अब उनका टेस्ट ये है कि आइंदा उन्हें अब कभी चुनाव में हिस्सा नहीं लेना चाहिए. ये उनके लिए टेस्ट है. क्योंकि एक चीज़ तो अब उन्होंने समझी, जिसपर उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया. इतना जो ज़ुल्म हो रहा है, आइंदा भी जारी रहेगा, शायद उस वक्त तक, जब तक हम गुलाम हैं. हिंदुस्तान के फौजी तसल्लुत (वर्चस्व) में हैं, ज़ुल्म चलता रहेगा. इसलिए आइंदा उन्हें कभी चुनाव में हिस्सा नहीं लेना चाहिए. मैंने बातचीत को यहीं बंद करना ठीक समझा, क्योंकि मैं उनसे राजनीति पर बात कर चुका था.

मैंने घड़ी देखी. कुल मिलाकर डेढ़ घंटे बीत चुके थे. इसके बाद गिलानी साहब उठे और उन्होंने मेरे सर के ऊपर हाथ रखा. शायद इस डेढ़ घंटे के दौरान बातचीत से जो भावनाएं प्रकट हुईं, उसने उन्हें अपना राजनीतिक पक्ष किनारे रखने के लिए प्रेरित किया और जब मैं बातचीत करके उठ रहा था, तो उन्होंने फिर चाय पीने का हुक्म दिया. वहां बैठे हुए उनके साथी और खुद उनके बेटे नसीम का भी ये कहना था कि इतने सालों में किसी ने भी गिलानी साहब से राजनीति से अलग हटकर इस तरह के सवाल नहीं पूछे या शायद पूछने की हिम्मत नहीं की. आपने पूछा और जिस तरह से गिलानी साहब ने जवाब दिया उसके ऊपर भी हमें बड़ी हैरानी है. लेकिन मैं गिलानी साहब के अंदर के उस इंसान को तलाश पाया, जो अपनी ज़िंदगी में अपने बच्चों के बचपन को न देख पाने, बच्चों को बड़ा होते हुए न देख पाने, बच्चों की शरारतों को न देख पाने की कसक लिए, लेकिन उस कसक को अपने दिल में ख़ामोशी के साथ बंद किए अपने मक़सद के लिए लड़ने की तैयारी करता रहा.■

editor@chauthiduniya.com

कश्मीरियों के सपनों का हिन्दुस्तान अभी मरा नहीं है

यूसुफ़ तारीगामी

आज कश्मीर में जो ये उबाल रहा, इसका कारण यही है कि बहुत सारे वादे किए गए थे और उन वादों को पूरा नहीं किया गया. आर्टिकल 370 को भी कमज़ोर किया गया, यानी कश्मीर को जो एक स्वायत्त दर्जा मिला हुआ था, न सिर्फ़ उसे कमज़ोर किया गया, बल्कि अपने बहुत ही विश्वसनीय इंस्ट्रूमेंट जगमोहन द्वारा आर्टिकल 249 लागू किया गया. लिहाज़ा बाक़ी के राज्यों को जो अधिकार हैं, विधायी अधिकार हैं उनके मुक़ाबले में भी जम्मू-कश्मीर के अधिकार को कम किया गया.

यूसुफ़ तारीगामी

जहां तक कश्मीर समस्या का संबंध है, तो दो बातें हमें ज़ेहन में रखनी होंगी. एक, कश्मीरी अवाम अपनी पहचान को लेकर बहुत ही संवेदनशील रही है. अगर इस सवाल को अलग भी कर दिया जाए कि 1947 से पहले डोगरा शासन के ख़िलाफ़ एक कश्मीरी आन्दोलन था, तो भी इतिहास की घटनाएं बताती हैं कि उससे पहले मुग़लों के ख़िलाफ़ संघर्ष था, पठानों के ख़िलाफ़ संघर्ष था और सिखों के शासन के ख़िलाफ़ संघर्ष था. कहने का अर्थ ये है कि कश्मीरी अवाम पहले से ही अपनी बहुसंस्कृतिवादी (प्लूरल) पहचान के बारे में काफ़ी संवेदनशील रही है. यही वजह है कि जो बंटवारा हुआ (हमारी नज़र में जब बटवारे का ट्रॉमा (आघात) हुआ) वो अभी भी हमारी मानसिकता का, पूरे उपमहाद्वीप की मानसिकता का एक हिस्सा बना हुआ है. अभी भी दोनों नेशन-स्टेट्स ने उस अघात पर क़ाबू नहीं पाया है. कश्मीर उसी आघात का एक हिस्सा है.

यही वजह है कि बंटवारे के बाद जब कश्मीर की अवाम के सामने यह सवाल आया कि उधर (पाकिस्तान) जाना है या इधर (भारत में) रहना है, तो यहां की उस वक्त की लोकप्रिय नेतृत्व ने ये फ़ैसला किया कि मज़हब राष्ट्रीयता की बुनियाद नहीं बन सकता. इसलिए कश्मीर छोड़ो आन्दोलन और भारत छोड़ो आन्दोलन के बीच मूल्यों (वैल्यूज़) का और दिशा (डायरेक्शन) का एक ढांचा था, जिसके अंदर रहकर एक रिश्ता बन सकता था. लिहाज़ा एक अतिरिक्त रिश्ता बना, जिसे हम विलय की संधि (इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन) के नाम से जानते हैं. आज लोग ये भूल जाते हैं कि ये सिर्फ़ क़ानूनी सवाल नहीं है कि विलय की संधि, जो क़ानूनी फ्रेम का एक हिस्सा है, की क़ानूनी हैसियत क्या है. लेकिन इसके अलावा इस रिश्ते के लिए एक नैतिक बंधन है और एक नैतिक समर्थन है, बेशक कुछ शर्तों के साथ. ये शर्तें क्या थीं? शर्तें थीं कि दिल्ली के साथ, हिंदुस्तान के साथ एक रिश्ता बने और उस रिश्ते से हमारी पहचान सुरक्षित रहे, बहुसंस्कृतिवादी पहचान सुरक्षित रहे. इसलिए भारतीय संविधान में आर्टिकल 370 वजूद में आया. भारत की संविधान सभा और कश्मीर की संविधान सभा दोनों इस रिश्ते की बुनियाद आर्टिकल 370 पर रखने को राज़ी हुए.

आर्टिकल 370 का मतलब है कि जम्मू-कश्मीर की एक स्वायत्त स्थिति रहे. यहां साझी संप्रभुता हो (जिसको आज लोग भूल जाते हैं), यानी कई मामलात में पूरी-पूरी स्वायत्तता रहे, जम्मू-कश्मीर की अवाम के लिए रेसिड्अल पावर्स बनी रहे और साथ-ही-साथ कई मामलात, ख़ासतौर पर तीन मामलों में भारत सरकार का अधिकार बना रहे. ये रिश्ता बना और उस रिश्ते को ध्यान में रखते हुए बाद में जो एकतरफ़ा बदलाव आये, उसका नतीजा ये भी था कि जो नेतृत्व एक पुल की हैसियत से सामने आई, उस पुल को यहां के लोकप्रिय नेता शेख़ अब्दुल्ला को मनमाने ढंग से गिरफ्तार करके, उनकी सरकार को बर्ख़ास्त करके और एक कठपुतली सरकार को सत्ता में बिठा कर लगभग नष्ट कर दिया गया. मेरे हिसाब से उस रिश्ते पर ये सबसे बड़ी चोट थी. भारत और कश्मीर के बीच जो नैतिक बंधन था, उसको ये एक ज़बरदस्त धक्का था, जो आज तक भी संभल न सका, जो बढ़ता ही गया. उसके बाद जो भी हुआ, वो इसी बुनियाद पर हुआ. इसमें दो बातें रहीं. पहली, भारत सरकार की तरफ़ से एक अधिकतमवादी (मैक्जिमलिस्ट) पोज़िशन रही और दूसरी जो सेक्युलर ढांचा था, उसमें भी बहुसंख्यकवाद की एक शक्ल मौजूद रही. इसका नतीजा ये हुआ कि उनके लिए ये बर्दाश्त से बाहर था कि एक मुस्लिम बहुल राज्य को एक स्वायत्त स्थिति मिले. इसको समझने की ज़रूरत है.

आज भी कश्मीर में जो ये उबाल रहा, इसका कारण यही है कि बहुत सारे वादे किए गए थे और उन वादों को पूरा नहीं किया गया. आर्टिकल 370 को भी कमज़ोर किया गया, यानी कश्मीर को जो एक स्वायत्त दर्जा मिला हुआ था, न सिर्फ़ उसे कमज़ोर किया गया, बल्कि अपने बहुत ही विश्वसनीय इंस्ट्रूमेंट जगमोहन साहब को आर्टिकल 249 लागू किया गया. लिहाज़ा बाक़ी के राज्यों को जो अधिकार हैं, विधायी अधिकार हैं, उनके मुक़ाबले में भी जम्मू-कश्मीर के अधिकार को कम किया गया. अब राज्यसभा एक रिजॉल्यूशन के ज़रिये कोई भी अमेंडमेंट ला सकती है. अब कॉन्स्टीट्यूशन में अमेंडमेंट ज़रूरी नहीं है, बल्कि राज्यसभा और लोकसभा इकट्ठे मिलकर किसी रिजॉल्यूशन को पास कर सकते हैं (आर्टिकल 249). यानी कश्मीरियों में जो एक रिश्ते की बुनियाद बनी थी, उसको बुरी तरह से कमज़ोर किया गया, जिसका नतीजा ये है कि लोगों में शुरू से ही बेचैनी रही, अनिश्चितता रही. अनिश्चितता का इलाज फ्राड्इसेस मैनेजमेंट के फॉर्मूले से किया गया. यह फॉर्मूला था, कभी एक को लाओ, कभी दूसरे को लाओ, कभी किसी को गिरफ्तार करो, कभी किसी को छोड़ दो. इसका नतीजा ये है कि कश्मीर के इतिहास में एक लम्बे समय तक जनता के लिए लोकतंत्र नहीं आने दिया गया है.

इसका अंदाज़ा इससे लगाया जा सकता है कि जब शेख़ साहब और इंदिरा जी के दरम्यान 1974-75 में समझौता हुआ, तो 1953 के बाद 1977 में पहला ऐसा चुनाव हुआ, जिसे लोकप्रिय चुनाव कहा जाता है. उस उस वक़्त दिल्ली में जनता पार्टी की सरकार थी और ये जो बहुत सारे अलगाववादी प्लेटफॉर्म हैं, वे एक बार चुनाव में आये. उन्होंने जनता पार्टी के इर्द-गिर्द चुनाव लड़ा. मरहूम अब्दुल ग़नी लोन साहब जनता पार्टी की पहली पंक्ति के लीडर थे. मरहूम मीरवाइज़ उनके सपोर्टर थे, यहां तक कि जमात-ए-इस्लामी भी उनके साथ थी. लेकिन उनके पास लोकप्रिय जनादेश नहीं था, उनके पास जन समर्थन नहीं था. शेख़ साहब ने चुनाव जीता और उसके बाद जब उनका स्वर्गवास हो गया, तो उनके पुत्र फ़ारूक़ अब्दुल्ला साहब आये. बड़ा जनादेश था. धांधली रहित चुनाव हुए थे. उस समय इंदिरा जी प्रधानमंत्री थीं और जगमोहन साहब गवर्नर थे. बीके नेहरू साहब (गवर्नर) ख़ुद कहते हैं कि उन्हें आदेश मिला था कि फ़ारूक़ अब्दुल्ला की सरकार को बर्ख़ास्त किया जाए, लेकिन उन्होंने आदेश को माना नहीं. फिर इंस्ट्रूमेंट ऑफ गवर्नर इस्तेमाल किया जगमोहन साहब को और दलबदल की व्यवस्था कर एक चुनी हुई सरकार को दिन के उजाले में ही बर्ख़ास्त कर दिया गया. ख्याल रहे कि इस वक्त फिलहाल यहां कर्फ्यू का जो सिलसिला रहा, उस वक्त भी सबसे लम्बा कर्फ्यू रहा था. उस वक्त भी लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया था. श्रीनगर में ग़ुलाम मुहम्मद शाह के शासनकाल को कर्फ्यू राज माना जाता था.

फ़ारूख़ अब्दुल्ला

महबूबा मुफ्ती

जगमोहन

इंदिरा गांधी

ही विश्वसनीय इंस्ट्रूमेंट जगमोहन द्वारा आर्टिकल 249 लागू किया गया. लिहाज़ा बाक़ी के राज्यों को जो अधिकार हैं, विधायी अधिकार हैं, उनके मुक़ाबले में भी जम्मू-कश्मीर के अधिकार को कम किया गया. अब राज्यसभा एक रिजॉल्यूशन के ज़रिये कोई भी अमेंडमेंट ला सकती है. अब कॉन्स्टीट्यूशन में अमेंडमेंट ज़रूरी नहीं है, बल्कि राज्यसभा और लोकसभा इकट्ठे मिलकर किसी रिजॉल्यूशन को पास कर सकते हैं (आर्टिकल 249). यानी कश्मीरियों में जो एक रिश्ते की बुनियाद बनी थी, उसको बुरी तरह से कमज़ोर किया गया, जिसका नतीजा ये है कि लोगों में शुरू से ही बेचैनी रही, अनिश्चितता रही. अनिश्चितता का इलाज फ्राड्इसेस मैनेजमेंट के फॉर्मूले से किया गया. यह फॉर्मूला था, कभी एक को लाओ, कभी दूसरे को लाओ, कभी किसी को गिरफ्तार करो, कभी किसी को छोड़ दो. इसका नतीजा ये है कि कश्मीर के इतिहास में एक लम्बे समय तक जनता के लिए लोकतंत्र नहीं आने दिया गया है.

कहने का मतलब यह है कि ये जो वादाख़िलाफ़ी का इतिहास है, ये जो लोकतंत्र से वंचित रखने का इतिहास है. इनकी लम्बी-लम्बी दास्तानें हैं. भले ही दिल्ली में किसी की भी सरकार रही, बार-बार कोशिश यही रही कि कश्मीर के जो भी संवैधानिक अधिकार हैं, उन्हें कम किया जाए और नागरिकों को संविधान के तहत जो भी अधिकार मिलते हैं, उनके साथ भी खिलवाड़ किया जाए. ये एक लम्बी दास्तान है. इसमें नागरिक स्वतंत्रता का सवाल है, अंधाधुंध गिरफ्तारियों का सवाल है, लाठियों का सवाल है, फ़ौज का सवाल और बाकी चीज़ों का सवाल है.

फिर 1990 के दशक में आपने देख लिया कि इस समस्या ने एक नया आयाम अख्तियार कर लिया, पूर्ण रूप से उग्रवाद (इन्सर्जेन्सी) का रूप धारण कर लिया. बेशक पाकिस्तान इसका हिस्सा था. इस बात का मुझे यकीन है कि पाकिस्तान ने हमेशा ईमानदारी के साथ काम नहीं किया है. साथ ही ये भी एक सच्चाई है कि बंटवारे के बाद से अब तक पाकिस्तान और भारत ने कई जंगें लड़ीं और कई समझौते किये. ये भी एक सच्चाई है कि अगर आप एलओसी को देखेंगे तो शायद देश विभाजन के बाद से अब तक बॉर्डर नहीं है. एक हिस्सा है, जहां अब भी स्थाई बॉर्डर नहीं है. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि इस में कुछ झगड़ा है. कोई झगड़ा है, तभी ये पहले एलओएसी था, अब एलओसी है. स्थाई बॉर्डर नहीं बना. पाकिस्तान का फैक्टर मैंने इसलिए दुहराया, क्योंकि उनकी तरफ़ से भी अपनी कोशिशें जारी रहीं, कभी एक शक्ल में कभी दूसरी शक्ल में.

वर्ष 1947 में विभाजन के समय जब जम्मू में साम्प्रदायिक दंगे हुए, जिसमें काफ़ी लोग मारे गए, जब पंजाब के बॉर्डर पर भी ख़ून की नदियां बह रही थीं, उस समय भी कश्मीर एक ऐसी जगह थी, जहां एक भी साम्प्रदायिक वारदात नहीं हुई. तो कश्मीर की वह पहचान बदल गई. ये पहचान किसी और चीज़ की वजह से नहीं, बल्कि लगातार आने वाली सरकारों की नीतियों की वजह से बदली. एक बड़ा वैक्यूम (रिक्ति) बन गया. उस वैक्यूम का फ़ायदा धार्मिक अतिवाद ने लिया, जम्मू में भी और कश्मीर में भी. आज हालत यह है कि जम्मू और कश्मीर के बीच पोलराइज़ेशन (ध्रुवीकरण) है. जो रही-सही कसर थी, बीजेपी की सत्ता में भागीदारी ने पूरी कर दी. अब कश्मीरी अवाम एक बार फिर अधिक ख़तरा महसूस करने लगी है, जैसे उनके पास नाम का ही जो बचाखुचा आर्टिकल 370 था, वो भी ख़त्म हो जाएगा. उनके कार्यकर्ता कभी एक अदालत में कभी एक ढंग से कभी दूसरे ढंग से स्टेट सब्जेक्ट्स के क़ानूनों को चुनौती दे रहे हैं और कभी 370 को बहस का मुद्दा बनाया जा रहा है. दरहक़ीक़त आज कश्मीर की जनता अधिक ख़तरा महसूस कर रही है.

अभी 2014 में जो चुनाव हुए उसमें पीडीपी, जो नेशनल कांफ्रेंस के एक विकल्प के तौर पर देखी जा रही थी, को एक बड़ा मैंडेट मिला. पीडीपी के एजेंडा में और बातों के अलावा यह सवाल भी था कि बीजेपी का ख़तरा है, बीजेपी का सैलाब आने वाला है, उसको रोकने के लिए ताक़त चाहिए, ताक़तवर प्लेटफार्म चाहिए, जो पीडीपी के पास है. लेकिन लोगों को तब बहुत ज्यादा मायूसी हुई, जब इसी पार्टी ने बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाने के लिए समझौता किया. लोगों ने इसको सरेंडर माना. पूरे देश में बीफ का सवाल उठा, उत्तर प्रदेश में जिस तरह से अख़लाक़ की पीट-पीट कर हत्या की गई और यहां उधमपुर में भी एक कश्मीरी को मारा गया, इसके साथ-साथ कश्मीर में सैनिक कालोनी बनाने की बात चली, कभी कश्मीरी पंडितों को कंपोजिट तरीक़े से रिहैबिलीटेट (पुनर्वास) करने के बजाए अलग कालोनी बनाने की बात हुई. इन सभी चीज़ों ने एक ख़ौफ़ का माहौल पैदा किया, एक असुरक्षा की भावना पैदा की. ये सब इकट्ठा होता गया और हमारी नज़र में यह इकट्ठा हुआ गुस्सा है, जिसकी अभिव्यक्ति आज के बड़े विरोध प्रदर्शन में और यहां जारी अशांति में हुई है और जो कि हर लिहाज़ से अभूतपूर्व है. उसे हम यह नहीं कह सकते हैं कि ये (जैसा कि पूरे देश में चर्चा है) पाकिस्तान की वजह से है, आतंकवाद की वजह से है. ये बिल्कुल सही है कि पाकिस्तान की अपनी दख़लअंदाज़ी है, आतंकवाद का अंश भी मौजूद है, लेकिन इस विरोध प्रदर्शन को पाकिस्तान और आतंकवाद की ही एक साज़िश करार दे देना बिल्कुल ग़लत होगा. सही यही है कि ज्यादतियों और ग़लतियों का आज तक जो सिलसिला जारी रखा गया, ये उसी अलगाव की भावना का नतीजा है. दर्द बढ़ता गया, ज्यों-ज्यों दवा की.

मुझे अफ़सोस ये है कि लोग भी मरे, काफ़ी घर भी उजड़ गए, बिजनस तबाह हैं, आज इतना वक्त हुआ और सब कुछ पैरालाइज्ड है, लेकिन भारत सरकार अभी भी डायलॉग की बात करने से हिचकिचाती है. हम विपक्ष के नेता 22 अगस्त को भारत के प्रधानमंत्री से मिले थे. हमने वहां अपील की कि यह सियासी मसला है, ये दर्द सियासी है और अपने लोगों को मनवाने के लिए एक ही रास्ता है, वो रास्ता है सियासी रास्ता, सियासी डायलॉग. हमने ये भी कहा कि इस दर्द से अगर आंखें बंद की जाएंगी, तो न सिर्फ़ जम्मू-कश्मीर का नुक़सान होगा, बल्कि पूरे उपमहाद्वीप का नुक़सान होगा और देश का भी नुक़सान होगा. इसलिए ज़रूरी है कि इस हक़ीक़त को माना जाए और डायलॉग की पेशकश की जाए. बाद में पीएमओ से एक घोषणा-पत्र मिला, उसमें लिखा गया था कि इस मसले का आख़िरी हल ढूंढने के लिए डायलॉग की प्रक्रिया ही सही रास्ता है. लेकिन 22 अगस्त से आज तक हम इंतज़ार कर रहे हैं कि डायलॉग की दिशा में कहीं से भी कोई एक क़दम उठाया जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा.

एक मांग की थी हमने कि हमारे जो लोग हैं, हमारे जो नौजवान हैं, कई लोग तो मारे गए लेकिन कई लोग हैं, जिनकी आंख की रौशनी चली गई है, वो अंधे हो गए हैं. हमें अंधा होने से बचाइए और हमें पैलेट गन से निजात दिलाइए. हमारी बातें चर्चा में लाई गईं संसद में और संसद के बाहर भी, लेकिन पैलेट गन का इस्तेमाल (ये लेख लिखे जाने तक) अब भी जारी है. आज भी एक ही रास्ता है सरकारों के पास कि दिल्ली से श्रीनगर तक गिरफ्तारियां करते रहो, और गिरफ्तारियों के साथ-साथ ताक़त का बेतहाशा इस्तेमाल करते रहो. हमारी नज़र में ताक़त का बेतहाशा इस्तेमाल, अंधाधुंध गिरफ्तारियां और पैलेट गन का इस्तेमाल कल भी हल नहीं थे और आज भी नहीं हैं. इसे मर्ज़ बढ़ता ही जाएगा. माना आज आग बुझ जायेगी, लोग थक जायेंगे, लेकिन चिंगारी बदस्तूर क़ायम रहेगी. कल क्या होगा? कल आज से ख़राब ही होगा, ये हमारा डर है, हमारा अंदाज़ा है. आज भी हमारी अपील है डेमोक्रेटिक सेक्शन से, हमें ये उम्मीद है कि हिंदुस्तान जैसे बड़े मुल्क में काफ़ी लोग हैं, जिनमें आज भी लोगों के अधिकार के बारे में तड़प है, लोगों के बारे में चिंता है. अभी वो हिंदुस्तान जिसके बारे में कश्मीरियों ने कभी सपना देखा था, वो मरा नहीं, वो अब भी मौजूद है. हमें उम्मीद है कि डेमोक्रेटिक सेक्शन चाहे वो संसद में हों या संसद के बाहर, वो आवाज़ उठाएंगे ताकि कश्मीरियों को इन्साफ मिले और इन्साफ न मिले तो ये रास्ता हम सब के लिए कल और ज्यादा ख़तरनाक बन सकता है.■

feedback@chauthiduniya.com

सभी फोटो-प्रभात पाण्डेय

भारत इज़राइल समझौता

मनमोहक लेकिन ख़तरनाक

जब पूरा देश नोटबंदी की अफरातफरी में फंसा था, उसी बीच भारत और इज़राइल के बीच ऐतिहासिक समझौते हुए. ये समझौते प्रथम दृष्टया चिंताजनक हैं. चिंताजनक इसलिए हैं, क्योंकि इज़राइल का इस्लाम और मुसलमानों को लेकर जो वर्ल्ड-व्यू है, जो नजरिया है, वो भारत जैसे बहुधार्मिक व बहुसांस्कृतिक देश के लिए अस्वीकारणीय और हानिकारक है. इज़राइल की नीतियों को भारत की एक बड़ी आबादी अच्छा नहीं मानती है. इज़राइल की नीतियों की निंदा करने वाले हिंदू, मुसलमान, ईसाई यानि सब धर्मों के हैं. इसलिए, भारत- इज़राइल रिश्ते को सरकार गुप्त रखती है. ये अगर इत्तेफाक है, तो अजीबोगरीब इत्तेफाक है कि जब पूरा देश नोटबंदी के बाद अफरातफरी में फंस गया इसी दौरान इज़राइल और भारत के बीच कई समझौते हो गए. हैरानी तो इस बात की है कि भारत सरकार के इस कारनामे पर किसी का ध्यान ही नहीं गया. मीडिया ने भी इसे जनता से छिपा लिया. देश की वो सभी विपक्षी पार्टियां जो मुसलमानों के वोट पर सत्ता का सुख प्राप्त करती हैं, उन्होंने भी चुप्पी साध ली.

मनीष कुमार

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के पहले प्रधानमंत्री होंगे जो इज़राइल का दौरा करेंगे. इज़राइल अब भारत में कंपनी लगाकर भारत सरकार की मेक-इन-इंडिया योजना के साकार करेगा. इज़राइल अब हर शहर और गांव में हर घरों तक डिजिटल इंडिया नामक योजना के तहत पहुंचेगा. इज़राइल अब देश में बनने वाले 100 स्मार्ट सिटीज में प्रभावी भूमिका निभाएगा. स्मार्ट सिटी के निर्माण में तकनीक के साथ-साथ घरों और शहरों को भी बनाएगा. इसके अलावा इज़राइल अब देश में हथियार बनाएगा, साथ ही भारत के साथ कंधे से कंधे मिलाकर आतंकवाद और नक्सलवाद के खिलाफ लड़ेगा. ये सारे फैसले तब हुए, जब देश की जनता बैंकों के बाहर लाइन में लगी थी. उसी दौरान इज़राइल के राष्ट्रपति रूवेन रिवलिन भारत में एक सप्ताह के राजकीय दौरे पर थे. इस दौरान वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले. कई समझौतों पर दस्तखत किए और तो और राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने उनके स्वागत में भोज भी रखा. 1996 के बाद किसी इज़राइली राष्ट्रपति का यह पहला दौरा था. भारत और इज़राइल के बीच हुए समझौतों को समझने से पहले इस दौरान दिए गए बयानों का विश्लेषण जरूरी है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बयान दिया कि दोनों देश रिश्ते को और भी सशक्त करने पर सहमत हैं. सवाल ये है कि और कितना सशक्त करना है और क्यों करना है. भारत वैसे ही इज़राइली हथियारों का सबसे बड़ा खरीददार है और इज़राइल का दसवां सबसे बड़ा बिजनेस पार्टनर है. हमने इज़राइल से अब तक 12 बिलियन डॉलर के हथियार खरीदे हैं और उसके साथ 4.52 बिलियन का हमारा सालाना व्यापार होता है. इसके बावजूद अगर रिश्ते को और भी ज्यादा सशक्त करने की जरूरत है, तो इसका मतलब है कि मामला कुछ ज्यादा ही गंभीर है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगे कहा कि रिश्ते को सशक्त करने की इसलिए जरूरत है ताकि चरमपंथ, अतिवाद और आतंकवाद जैसे खतरे से मिलकर लड़ा जा सके. अब आज के दौर में इन भारी भरकम शब्दों का मतलब समझना ज्यादा कठिन नहीं है. इन तीनों शब्दों में सब शामिल हैं, जैसे इस्लामिक रूढ़िवादी, आतंकवादी, अलगाववादी, नक्सली संगठन, व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई लड़ने वाले और सत्ता से लड़ने वाली सारी शक्तियां हैं, जो यथास्थिति के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं. मतलब साफ है कि भारत सरकार इज़राइल के साथ मिल कर इन खतरों से लड़ने की तैयारी कर रही है और दोनों देश इन्हें खत्म करने पर सहमत हैं.

अब जरा राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के बयानों पर गौर करते हैं. उन्होंने तो आजादी के बाद से चली आ रही विदेश नीति को ही उल्टा-पुल्टा कर दिया. उन्होंने पहले अपने बयान में इज़राइल की जनता को अनोखा व उत्कृष्ट बताया और फिर भारत की जनता के साथ उनके अटूट रिश्ते का वास्ता दिया और कहा कि दोनों देशों की जनता के बीच कितनी समानता है. इतना ही नहीं, राष्ट्रपति रेवलिन से गांधी जी की समाधि पर फूल भी चढ़वाया गया और रात्रि भोज के दौरान राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने यहां तक कह दिया कि इज़राइल की जनता ने हिम्मत के साथ अपनी दिक्कतों का सामना किया और अपनी इच्छाशक्ति की बदौलत यह एक सशक्त राष्ट्र बनकर उभरा है. क्या प्रणब मुखर्जी के बयान से ये प्रतीत नहीं होता है कि उन्होंने इज़राइल द्वारा फिलिस्तीन की जनता पर ढाए सारे जुल्म को उचित ठहराया? लेकिन इससे भी ज्यादा हैरान करने वाला बयान राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने ये

दिया कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने इज़राइल पर यहूदियों के अधिकार को न्यायसंगत माना था. साथ ही पंडित नेहरू ने भी इज़राइल पर यहूदियों के अधिकार का समर्थन किया था और उसे एक हकीकत माना था. अब ये बात समझ के बाहर है कि जब महात्मा गांधी और पंडित नेहरू ने इज़राइल पर यहूदियों के अधिकार को जायज मान लिया तो फिर 1992 तक इज़राइल के साथ भारत के रिश्ते को गुप्त क्यों रखा गया? क्यों भारत फिलिस्तीन का हिमायती होने का दावा करता रहा?

अब जरा दोनों देशों के बीच हुए करारों पर नजर डालते हैं. भारत सरकार अब इज़राइलियों को कृषि, शोध, व्यापार, साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में काम करने की छूट दे रही है. गौर करने वाली बात ये है कि भारत सरकार पहले से ही इज़राइली कंपनियों को भारत में ज्वाइंट वेंचर बना कर हथियार बनाने की इजाजत दे चुकी है. इज़राइल के राष्ट्रपति ने कहा कि भारत में जारी उदारीकरण इज़राइली कंपनियों के लिए एक सुनहरा अवसर है. दोनों देशों के बीच हुए समझौते का लब्बोलुबाव ये है कि इज़राइल मोदी सरकार की मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्मार्ट सिटी जैसी तमाम योजनाओं में एक प्रभावी भूमिका निभाएगा. इज़राइली कंपनियां सीधे इन योजनाओं से जुड़ कर इन्हें पूरा करेंगी. मतलब ये कि मेक इन इंडिया के तहत इज़राइली कंपनियां भारत में निवेश करेंगी और अलग-अलग उपयोगी सामान बनाएंगी. इसी योजना के तहत भारत सरकार देश में रोजगार पैदा करने की बात कह रही है. अब सवाल ये है कि क्या इज़राइली कंपनियों में सभी धर्म के लोगों को रोजगार मिलेगा या इन कंपनियों में भेदभाव होगा? उसी तरह डिजिटल इंडिया के जरिए इज़राइली कंपनियां गांव-गांव तक अपनी पहुंच बनाएंगी. क्या सरकार ने ये सोचा है कि इससे देश के अल्पसंख्यकों खास कर मुसलमानों के बीच क्या संदेश जाएगा? उसी तरह अगर इज़राइल के जरिए देश में स्मार्ट सिटी बनाया जाएगा या इज़राइली कंपनियां मकान बनाएंगी तो क्या देश के मुसलमान उन शहरों और घरों में रहने में सहज महसूस करेंगे? ये सवाल अटपटा जरूर लग सकता है, लेकिन सच्चाई ये है कि दुनिया भर के मुसलमान इज़राइल को लेकर असहज महसूस करते हैं. इन समझौतों पर अमल करने के पहले क्या सरकार को देश के करीब 20 फीसदी आबादी के बारे में सोचना नहीं चाहिए था? सरकार ने नहीं सोचा तो क्या देश की दूसरी पार्टियों को इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाना चाहिए? ये बात इसलिए भी कही जा सकती है, क्योंकि राष्ट्रपति रिवलिन की भारत यात्रा से एक अजीबोगरीब संदेश देने की कोशिश की गई है. उनके कार्यक्रम में 2008 में हुए मुंबई हमले के घटनास्थलों का दौरा शामिल किया गया. उन्हें द्वितीय विश्वयुद्ध में शहीद हुए भारतीय जवानों की समाधि पर ले जाया गया. मुंबई के यहूदी समुदाय के लोगों ने चाबाद हाउस में एक विशेष श्रद्धांजलि समारोह का अयोजन किया. भारत के शीर्ष अधिकारियों और यहूदी समुदाय के विशिष्ट लोगों से मुलाकात भी कराया गया. भारत सरकार को समझना पड़ेगा कि देश के अंदर जब अल्पसंख्यकों या समाज के पिछड़े वर्गों के खिलाफ हिंसक घटनाएं होती हैं, तो लोग लड़ते हैं. कोर्ट मीडिया और गली चौराहों पर अपने अधिकार जमाते हैं. कुछ दिन बाद भूल भी जाते हैं. भारत का बहुसंख्यक समाज हिंसक घटनाओं की निंदा भी करता है, जिससे अल्पसंख्यकों का हौसला कभी पस्त नहीं होता है. गौ-मांस का मुद्दा हो या कॉमन सिविल कोड का, उस पर विरोध भी होता है और वाद-विवाद भी होता है. हर पक्ष जमकर बहस भी कर लेता है. बात आई गई हो जाती है लेकिन जब मामला इज़राइल को देश के अंदर खुली छूट देने का हो, तो यह बाकी सारे मामलों से ज्यादा संवेदनशील हो जाता है. इज़राइल के हस्तक्षेप से देश की 20 फीसदी आबादी के विमुख होने का खतरा पैदा हो जाता है, जिसे वापस खत्म करना मुश्किल हो जाएगा. इसकी वजह यह है कि इज़राइल का इतिहास और नीति शुरू से ही मुस्लिम विरोधी रही है. यही भारत-इज़राइल समझौते का प्रच्छन्न भाव भी था.

ऐसा लगता है कि भारत-इज़राइल वार्ता के दौरान हर फैसला इस्लामिक आतंकवाद को ध्यान में रख कर लिया गया है. दोनों देशों के द्वारा जारी संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति को पढ़ कर ऐसा लगता है कि दुनिया के सामने सिर्फ आतंकवाद ही एक मात्र समस्या है. हालांकि विज्ञप्ति में इस्लामिक आंतकवाद शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया, लेकिन भाषा और शैली से ये साफ हो जाता है. इज़राइल को फिलिस्तीनियों से परेशानी है और भारत को पाकिस्तान से इसलिए विज्ञप्ति में ये लिखा गया कि वो देश या संगठन, जो आंतकवाद को संरक्षण देते हैं, उनके खिलाफ दोनों देश एकजुट होकर लड़ेंगे. इस एकजुटता का सबसे ज्यादा असर सैन्य, तकनीक और साइबर क्षेत्र में होगा. अब ये समझ के बाहर की बात है कि न तो मीडिया और न ही विपक्षी पार्टियों ने इस मुद्दे को उठाया. खासकर खुद को सेकुलर होने का दंभ भरने वाली पार्टियों और नेताओं को तो सामने आना चाहिए. क्या वजह है कि सबकुछ गुप्त रूप से किया गया. भारत का मीडिया, टीवी चैनल या अखबार, भारत-इज़राइल रिश्ते पर विस्तृत जानकारी नहीं देते हैं, लेकिन इज़राइल की अखबारों से पता चलता है कि भारत-इज़राइल रिश्ता पिछले कुछ सालों में कितना प्रगाढ़ और गहरा हो गया है. ये बहुत कम लोग जानते हैं कि करीब 40 हजार यहूदी हर साल भारत आते हैं. इनमें ऐसे कई लोग शामिल होते हैं, जो इज़राइली सेना में काम कर चुके हैं. ये बात क्यों छिपाई गई है कि भारत की स्पेस एजेंसी इसरो ने हाल में ही इज़राइल के लिए एक मिलिट्री सेटेलाइट को लॉन्च किया था. सितंबर 2015 में मोदी सरकार ने इज़राइल एयरोस्पेस इंडस्ट्री से 10 ड्रोन खरीदने की इजाजत दी. इसके अलावा सितंबर 2016 में भारत सरकार ने इज़राइल से अथअउड प्लेन लेने की योजना को हरी झंडी दी. साथ ही भारत और इज़राइल की सेना के बीच एक ज्वाइंट एक्सरसाइज की भी पूरी तैयारी कर ली गई है. हाल में ही इज़राइली अखबार द हारेट्ज़ ने खबर दी कि इज़राइली एफ-16 लड़ाकू विमान के पायलटों का एक जत्था भारतीय वायुसेना के साथ एक अलग किस्म का प्रशिक्षण देगा. नवंबर 2015 में एक और अजीबोगरीब खबर आई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तुर्की यात्रा के दौरान उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी इज़राइली खुफिया एजेंसी मोसाद के हाथों थी. मोदी जब जी-20 समिट के लिए इंग्लैंड जा रहे थे उस दौरान वो टर्की में रुके थे.

इज़राइली अखबार जेरूसलम पोस्ट ने खबर दी कि अगस्त के महीने में भारत की बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की एक टीम इज़राइल पहुंची थी. बीएसएफ की टीम इज़राइली रडार टेक्नोलॉजी और डिटेक्शन सिस्टम को ऑपरेट करने की तकनीक की ट्रेनिंग के लिए वहां गई थी. मतलब यह कि इज़राइली रडार टेक्नोलॉजी भारत आने वाला है. इसे कश्मीर में इस्तेमाल किया जाएगा. इसे नक्सलियों के खिलाफ आपरेशन में भी इस्तेमाल किया जा सकता है. इस पूरे सिस्टम की खासियत यही है कि यह घने जंगल और पहाड़ों में सटीक काम करता है. इसमें उच्च कोटि के सेंसर लगे हैं, जो इंसानों और गाड़ियों को घने जंगल में भी चिन्हित कर सकते हैं और उनका पीछा कर सकते हैं. इस खबर में ये भी बताया गया कि इस रडार सिस्टम को खरीदने की अनुमति सीधे अजीत डोभाल ने दी थी. जानकार बताते हैं इस रडार सिस्टम का इस्तेमाल इज़राइल ने फिलिस्तीन के कई नेताओं और उपद्रवियों को खत्म करने के लिए किया है. इसका निशाना अचूक होता है.

भारत और इज़राइल के बीच ऐतिहासिक समझौते हुए लेकिन देश को पता तक नहीं है. भारत-इजराइल के साथ क्यों नज़दीकियां बढ़ाना चाहता है. दोनों देशों की रणनीति क्या है और दोनों देशों को इससे क्या फायदा मिलने वाला है. लगता तो यही है कि इस गठजोड़ का मक़सद है, इस्लामिक आतंकवाद का खतरा दिखा कर दक्षिण एशिया को वार-जोन में बदलना. क्या इज़राइल और भारत सरकार पाकिस्तान की तबाही और जम्मू-कश्मीर मे दमन की तैयारी कर रही है. क्या इस गठजोड़ का आधार सिर्फ इतना है कि दोनों देशों का दुश्मन एक ही है, मतलब इस्लामिक आतंकवाद और पाकिस्तान. क्या भारत सरकार ने इज़रायल और अमेरिका के साथ मिलकर आतंकवाद और पाकिस्तान के खिलाफ़ स्ट्राइक एंड क्रश यानी हमला करने और कुचलने की नीति बनाई है. ऐसे कई सवाल हैं, जो आज महत्वपूर्ण बन गए हैं. आंतकवाद, वैचारिक अतिवाद, धार्मिक रूढ़िवाद व हिंसा से भारत को खतरा तो है, लेकिन इसका हल देश के अंदर ही निकालना पड़ेगा. पाकिस्तान के साथ रिश्ते सुधार कर निकालना पड़ेगा. इज़राइल के साथ मिल कर इसका कोई हल नहीं निकल सकता, उल्टा ये पूरा इलाका वार जोन में बदल जाएगा. ■

manishbph244@gmail.com

कश्मीर की स्थिति में सुधार के इशारे

अवाम की मुश्किलें बरक़रार

हारून रेशी

कश्मीर घाटी में स्थिति में सुधार के साफ़ इशारे मिलने शुरू हो गए हैं. वरिष्ठ अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी, मीरवाइज उमर फारूक और यासीन मलिक की ओर से जारी होने वाले विरोध प्रदर्शन के साप्ताहिक कैलंडरों में भी अब बदलाव दिखने लगे हैं. विरोध प्रदर्शन के कैलेंडर में पहली बार सप्ताह के अन्दर हड़ताल में छूट दी गई है. यानि चार महीने के लम्बे विरोध प्रदर्शन के सिलसिले के बाद पहली बार कश्मीर घाटी में आम ज़िन्दगी पूरे दो दिन तक सामान्य रहेगी. पिछले सप्ताह एक लम्बे समय के बाद श्रीनगर की सड़कों पर सवारी गाड़ियां दौड़ती हुई देखी गईं. यानी पिछले चार महीनों के दौरान कश्मीर में शत प्रतिशत ट्रांसपोर्ट बंद रहने के बाद अब सवारी गाड़ियां सड़कों पर निकलनी शुरू हो गई हैं. दसवीं और बारहवीं की परीक्षा में उम्मीद के विपरीत 98 फ़िसद छात्र-छात्राओं ने भाग लिया. चार महीने में पहली बार मुख्यधारा की दो पार्टियों पीडीपी और नेशनल कांफ्रेंस ने श्रीनगर में आम सभाएं की, जिनमें सैकड़ों पार्टी कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया.

पीडीपी ने 13 नवंबर को श्रीनगर के लालचौक से एक किलोमीटर की दूरी पर स्थित पार्टी ऑफिस के करीब एक दिवसीय सम्मलेन किया, जिसमें पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने भाग लिया. उसके तीन दिन बाद यानि 16 नवंबर को नेशनल कांफ्रेंस ने श्रीनगर में अपने पार्टी हेडक्वार्टर पर एक सभा का आयोजन किया. कुछ सप्ताह पहले तक मुख्यधारा की पार्टियां इसतरह की सभाओं के आयोजन के बारे में सोच भी नहीं सकती थीं. नोटबंदी के बाद पुराने नोटों को बदलवाने के लिए श्रीनगर और घाटी के दूसरे क्षेत्रों में बैंकों की शाखाओं पर लोगों की लम्बी कतारें देखने को मिल रही हैं. हालांकि चार महीने तक चले विरोध प्रदर्शन के दौरान यहां के बैंक भी बंद रहे हैं. इस बीच हिंसक घटनाओं की संख्या में भी लगातार कमी देखने को मिल रही है. पुलिस के आंकड़ों के मुताबिक 8 जुलाई को हिज्ब कमांडर बुरहान वानी के मारे जाने के बाद जुलाई में पथराव की 820 वारदातें हुईं. अगस्त में 747, सितंबर में 157 और अक्टूबर में 119 पथराव की घटनाएं हुईं. जबकि चालू महीने के शुरुआती पंद्रह दिनों में पथराव की केवल 49 वारदातें सामने आई हैं.

पीडीपी ने 13 नवंबर को श्रीनगर के लालचौक से एक किलोमीटर की दूरी पर स्थित पार्टी ऑफिस के करीब एक दिवसीय सम्मलेन किया, जिसमें पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने भाग लिया. उसके तीन दिन बाद यानि 16 नवंबर को नेशनल कांफ्रेंस ने श्रीनगर में अपने पार्टी हेडक्वार्टर पर एक सभा का आयोजन किया. कुछ सप्ताह पहले तक मुख्यधारा की पार्टियां इसतरह की सभाओं के आयोजन के बारे में सोच भी नहीं सकती थीं. नोटबंदी के बाद पुराने नोटों को बदलवाने के लिए श्रीनगर और घाटी के दूसरे क्षेत्रों में बैंकों की शाखाओं पर लोगों की लम्बी कतारें देखने को मिल रही हैं.

ये सारी बातें इशारा कर रही हैं कि कश्मीर घाटी में हालात सामान्य हो रहे हैं. लेकिन हालात में बेहतरी आने के साथ ही कश्मीर के राजनीतिक और अवामी हल्कों में इस सवाल पर बहस शुरू हो गई है कि लगातार चार महीनों से जारी प्रदर्शन से कश्मीर की जनता ने क्या खोया और क्या पाया. गौरतलब है कि इस दौरान कश्मीर घाटी के सभी दस जिलों में कश्मीरी अवाम को हिंसा से भरे दौर से गुजरना पड़ा है. सुरक्षा बलों की कार्रवाई में इस दौरान कई बच्चों समेत लगभग 100 लोग मारे गए हैं. स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक हिंसक विरोध प्रदर्शन के दौरान 1200 बच्चों के साथ 9010 लोग घायल हुए. यह आंकड़ा उन लोगों पर आधारित है, जिन्हें ज़ख्मी होने के बाद इलाज के लिए घाटी के अलग-अलग अस्पतालों में लाया गया था. ज़ख्मी लोगों में कई ऐसे हैं, जो पैलेट गन की ज़द में आकर अपनी एक आंख या दोनों आखें खो चुके हैं. इतना ही नहीं पुलिस ने हिंसा और विरोध प्रदर्शन के वारदात में शामिल होने के इल्जाम में दस हज़ार नौजवानों को गिरफ्तार किया है. इनमें से पांच सौ से अधिक लोगों को पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत जेल भेज दिया गया है, यानी ऐसे लोगों को अदालत में पेश किये बिना महीनों या बरसों तक जेल में रखा जा सकता है.

पिछले चार महीने के दौरान घाटी में हर वर्ग के लोगों को आर्थिक दृष्टि से भी नुकसान उठाना पड़ा है. अर्थशास्त्रियों के मुताबिक कश्मीर घाटी प्रतिदिन 130 करोड़ रुपये का नुकसान झेल रही है. सबसे बदतर स्थिति गरीबी रेखा से नीचे जीवन व्यतीत करने वालों की हुई है. इन चार महीनों के दौरान निजी कंपनियों और कारोबारी संस्थाओं में काम करने वाले लोग बड़ी तादाद में बेरोजगार हो चुके हैं. वो लाखों व्यापारी जिन्होंने बैंकों से ऋण ले रखा है, ब्याज के बाद ब्याज के बोझ से दब चुके हैं. इस पृष्ठभूमि में ज्यादातर राजनीतिक विश्लेषक इस बात से सहमत हैं कि विरोध प्रदर्शनों और हड़तालों की रणनीति को बदलने की जरूरत है.

कश्मीर यूनिवर्सिटी में राजनीति शास्त्र के पूर्व विभागाध्यक्ष नूर अहमद बाबा ने इस विषय पर चौथी दुनिया से बातचीत करते हुए बताया कि सबसे पहले कश्मीरी जनता और उसके नेतृत्व को इस सवाल का जवाब ढूंढना चाहिए कि वे लगातार हड़तालों से किस तरह की नतीजों की उम्मीद कर रहे हैं. पिछले चार महीनों के प्रदर्शन के नतीजे में हमें क्या हासिल होने की उम्मीद है. उन्होंने आगे कहा कि हड़तालों से छोटी-छोटी समस्याएं तो हल हो सकती हैं, लेकिन जहां तक बड़े राजनीतिक उद्देश्य यानि आजादी का सवाल है, तो इसके जरिए भारत सरकार को मजबूर नहीं किया जा सकता है.

कई दूसरे विश्लेषकों को कहना है कि कश्मीर की जनता के संघर्ष को किसी नतीजे तक पहुंचाने और कुर्बानियों को बेकार हो जाने से बचाने के लिए ये जरूरी है कि जनता और नेतृत्व आत्मविश्लेषण करें. वरिष्ठ पत्रकार और दैनिक चट्टान के एडिटर ताहिर मोहीउद्दीन ने चौथी दुनिया से बातचीत में कहा कि हालात ठीक हो जाने के बाद यह आवश्यक है कि कश्मीरी जनता खास तौर पर उनके नेता इस बात पर विचार करें कि चार-पांच महीने के इस संघर्ष के नतीजे में क्या हासिल किया गया और अगर कुछ हासिल नहीं हुआ है, तो इसके कारण क्या हैं? इस सवाल पर राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर बहस की जरूरत है.

बहरहाल, अब एक ऐसे वक्त में जब घाटी में हड़तालों और प्रदर्शनों का सिलसिला थमता हुआ नजर आ रहा है और हालात सामान्य होते नजर आ रहे हैं. ऐसे में आम कश्मीरियों को कुछ नई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है. सबसे ज्यादा परेशानी उन लोगों को होगी जिनके बच्चे या रिश्तेदार पिछले चार माह के दौरान हिरासत में लिये जा चुके हैं. उन्हें छुड़ाना उनके लिए एक समस्या होगी. आम व्यापारियों और ट्रांसपोर्टरों को ये परेशानी होने लगी है कि पिछले चार माह के बंद के दौरान उनके बैंक कर्जों में जो वृद्धि हुई है उसकी भरपाई कैसे होगी. गौरतलब है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने राज्य स्तर के बैंकर्स की समीति के उस दरख्वास्त को रद्द कर दिया है, जिसमें उन्होंने मुश्किल परिस्थितियों से प्रभावित हुए व्यापारियों के कर्जे की वसूली में नरमी बरतने और वसूली की अवधि में वृद्धि करने की अपील की थी. साफ जाहिर है कि अगर हड़तालों और प्रदर्शनों का सिलसिला थम भी गया, तो भी कश्मीरी जनता को तरह-तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा. ■

feedback@chauthiduniya.com

बनने से पहले ही विवादों में मणिपुर स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी

एस. बिजेन सिंह

मणिपुर में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाना मोदी सरकार के पहले 100 दिन के एजेंडे में शामिल था. इसके लिए यूनियन बजट में 100 करोड़ रुपये का प्रावधान भी कर दिया गया. लेकिन अब तक यूनिवर्सिटी के लिए जमीन तय करने का काम भी पूरा नहीं हो पाया है. स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी में पदकर खिलाड़ी बनने का सपना पाले बच्चों का भविष्य केंद्र और राज्य सरकार के बीच मतभेदों में उलझ कर रह गया है. पहले सौ दिन क्या, मोदी सरकार ने अपने दो साल पूरे कर लिए लेकिन स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वादा अभी तक अधर में लटका पड़ा है.

स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के लिए राज्य सरकार से केंद्र की मांग 200 एकड़ जमीन की थी. लेकिन राज्य सरकार ने इसके लिए निर्धारित जमीन से ज्यादा ही एलॉट कर दिया. मणिपुर सरकार ने 27 अगस्त 2015 को याइथिबी लौकोल में 336.93 एकड़ जमीन स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री को दे दी थी. याइथिबी लौकोल, श्रीवाल जिले में पड़ता है. हालांकि जमीन मालिक शुरू से ही इसका विरोध कर रहे थे. राज्य सरकार के द्वारा जमीन एलॉट किए जाने के एक साल बाद चार नवंबर 2016 को इंफाल दौरे पर आए केंद्रीय खेल मंत्री विजय गोयल ने उस जगह को स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के लिए नापसंद कर दिया.

स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के लिए राज्य सरकार ने थौबाल जिले के सोरा गांव स्थित याइथिबी लौकोल की जो जमीन एलॉट की थी, वह उपजाऊ खेतीहर जमीन है. सोरा दो पहाड़ों के बीच बसा एक गांव है, जिसकी आबादी 7500 के करीब है. लगभग 300 जमीन मालिकों ने उस जमीन पर स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाने का विरोध किया था. सोरा निवासी इफेक्टेड लैंड एसोसिएशन के जॉइंट सेक्रेटरी एमडी नजीमुद्दीन का कहना है कि यह विरोध लैंड एक्यूजिशन से पहले हुआ था. हम लोग भी विकास चाहते हैं. मणिपुर में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाने का हम स्वागत करते हैं. लेकिन इस जमीन पर लोगों की रोजी रोटी चल रही है. अगर यहां स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनता है, तो हमारा घर और खेती की जमीन बर्बाद हो जाएंगे. हमें ऐसा विकास पसंद नहीं, जो हमें बेघर बनाकर किया जा रहा है. इसलिए हम लोग विरोध करते हैं. राज्य सरकार के द्वारा लोगों को जानकारी नहीं देने की वजह से जमीन पर विवाद बढ़ा. विजय गोयल के इंफाल दौरे में याइथिबी लौकोल में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाने के फैसले से नाखुश ग्रामीणों ने जमकर विरोध किया. भीड़ को काबू कर रही पुलिस और ग्रामीणों में तीखी नोक-झोक भी हुई, जिसमें 22 लोग घायल हुए.

अब सोरा के लोगों के विरोध को केंद्र सरकार की तरफ से इस जगह को नापसंद करने की वजह बताया जा रहा है. राज्य के लोगों ने आरोप लगाया कि सोरा की जनता ने भाजपा से मिलकर यहां से यूनिवर्सिटी को शिफ्ट करवाया है. लोगों को इस बात का भी डर है कि जमीन विवाद को देखते हुए कहीं इस यूनिवर्सिटी को मणिपुर से असम शिफ्ट न कर दिया जाए. पूर्व खेल मंत्री, असम के सीएम सर्वानंद सोनोवाल पहले भी स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी को असम में खुलवाने की बात कह चुके हैं. जमीन चिन्हित करने समय ही अगर राज्य सरकार ने इस बारे में जानकारों से राय-मशवरा लिया होता, तो यह विवाद नहीं होता. अब विवाद बढ़ गया, तब मुख्यमंत्री ने बयान जारी किया कि राज्य सरकार को राज्य में कहीं पर भी यूनिवर्सिटी बनाने में कोई एतराज नहीं है. अगर उन्होंने यह बयान पहले दिया होता, तो सब सामान्य होता. राज्य सरकार को अब भी जमीन विवाद को लेकर स्पष्ट रुख अपनाना चाहिए, ताकि जल्द से जल्द यूनिवर्सिटी का कार्य शुरू हो सके. राज्य में अगले साल विधानसभा चुनाव होना है. ऐसे में राज्य की कांग्रेस सरकार और विपक्षी भाजपा इस मुद्दे का राजनीतिक लाभ लेना चाह रही हैं. दोनों एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप का खेल खेल रहे हैं. होना यह चाहिए कि केंद्र और राज्य की सरकारें एकमत होकर स्थानीय जनता के सहयोग से एक जगह तय करें, ताकि पूर्वोत्तर के युवाओं ने इस स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के सहारे खिलाड़ी बनने का जो सपना देखा है, वह सच साबित हो सके. ■

sbijensngh@gmail.com

याइथिबी लौकोल की जगह कौक्रूक में बने स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी: विजय गोयल

राज्य सरकार याइथिबी लौकोल में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाना चाहती है, लेकिन केंद्र सरकार इस जगह को पसंद नहीं करती. खेल मंत्री के इंफाल दौरे के दौरान उन्होंने पत्रकारों से बताया कि मणिपुर एक छोटा राज्य होने के बाद भी खेलकूद के क्षेत्र में आगे है. मणिपुर के खिलाड़ियों ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश का नाम रौशन किया है. आगे भी मणिपुर से और भी खिलाड़ी देश का नाम कमाएंगे, इसी मकसद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मणिपुर में एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाने का एलान किया था. उन्होंने कहा कि खेल के क्षेत्र में सबसे आगे रहने वाले राज्य में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाने में देरी होना सही नहीं है. कहां जमीन देना है, यह राज्य सरकार की मर्जी है. राज्य सरकार ने जमीन देने में दो साल लगा दिया. उसके बाद भी जो जमीन मिली है, वह विवादित होने के साथ-साथ लो लैंड जमीन भी है. यह जगह राजधानी इंफाल से ज्यादा दूरी पर है, जो कानून व्यवस्था के लिहाज से भी सही नहीं है. यह यूनिवर्सिटी केवल देश के लिए नहीं विदेशों से भी कोच और खिलाड़ी आनेवाले हैं. इसलिए हम चाहते हैं कि यह स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी याइथिबी लौकोल की जगह इंफाल वेस्ट स्थित कौक्रूक में बने. ■

राज्य ने नहीं केंद्र ने तय की थी जमीन : मुख्यमंत्री

राज्य के मुख्यमंत्री ओक्रम इबोबी सिंह ने कहा कि मणिपुर में नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाने की जगह राज्य ने तय नहीं किया था. यह निर्णय केंद्र सरकार का था. जमीन फाइनल करने से पहले हमने उसे केंद्र सरकार के प्रतिनिधियों को दिखाया था. अगर यह जमीन पसंद नहीं आई, तो उन्हें पहले ही कहना चाहिए था. सबकुछ तय होने के बाद अब इस तरह का बयान आना आश्चर्यजनक बात है. केंद्र के आदेश पर राज्य सरकार ने कुछ जगहों को स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी को दिखाया था. उन जगहों में कौक्रूक, याइथिबी लौकोल, नारानसैना और ताकमू आदि शामिल था. उन जगहों में याइथिबी लौकोल को सबसे ज्यादा पसंद किया था. अब एक साल बाद केंद्र सरकार की तरफ से याइथिबी लौकोल को नापसंद करने की बात समझ से परे है. राज्य सरकार की तरफ से राज्य की किसी भी जगह पर स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाने में कोई आपत्ति नहीं है. ■

नोटबंदी
पूंजीपतियों के लिए पेशबंदी

मोदी सरकार के काले धन पर सर्जिकल ऑपरेशन के इस पहलू पर भी गौर करना चाहिए कि मई 2014 में सत्ता में आने के बाद जून 2014 में ही विदेशों में भेजे जाने वाले पैसे की प्रतिव्यक्ति सीमा 75,000 डॉलर से बढ़ाकर 1,25,000 डॉलर कर दिया और जो अब 2,50,000 डॉलर है. केंद्र सरकार के केवल इस निर्णय से पिछले करीब एक साल में 30,000 करोड़ रुपये विदेशों में चले गए. विदेशों से काला धन वापस लाने की बात करने और लोगों को दो दिन में जेल भेजने वाली मोदी सरकार के दो साल बीत जाने के बाद भी आलम यह है कि एक व्यक्ति भी जेल नहीं भेजा गया. क्योंकि इस सूची में कई ऐसे नाम भी हैं, जो मोदी के चहेते बताए जाते हैं.

डॉ. रामभरोसे दास

पिछले 8 नवम्बर की रात से देशभर में अफरा-तफरी का माहौल है. बैंकों के बाहर सुबह से रात तक लम्बी-लम्बी कतारें लगी हैं, सारे काम छोड़कर लोग अपना पैसा निकालने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं. अस्पतालों में मरीजों का इलाज नहीं हो पा रहा, बाज़ार बन्द पड़े हैं, कामगारों को मज़दूरी नहीं मिल पा रही है, आम लोग रोज़मर्रा की मामूली ज़रूरतें तक पूरी नहीं कर पा रहे हैं. देश में कई जगह सदमे से लोगों की मौत तक हो जाने की ख़बरें आ रही हैं. देश के बड़े पूंजीपतियों, व्यापारियों, अफसरशाहों-नेताशाहों, फिल्मी अभिनेताओं में काले धन पर इस तथाकथित सर्जिकल स्ट्राइक से कोई बेचैनी या खलबली नहीं दिखाई दे रही है. उनके कारिंदे लाइनों में लगे नोट भले ही बदलवा रहे हों. पूरे देश का दृश्य यही है.

देश की 90 फीसदी सम्पत्ति महज 10 फीसदी लोगों के पास है और इसमें से आधे से अधिक सम्पत्ति महज एक फीसदी लोगों के पास है. यह देश के मेहनत और प्राकृतिक संसाधनों की बेतहाशा लूट से ही सम्भव हुआ है. काला धन केवल वह नहीं होता, जिसे बक्सों में बंद कर, बिस्तरों के नीचे दबा कर या जमीन में छुपा कर रखते हैं. देश में काले धन का महज छह प्रतिशत नगदी (कैश) के रूप में है. कालेधन का अधिकतम हिस्सा रियल इस्टेट, विदेशों में जमा धन और सोने की खरीद आदि में लगता है. कालाधन भी सफेद धन की तरह बाजार में घूमता रहता है और इसका मालिक उसे लगातार बढ़ाता रहता है. आज पैसे के रूप में जो काला धन है, वह कुल कालेधन का बेहद छोटा हिस्सा है और वह भी लोगों के घरों में नहीं, बल्कि बाजार में लगा हुआ है. आज देश के काले धन का अधिकांश हिस्सा बैंकों के माध्यम से पनामा, स्विस और सिंगापुर के बैंकों में पहुंच जाता है. असली भ्रष्टाचार श्रम की लूट के अलावा सरकार द्वारा ज़मीनों और प्राकृतिक संसाधनों को औने-पौने दामों पर पूंजीपतियों को बेचकर किया जाता है. साथ ही बड़ी कम्पनियों द्वारा कम या अधिक के फर्जी बिलों द्वारा, बैंकों के कर्जों का भुगतान न देकर और उसे बाद में बैंकों द्वारा नॉन परफ़ार्मिंग सम्पत्ति घोषित करा लेने और उसका भुगतान जनता के पैसे से कराने, बुरे ऋणों (बैड लोन) की माफी और उसका बैंकों को भुगतान जनता के पैसों से करके भ्रष्टाचार की लिपाई-पुताई की जाती है. पूंजीपतियों द्वारा हड़पा गया पैसा विदेशी बैंकों में जमा होता है और फिर वहां से देसी और विदेशी बाज़ारों में लगता है. इस भ्रष्टाचार में कालेधन का एक हिस्सा छोटे व्यापारियों और अफसरों को भी जाता है, लेकिन यह कुल कालेधन के अनुपात में बहुत छोटा है.

मोदी सरकार के काले धन पर सर्जिकल ऑपरेशन के इस पहलू पर भी गौर करना चाहिए कि मई 2014 में सत्ता में आने के बाद जून 2014 में ही विदेशों में भेजे जाने वाले पैसे की प्रतिव्यक्ति सीमा 75,000 डॉलर से बढ़ाकर 1,25,000 डॉलर कर दिया और जो अब 2,50,000 डॉलर है. केंद्र सरकार के केवल इस निर्णय से पिछले करीब एक साल में 30,000 करोड़ रुपये विदेशों में चले गए. विदेशों से काला धन वापस लाने की बात करने और लोगों को दो दिन में जेल भेजने वाली मोदी सरकार के दो साल बीत जाने के बाद भी आलम यह है कि एक व्यक्ति भी जेल नहीं भेजा गया. क्योंकि इस सूची में कई ऐसे नाम भी हैं, जो मोदी के चहेते बताए जाते हैं. इसमें अंबानी, अडानी से लेकर अमित शाह, स्मृति ईरानी और भाजपा के कई नेताओं के नाम हैं. यह सही है कि यूपीए के शासनकाल में भीषण घोटाले हुए, लेकिन क्या भाजपा की तत्कालीन सरकार के दरम्यान सेना का ताबूत घोटाला नहीं हुआ था? क्या मध्यप्रदेश का व्यापम घोटाला, पंकजा मुंडे और बसुंधरा राजे के घोटाले लोग भूल चुके हैं? क्या विजय माल्या और ललित मोदी जैसे उद्योगपति हजारों करोड़ धन लेकर भाजपा के मौजूदा शासनकाल में विदेश नहीं भाग गए? आज देश में 99 फीसदी काला धन इसी रूप में है और यह स्पष्ट है कि इसमें देश के नेता-मंत्रियों और पूंजीपतियों की ही हिस्सेदारी है.

आज देश में मौजूद कुल 500 और 1000 के नोटों का मूल्य 14.18 लाख करोड़ है जो देश में मौजूद कुल काले धन का महज तीन फीसदी है. जिसमें जाली नोटों की संख्या सरकारी प्रतिष्ठान राष्ट्रीय सांख्यकीय संस्थान के अनुसार मात्र 400 करोड़ है. अगर एकबारगी मान भी लिया जाय कि देश में मौजूद इन सारी नोटों का आधा काला धन है, तब भी डेढ़ फीसदी से अधिक काले धन पर अंकुश नहीं लग सकता. दूसरी तरफ जिन पाकिस्तानी नकली नोटों की बात मोदी सरकार कर रही है, वह 400 करोड़ ही है, जो आधा फीसदी भी नहीं है. अब तो यह भी सवाल उठ रहा है कि सरकार ने जो 2000 के नये नोट निकाले हैं, उससे आने वाले दिनों में भ्रष्टाचार और काला धन 1000 के नोटों की तुलना में ज्यादा बढ़ेगा. इससे पहले चाहे 1948 या 1978 में नोटों को हटाने का फैसला हो, इतनी बुरी मार जनता पर कभी नहीं पड़ी. हालांकि जनसंख्या का दबाव भी तब इतना नहीं था.

नोटबंदी के कारण महंगाई, बेरोजगारी, किसान-मजदूरों की मुश्किलों जैसे तमाम समस्याओं पर चर्चा बंद हो गई. अब सिर्फ चर्चा है तो नोटबंदी की. इसी के बूते भाजपा उत्तर प्रदेश और पंजाब के चुनावों में बाजी मार लेना चाहती है. लोगों के जेहन में यह सवाल उठ रहा है कि क्या देश का सारा काला धन 5,000 से 15,000 रुपये कमाने वाले आम श्रमजीवियों के पास है? रिक्शा चलाने वाला मजदूर, दिहाड़ी मजदूर, रेहड़ी-खोमचा लगाने वाले लोग, छोटी-मोटी नौकरी कर आजीविका चलाने वाली आम जनता बैंकों के सामने लाइन में लगी है. इनमें अधिसंख्य लोगों के पास बैंक खाते नहीं हैं, पहचान पत्र नहीं हैं. आने-जाने के पैसे नहीं हैं. राशन के पैसे नहीं हैं. दलाल इस अफरातफरी का भी फायदा उठा रहे हैं. अफवाहें उड़ रही हैं; कहीं नमक महंगे दामों पर बिक रहा है तो कहीं 500 के नोट 300 और 400 रुपये में लिए जा रहे हैं. कोई बेटी की शादी को लेकर परेशान है, तो कोई अस्पताल में परेशान है. ■

feedback@chauthiduniya.com

पूंजीपतियों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए हुई नोटबंदी

देश में मंदी और पूंजीपतियों द्वारा बैंकों के कर्जे को हड़प जाने के बाद देश के पास मुद्रा नहीं बची थी. 'कैश-क्रंच' (नगदी के अभाव) के कारण पूंजीपतियों को नया ऋण मिलने में दिक्कतें पेश आ रही थीं. जनता की गाढ़ी ईमानदार कमाई की जो राशि बैंकों में जमा होगी, उससे पूंजीपतियों को फिर से मुनाफा लूटने के लिए ऋण के रूप में पैसा दिया जा सकेगा. पूंजीपतियों द्वारा तमाम बड़े लोन बैंकों से लिए गए हैं और उनको चुकाया नहीं गया है. आज सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक 6,00,000 करोड़ रुपये की भयंकर कमी से जूझ रहे हैं. पूंजीपतियों को फिर ऋण चाहिए और सरकार अब जनता के पैसे बैंकों में भरवा रही है, जिससे धनपशुओं को ऋण दिया जा सके. रिलाएंस, वेदांता समेत कई बड़े पूंजी घराने ऋण के लिए कतार में खड़े हैं.

यूपी के किसानों को क्यों डाला मुश्किल में?

समाजवादी पार्टी के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष शिवपाल यादव का कहना है कि केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के सहकारी बैंकों पर पुराने 500 व 1000 के नोटों को बदलने व निकालने की अनुमति न देकर सहकारी बैंकों का अस्तित्व ही खतरे में डाल दिया है. इससे किसानों को भयंकर कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है. क्षेत्र के किसानों का खाता अधिकांशतः गांव-देहात के सहकारी बैंकों में ही होता है, लेकिन वे बैंक में नोट नहीं बदल सकते. गांवों से दूर शहरों में जाकर बड़े बैंकों में पैसा जमा कराना किसानों के लिए बड़ा जोखिम भरा काम होता है. सहकारी बैंकों का गठन ही किसानों व ग्रामीण जनता की सुविधा के लिए किया गया था, लेकिन केंद्र सरकार के इस फैसले से इन ग्रामीण बैंकों के अस्तित्व पर ही प्रश्नचिन्ह लग गया है. अभी रबी की फसल बुआई का समय है. किसान को फसल लगाने के लिए बीज व खाद आदि के लिए पैसों की जरूरत है, लेकिन केंद्र सरकार के धन निकासी पर रोक लगाने से किसान के सामने यह संकट खड़ा हो गया है कि वह आखिर वह फसल की बुआई बिना बीज व खाद कैसे करे. शिवपाल ने कहा कि हरियाणा के सहकारी बैंकों को पुराने नोटों को जमा करने व नये नोट निकालने की अनुमति दी गई, क्योंकि वहां भाजपा की सरकार है. लेकिन यूपी के सहकारी बैंकों को मनाही कर दी गई. केंद्र ने राजनीतिक भेदभाव में उत्तर प्रदेश के किसानों के साथ अन्याय किया है. केंद्र सरकार का यह फैसला यूपी के किसानों पर कुठाराघात है. ■

www.kamalmorarka.com

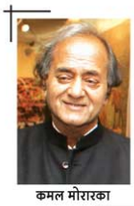

कमल मोरारका

नोटबंदी से कालाधन ख़त्म नहीं होगा

कुछ लोग आर्थिक आपातकाल की बात कर रहे हैं. लेकिन मैं नहीं समझता कि वो दौर अभी आया है. यह क़दम उठाते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि आज की रात के बाद ये नोट कागज़ के टुकड़े बन जायेंगे. ये ख़ुद एक ख़तरनाक बयान था. कम आमदनी वाला व्यक्ति सरकार में विश्वास रखता है और यदि सरकार ख़ुद ये कहे कि ये नोट किसी काम के नहीं, तो सरकारी बॉन्ड का क्या, सरकारी गारंटी का क्या, प्रोविडेंट फण्ड का क्या या सारा पैसा सरकार का पैसा है. कोई काम करने के लिए सरकार का स्टेक हटा देना बुद्धिमतापूर्ण काम नहीं है. बहरहाल, यह एक चुनी हुई सरकार है, उनको शासन करने का अधिकार है. विपक्षी पार्टियां बेशक अपनी आवाज़ उठा रही हैं, लेकिन मैं आशा करता हूं कि लोग चाक-चौबंद रहेंगे. उत्तर प्रदेश के चुनाव पर इसका क्या असर पड़ेगा यह अभी कहना बड़ा मुश्किल है. लेकिन जो सूचनाएं आ रही हैं, उस लिहाज़ से किसान बहुत दु:खी हैं, क्योंकि उनके खेत की पैदावार बिक नहीं सकती. हमें आशा करनी चाहिए कि देशहित में चीज़ें ठीक हो जायेंगी.

पांच सौ और एक हज़ार के नोटों को बंद करने की घोषणा देश के सामने अचानक आई. बिना इस विरोधाभास के डर के कि यह ये क़दम सफल होता है या असफल. यह कहा जा सकता है कि यह बिना किसी तैयारी के उठाया गया क़दम था. 19 जुलाई, 1969 को श्रीमती इंदिरा गांधी ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था. ज़ाहिर है इसके लिए कुछ क़दम उठाये गए होंगे, जिसने हर किसी को हैरान किया होगा. इसमें कोई झगड़ा नहीं है. लेकिन आंतरिक तौर पर सरकार को तैयार रहना चाहिए. श्रीमती गांधी ने बहुत होशियारी के साथ यह काम किया. जिस दिन बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, प्राइवेट सेक्टर द्वारा नियुक्त किये गए मौजूदा चेयरमैन को उसी दिन सरकार की तरफ से बैंकों का संरक्षक बना दिया गया. लिहाज़ा बैंकों के कार्यों में एक दिन की भी अव्यवस्था नहीं हुई. केवल स्वामित्व बदला, बाकी सब कुछ वही रहा जो था. ग्राहकों को किसी तरह की असुविधा में नहीं डाला गया. बेशक इस पर बहस की जा सकती है कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण ठीक नहीं था.

उसी तरह नोटबंदी पर भी बहस की जा सकती है कि यह क़दम सफल होगा, असफल होगा या इसके परिणाम क्या होंगे. लेकिन जो वास्तविक बिन्दु है, वो ये हैं कि प्रधानमंत्री ने इस संबंध में तीन चीज़ों पर निशाना लगाने की बात की हैं. ये तीन चीज़ें हैं, आतंकवाद, जाली नोट और कालाधन. ये कहा जा सकता है कि इस से आतंकवाद और जाली नोटों पर निशाना लगाया जा सकता है, लेकिन कालाधन इस छोटे से कदम से ख़त्म नहीं किया जा सकता. कालाधन इस देश की ऐसी समस्या है, जिससे देश की हर सरकार निपटने की कोशिश करती रही है. यह क़दम अधिक से अधिक कालेधन के स्टॉक को (यदि कोई स्टॉक है या जहां कहीं भी है) फ्रीज़ कर सकता है. लेकिन यह बहुत मामूली है. देश में कालेधन का असल स्टॉक रियल एस्टेट और सोने में है. कालेधन के जो दूसरे स्त्रोत हैं, वो ये हैं कि जिन लोगों के पास बहुत अधिक कालाधन है वहां एक बहाव है. रोज़ाना काला सफ़ेद होता है और सफ़ेद काला. ऐसे लोग हैं, जिनके पास कालाधन नहीं है, लेकिन उन्हें ब्लैक मनी में अदाएगी करनी पड़ती है. वो अपने व्हाइट को ब्लैक में परिवर्तित करने के बाद अदाएगी करते हैं. दूसरी तरफ कुछ लोग भी हैं, जो अपने ब्लैक को व्हाईट में बदल कर अदाएगी करते हैं. यह लगातार चलने वाला सिलसिला है, जिसके लिए बुद्धिमत्तापूर्ण सोच और कर अधिकारियों द्वारा कारगर उपाय की आवश्यकता है. नोटबंदी (जिसने आयकर अधिकारियों को भी अचंभीत कर दिया) कालेधन की समस्या का केवल दस फीसद समाधान है. इसका परिणाम क्या होगा हमें आने वाले महीनों और सालों में पता चलेगा. बिना किसी विवाद के फिलहाल यह कहा जा सकता है कि यह एक नाटकीय लेकिन कम प्रभावकारी क़दम है. अगर कोई यह समझता है कि उन्होंने देश को बदल दिया है या बहुत क्रांतिकारी काम किया है तो यह एकदम गलत है.

यह सच है कि उन्होंने देश को अचंभित किया है, शायद उनकी ख़ुद की पार्टी को भी इसकी ख़बर नहीं थी, हालांकि कुछ आरोप हैं, जो इसके विपरीत हैं. लेकिन इस तरह के एकमात्र क़दम से समस्या का समाधान कर लेना संभव नहीं है. इसका दूसरा पहलू यह है कि छोटे, मझोले, निम्न मध्यम वर्ग को पूरी तरह से परेशानी में डाल दिया गया है. क्योंकि आजकल एक हज़ार रुपया बहुत बड़ी रक़म नहीं है और पांच सौ रुपया तो कुछ भी नहीं है. हर किसी के पास 500 रुपये का नोट

हैं. ख़ुद सरकारी आंकड़े कहते हैं कि देश का 86 प्रतिशत मूल्य का रुपया, 500 और 1000 रुपये के नोट के रूप में है. आपने अपने क़दम से क्या किया है? आपने 85 प्रतिशत करेंसी को देश से बाहर कर दिया है. यह बहुत ही नासमझी भरा क़दम है. अगर आप को यह करना ही था तो इसे केवल 1000 तक सिमित रखा जाता और फिर उसका नतीजा देखना चाहिए था. अगर नतीजा अच्छा होता तो आगे 500 रूपये के नोट के साथ करते, किसी को कोई परेशानी नहीं होती. आपके कदम से कम आमदनी वाला व्यक्ति जो लाइन में खड़ा है गुस्से में है. वह क़तार में कोई सरकारी लाभ लेने के लिए नहीं खड़ा है. वह अपना पैसा बदलने के लिए घंटों तक कतार में खड़ा है और इससे बड़ क्र यह कहा जा रहा है कि उनकी उंगली पर स्याही लगाई जायेगी, ताकि वो दुबारा क़तार में न खड़े हो सकें. इसका मतलब यह है कि वह अपना पैसा केवल एक बार ही निकाल सकता है या बिल्कुल ही नहीं निकाल सकता. यह किस तरह की नासमझी वाला, मूर्खतापूर्ण फैसला है?

मैं सरकार के इस क़दम से हैरान हूं, क्योंकि वो बेढंगे हैं. ढाई साल के दौरान उन्होंने ऐसे क़दम उठाए जो अधिक नाटकीय थे और उनमें दुरगामी परिणामों के बारे में नहीं सोचा गया है. रक्षा मंत्री जिस तरह की बातें कर रहे हैं, वो उदाहरण है इस बात का कि इस स्तर पर भी मसख़रापन चल रहा है. फिलहाल उन्होंने यह कहा है कि हमें परमाणु हथियारों के फर्स्ट-यूज़ ऑप्शन को नहीं छोड़ना चाहिए. जबकि हर सभ्य देश ने अपने फर्स्ट-यूज़ ऑप्शन को त्याग दिया है. उसके फ़ौरन बाद रक्षा मंत्रालय को एक सर्कुलर जारी कर के यह कहना पड़ा कि यह उनके व्यक्तिगत विचार हैं, यह सरकार के विचार नहीं. क्या आप विश्वास कर सकते हैं, अगर कोई अधिकारी व्यक्तिगत रूप से ऐसे बात करे तो उसे समझा जा सकता है, लेकिन यदि मंत्री कहें और फिर कहा जाए कि यह सरकार के विचार नहीं हैं, तो फिर सरकार कौन है? मंत्री ही सरकार है.

अपने असल विषय नोट बंदी की तरफ वापस आते हैं. इसके असली परिणाम को पता लगाने में समय लगेगा, लेकिन फिलहाल गुस्सा है. यह गुस्सा आम लोगों में है और यहां तक कि बीजेपी के समर्थकों में है, बीजेपी के कार्यकर्ताओं में है, मोदी के पक्के समर्थकों में है. प्रधानमंत्री ख़ुद कह रहे हैं कि साधारण आदमी चैन की नींद सो रहा है और जो भ्रष्टाचारी हैं, वो डरे हुए हैं. लेकिन बदकिस्मती से मामला ठीक इसके उलट है. भ्रष्ट और कालाबाज़ारी करने वाले आराम से सो रहे हैं, यह सोचते हुए कि यह एक मज़ाक है, उन्हें इसकी कोई चिंता ही नहीं. दरअसल, जो कम आमदनी वाले लोग हैं, जिनका कलाधन से कोई लेना-देना नहीं है, वे नहीं सो पा रहे हैं.

बेशक इसे बदला नहीं जा सकता है. यह संभव नहीं है. दरअसल उन्हें 500 के पुराने नोटों को फिर से चलाने के बारे में सोचना चाहिए. लेकिन इस तरह का क़दम उठाना कठिन काम है. यह समय ही बताएगा कि ये क़दम मोदी को आगे ले जाता है या यह चाल उन पर उल्टी पड़ जायेगी. बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि यह चाल उल्टी पड़ जायेगी. बहुत सारे लोग यह कह रहे हैं कि मोदी ने पहला ग़लत फ़ैसला लिया है. लेकिन हमें यह देखने के लिए इंतज़ार करना पड़ेगा.

ताज़ा सूचना के मुताबिक़ अब 4500 की जगह केवल 2000 रुपये के नोट बदले जा सकते हैं. इस दृष्टि से उन्हें इस बात पर विचार करना चाहिए कि क्या 500 रुपये के नोट को एक बार फिर चलन में लाना चाहिए या नहीं. कम आमदनी के लोगों की समस्याओं के समाधान का यह एक तरीक़ा हो सकता है.

यह ख़बर आई है कि स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया ने कई क़र्ज़ों को राईट-ऑफ कर दिया है. उनमें से 1200 करोड़ के लोन विजय माल्या के भी हैं. अब मुझे यह नहीं मालूम कि इस तरह की चीज़ें अख़बारों में कैसे रिपोर्ट होती हैं. बैंकिंग एक गोपनीय मामला है, खाते से राईट-ऑफ का यह मतलब नहीं होता कि उसे माफ़ कर दिया गया. राईट-ऑफ का मतलब होता है, बैलेंस शीट पर एक अधिक इमानदार आंकड़ा दर्ज करना. वो अपने शेयर धारकों को यह बता रहे हैं कि देखिये हो सकता है, यह पैसा वापस न आये. राईट-ऑफ के बजाये यह कहा जाना चाहिए था कि शायद यह पैसा वापस नहीं आएगा. लेकिन यह जो नतीजा निकाला गया है कि क़र्ज़ माफ़ कर दिया गया है, सही नहीं है. बहरहाल, यह सरकार माल्या के समर्थन में नहीं है, लेकिन जो दूसरे नाम हैं, उनको फायदा पहुंचाने के लिए विजय माल्या का नाम सबसे ऊपर कर दिया गया है. हमे मालूम नहीं. यह हमें देखने के लिए इंतजार करना चाहिए.

कुछ लोग आर्थिक आपातकाल की बात कर रहे हैं. लेकिन मैं नहीं समझता कि वो दौर अभी आया है. यह क़दम उठाते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि आज की रात के बाद ये नोट कागज़ के टुकड़े बन जायेंगे. ये ख़ुद एक ख़तरनाक बयान था. कम आमदनी वाला व्यक्ति सरकार में विश्वास रखता है और यदि सरकार ख़ुद ये कहे कि ये नोट किसी काम के नहीं, तो सरकारी बॉन्ड का क्या, सरकारी गारंटी का क्या, प्रोविडेंट फण्ड का क्या या सारा पैसा सरकार का पैसा है. कोई काम करने के लिए सरकार का स्टेक हटा देना बुद्धिमतापूर्ण काम नहीं है. बहरहाल, यह एक चुनी हुई सरकार है, उनको शासन करने का अधिकार है. विपक्षी पार्टियां बेशक अपनी आवाज़ उठा रही हैं, लेकिन मैं आशा करता हूं कि लोग चाक-चौबंद रहेंगे. उत्तर प्रदेश के चुनाव पर इसका क्या असर पड़ेगा यह अभी कहना बड़ा मुश्किल है. लेकिन जो सूचनाएं आ रही हैं, उस लिहाज़ से किसान बहुत दु:खी हैं, क्योंकि उनके खेत की पैदावार बिक नहीं सकती. हमें आशा करनी चाहिए कि देशहित में चीज़ें ठीक हो जायेंगी. ■

feedback@chauthiduniya.com

मत-मतांतर

सरदार पटेल का ख़त गोलवलकर के नाम

नई दिल्ली, 11 सितंबर, 1948
औरंगजेब रोड

भाई श्री गोलवलकर,

आपका ख़त मिला जो आपने 11 अगस्त को भेजा था. जवाहरलाल ने भी मुझे उसी दिन आपका ख़त भेजा था. आप राष्ट्रीय स्वंयसेवक संघ पर मेरे विचार भली-भांति जानते हैं. मैने अपने विचार जयपुर और लखनऊ की सभाओं में भी व्यक्त किए हैं. लोगों ने भी मेरे विचारों का स्वागत किया है. मुझे उम्मीद थी कि आपके लोग भी उनका स्वागत करेंगे, लेकिन ऐसा लगता है मानो उन्हें कोई फर्क ही न पड़ा हो और वो अपने कार्यों में भी किसी तरह का परिवर्तन नहीं कर रहें. इस बात में कोई शक नहीं है कि संघ ने हिंदू समाज की बहुत सेवा की है. जिन क्षेत्रों में मदद की आवश्यक्ता थी उन जगहों पर आपके लोग पहुंचे और श्रेष्ठ काम किया है. मुझे लगता है इस सच को स्वीकारने में किसी को भी आपत्ति नहीं होगी. लेकिन सारी समस्या तब शुरू होती है जब ये ही लोग मुसलमानों से प्रतिशोध लेने के लिए कदम उठाते हैं. उन पर हमले करते हैं. हिंदुओं की मदद करना एक बात है, लेकिन गरीब, असहाय लोगों, महिलाओं और बच्चों पर हमले करना बिल्कुल असहनीय है.

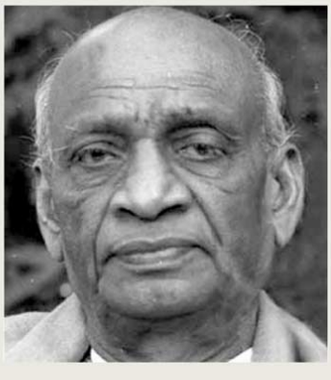

इसके अलावा देश की सत्ताधारी पार्टी कांग्रेस पर आपलोग जिस तरह के हमले करते हैं, उसमें आपके लोग सारी मर्यादाएं, सम्मान को ताक पर रख देते हैं. देश में एक अस्थिरता का माहौल पैदा करने की कोशिश की जा रही है. संघ के लोगों के भाषण में सांप्रदायिकता का जहर भरा होता है. हिंदुओं की रक्षा करने के लिए नफरत फैलाने की भला क्या आवश्यक्ता है? इसी नफरत की लहर के कारण देश ने अपना पिता खो दिया. महात्मा गांधी की हत्या कर दी गई. सरकार या देश की जनता में संघ के लिए सहानुभूति तक नहीं बची है. इन परिस्थितियों में सरकार के लिए संघ के खिलाफ निर्णय लेना अपरिहार्य हो गया था.

राष्ट्रीय स्वंयसेवक संघ पर प्रतिबंध को छह महीने से ज्यादा हो चुके हैं. हमें ये उम्मीद थी कि इस दौरान संघ के लोग सही दिशा में आ जाएंगे. लेकिन जिस तरह की खबरें हमारे पास आ रही हैं, उससे तो यही लगता है जैसे संघ अपनी नफरत की राजनीति से पीछे हटना ही नहीं चाहता. मैं एक बार पुन: आपसे आग्रह करूंगा कि आप मेरे जयपुर और लखनऊ में कही गई बात पर ध्यान दें. मुझे पूरी उम्मीद है कि देश को आगे बढ़ाने में आपका संगठन योगदान दे सकता है, बशर्ते वह सही रास्ते पर चले. आप भी ये अवश्य समझते होंगे कि देश एक मुश्किल दौर से गुजर रहा है. इस समय देश भर के लोगों का चाहे वो किसी भी पद, जाति, स्थान या संगठन में हों, उनका कर्तव्य बनता है कि वे देशहित में काम करे. इस कठिन समय में पुराने झगड़ों या दलगत राजनीति के लिए कोई स्थान नहीं है. मैं इस बात पर आश्वस्त हूं कि संघ के लोग देशहित में काम कांग्रेस के साथ मिलकर ही कर पाएंगे न कि हमसे लड़कर. मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आपको रिहा कर दिया गया है. मुझे उम्मीद है कि आप सही फैसला लेंगे. आप पर लगे प्रतिबंधों की वजह से मैं संयुक्त प्रांत सरकार के जरिए आपसे संवाद कर रहा हूं. पत्र मिलते ही उत्तर देने की कोशिश करूंगा

आपका
वल्लभ भाई पटेल

जब तोप मुक़ाबिल हो

संतोष भारतीय

सरकार ही क़ानून तोड़ेगी तो क़ानून की रक्षा कौन करेगा

ये शिकायत नहीं है, ये गुस्सा भी नहीं है और इसके आगे कहें, तो अब कोई तकलीफ़ भी नहीं है, क्योंकि ऐसा लगता है कि दर्द हद से ज्यादा बढ़ गया है. सिर्फ़ कुछ शंकाएं हैं वो शंकाएं प्रधानमंत्री जी से कह नहीं सकते क्योंकि प्रधानमंत्री जी को लोगों का ख़त मिलना पसंद नहीं आता. वो कहते भी हैं कि कुछ लोग मुझे ख़त लिखने की हिम्मत कर रहे हैं. उनके सलाहकार इस देश को ज्यादा जानते हैं. भारतीय जनता पार्टी के सांसद या कार्यकर्ता या अब तो मीनाक्षी लेखी का नाम ले सकते हैं. अगर उनसे ही प्रधानमंत्री अपने उठाए क़दमों के बारे में प्रतिक्रिया जान लेते कि जनता क्या सोच रही है, तो भी हमें थोड़ा सुकून मिलता. लेकिन शायद उनका भी संवाद प्रधानमंत्री जी के साथ नहीं है. इसलिए चलिए आपस में ही कुछ बातें कर लेते हैं.

500 रुपये और 2000 रुपये के नये नोट रिज़र्व बैंक द्वारा छपाई के बाद बाज़ार में आ गये हैं. उन नोटों का डिज़ाइन देखकर लगता है कि ये ऐसे नोट हैं जिनकी नक़ल नहीं हो सकती, जिन्हें कहीं छापा नहीं जा सकता, या इनके डिज़ाइन अद्भुत हैं. पर नोट देखकर अधिकांश लोगों का कहना है कि इसकी डिज़ाइन बिल्कुल बाज़ार में मुफ्त में दिये जा रहे चुर्ण वाले नोटों की तरह है. ये नोटों का अपमान करने के लिए नहीं कह रहा हूं. मैं सिर्फ़ ये कह रहा हूं कि जिन लोगों ने भी डिज़ाइन को पास किया वो कितने बड़े बुद्धिमान हैं. इस नोट पर सरकार के विज्ञापन हैं, जो ग़ैर-क़ानूनी हैं. क्योंकि क़ानूनन किसी भी करेंसी के ऊपर किसी तरह का विज्ञापन नहीं हो सकता. यहां तक कि नोट के ऊपर अपना नाम लिखना भी ग़ैर-क़ानूनी है. लेकिन सरकार ने अपने विज्ञापन किये, वो सरकार जाने, क्योंकि जब सरकार ही क़ानून तोड़ेगी तो क़ानून की रक्षा कौन करेगा. इसे तो हमारे देश को चला रहा ईश्वर ही जाने. लेकिन उसमें हिंदी ग़लत है, मराठी ग़लत है, उर्दू ग़लत है. दो हज़ार रुपये की इबारत तीनों भाषाओं में ग़लत छपी है. इसलिए हमने कहा कि जिन्होंने इस डिज़ाइन को अंतिम रूप से पास किया वो महान बुद्धिमान और महान समझदार लोग हैं. ये नोट जब हाथ में आया इसका रंग उतरने लगा. हमने अपने दफ्तर में 2000 रुपये का नोट बैंक से मंगवाया, रूई हल्की गीली की और नोट के ऊपर दो बार घुमाया, नोट की स्याही छूटने लगी. वित्त सचिव टेलीविज़न पर आकर के कहते हैं कि जिन नोटों की स्याही छूटती है, वो नोट सही हैं और जिन नोटों की स्याही नहीं छूटती है, वो गलत हैं. मजे की बात, इसके चौबीस घंटे बाद वित्त मंत्रालय ये बयान देता है कि जिन नोटों की स्याही छूट रही है वो ग़लत नोट हैं या नक़ली नोट हैं और जिनकी स्याही नहीं छूटती है वो असली नोट हैं. हम किसे सही माने. जो नोट हमारे पास आया वो तो बैंक ने दिया. और अधिकांश लोगों के पास वही नोट है जो बैंक दे रहे हैं. उनकी स्याही छूट रही है. क्या हम ये माने कि ये सारे नोट नक़ली हैं या ये सारे नोट असली हैं. अगर ये नोट असली हैं, तो ये कैसी डिज़ाइन है कि जो तीन महीने से नोट छप रहे थे, वो सूख नहीं भी पाए और जब वो उपभोक्ता के हाथ में या जनता के हाथ में पहुंचे तो अपनी स्याही छोड़ रहे हैं. हिंदुस्तान में अधिकांश लोग गर्मी से परेशान होते हैं, उन्हें पसीना निकलता है, उनकी बनियान यहां तक कि क़मीज़ भी गीली भी हो जाती है. उसमें रखे हुए ये सारे नोट अगर गीले होकर स्याही छोड़ दें और एक दूसरे के ऊपर स्याही ओवरलैप कर जाए, तो क्या ये नोट बाज़ार में चलेंगे. अब न ये शिकायत है न तकलीफ़ है, ये सिर्फ़ आपस में बातचीत करने का एक माध्यम है. क्योंकि हमें तो कचोट हो रही है. और वो कचोट इसलिए हो रही है कि इस देश के अधिकांश लोगों की ये चिंता है. अब सवाल खड़ा होता है कि क्या ये नोट दोबारा बदले जाएंगे. अगर दोबारा बदले जाएंगे तो फिर वही अफ़रा तफ़री होगी, तो क्या सरकार चलाने वाले मुखिया जिन्होंने बहुत गोपनीय रखकर ये सारा काम किया, क्या उन्हें इन सवालों के ऊपर सोचने का अभी समय मिल पायेगा? शायद नहीं मिल पायेगा, क्योंकि ये सरकार जो कर देती है वही आख़िरी होता है. उससे वो पीछे नहीं आती. भले ही कितना भी बड़ा नुक़सान हो जाये. सरकार की तारीफ़ करनी चाहिए.

हिंदुस्तान के 60 प्रतिशत लोग खेती के ऊपर जी रहे हैं और 25 प्रतिशत तो सीधा खेती के पर ही निर्भर हैं. गांव से बैंक छह से आठ किलोमीटर दूर हैं. उस गांव को छोड़ दें, जहां पर बैंक की शाखा है और किसान का परंपरागत अभ्यास बैंक में पैसे रखने का, रोज़ जाकर जमा कराने का नहीं है, वो महीने दो महीने में एक बार जाता है अपना पैसा जमा करा देता है या जब क़र्ज़ लेने जाना होता है तो किसान क्रेडिट कार्ड से पैसे ले लेता है. क्या वो किसान जिसकी फ़सल खेत में पड़ी हुई है और नहीं बिक रही है या ग़लती से बिक जाये और वो पैसा लेकर जाये और उसका रंग छूट जाये तो किसान क्या करे. इससे भी बड़ी समस्या किसान की धान की फ़सल के बिकने या अभी जो फ़सल बोनी है, जिसके लिये खाद और बीज चाहिए

उसके लिए वो पैसे कहां से लाये. फ़सल बोने का एक समय होता है और उस समय अगर किसान के पास कैश नहीं हो तो वो चीज़ें ख़रीद नहीं सकता और अगर ख़रीद नहीं पायेगा तो खेत में बोएगा क्या? सरकार चलाने वाली व्यवस्था को इस बात का एहसास नहीं है कि इतने सालों से खेती की ज्यादातर ख़रीद और बिक्री, खेती के फ़सल की ख़रीद और बिक्री नक़द होती है. व्यापारी या आढ़ती किसान से जब ख़रीदता है तो उसे नक़द पैसा देता है. या फ़सल कटने से पहले बयाना भी वो नक़द ही देता है. किसान उस पैसे को अपने घर में रखता है. पूरा एग्रीकल्चर सेक्टर इस समय पशोपेश में है क्या करे? उसकी चीख़ सुनने वाला न उसका सांसद है न उसका विधायक है और न मीडिया के लोग. खुद़रा दुकानदार का सारा व्यापार कैस के उपर नक़द लेन-देन पर चलता है, लेकिन कैश नहीं होने की वजह से सप्लाई लाईन कमज़ोर हो गयी. पर हम ये मान भी लें कि ये सब एक या दो महीने में ठीक हो जायेगा तो भी जो मैन्यूफैक्चरिंग डिफेक्ट है उस

> एक और चिंताजनक बात कि क्या वो लोग जिनके ऊपर कालेधन चलाने का आरोप है, जिनके खाते विदेशी बैंकों में हैं, जिनको लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव जीता. क्योंकि उसने कहा था कि जब ये पैसा आएगा तो हरेक के खाते में 15 लाख रुपये जमा हो जायेंगे. या वो लोग देश में जो कालेधन की सत्ता के प्रधानमंत्री और वित्तमंत्री हैं क्या उन्हें कोई फ़र्क़ इस नोटबंदी के फ़ैसले से पड़ा है. वो तो कहीं चिंतित नहीं दिखाई दिये और फिल्मी दुनिया के लोग जिनके बारे में माना जाता है कि वो जितना चेक से पैसा लेते हैं उससे ज्यादा ब्लैक में लेते हैं. वो लोग इस क़दम की तारीफ़ कर रहे हैं. दरअसल, हर वो आदमी इस कदम की तारीफ़ कर रहा है, चाहे वो उद्योगपति हों या फिल्म स्टार हों या क्रिकेटर हों जिनके उपर आमतौर पर ये संदेह है कि ब्लैकमनी का व्यापार यही करते हैं और यही उस अर्थव्यवस्था के काली अर्थव्यवस्था के चलन के ज़िम्मेदार लोग हैं, वो सब तारीफ़ कर रहे हैं.

डिफेक्ट का क्या करेंगे. और अब पहली बार किसान के ऊपर इनकम टैक्स लगने का ख़तरा संकेतों में आ चुका है. अब तक खेती से उपजी आमदनी या किसान की किसी भी तरीक़े से हुई आमदनी टैक्स फ्री थी. पर अब उनके खातों के ऊपर नज़र रखी जा रही है कि अगर वो अपने किसी रिश्तेदार का पैसा या किसी का पैसा अपने खाते में डालते हैं, तो इनकम टैक्स उनसे टैक्स भी वसूल सकता है और जुर्माना भी लगा सकता है. सरकार के नोटों का हाल ये है कि अब तक 4000 या 4500 के पुराने नोट बदले जा रहे थे. अब सरकार ने घोषणा की है कि सिर्फ दो हज़ार रुपये ही बदले जा सकेंगे. ये सरकार की महान बुद्धिमानी के नमूने हैं. 100 करोड़, 80 करोड़, 60 करोड़ जिनका पैसा व्हाईट है, वो भी अपना पैसा बैंक से नहीं निकाल पायेंगे, न निकाल पा रहे हैं. क्योंकि बैंक के पास नोट ही नहीं हैं. और दूसरी तरफ रोज़मर्रा के खाने-पीने के लिए जो लोग कल तक 4500 रुपये हफ्ते में बदल रहे थे, अब वो सिर्फ 2000 रुपये बदल पायेंगे. सरकार निश्चिंत है कि उसने काले धन के ऊपर काबू पा लिया है.

सरकार की ये निश्चिंतता कि उसने काले धन के उपर क़ाबू पा लिया है, हमें भी अच्छी लग रही है, क्योंकि टेलीविज़न चैनलों ने और ख़ासकर सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री के या सरकार के किसी भी कदम की तारीफ़ करने वाली दो या तीन हज़ार लोगों की सेना ने माहौल ऐसा बना दिया है कि अगर आप नोट बदली को कालेधन के ख़िलाफ़ सबसे बड़ा क़दम बताकर तारीफ़ नहीं करते तो आप कालेधन के समर्थक हैं. ये ठीक उसी तरह की बात है, जैसे एक महीने पहले अगर आप पाकिस्तान को गाली न दें तो आप देशभक्त नहीं हैं. अगर आप युद्ध का विरोध करें तो आप देशद्रोही हैं. लेकिन नोटबंदी के इस माहौल में जब आदमी अपनी ज़िंदगी की एक अहम लड़ाई लड़ रहा है, अचानक पाकिस्तान के साथ तनाव समाप्त हो गया है. कश्मीर का तनाव समाप्त हो गया है. रक्षामंत्री कहते हैं कि कश्मीर में पत्थर नहीं चल रहे हैं. ये रक्षामंत्री के लिए ख़ुशी की बात है. लेकिन कश्मीर का दर्द समाप्त हो गया इसके उपर रक्षामंत्री कुछ नहीं बोल रहे हैं. ये भी कह देना चाहिए कि कश्मीर की सारी समस्याएं हल हो गई हैं. अब वहां के लोगों के मन में भारतीय क़दमों को, भारत सरकार द्वारा उठाये गये क़दमों को समर्थन ही समर्थन है. लेकिन एक अच्छी बात है कि देश जिस युद्धोन्माद की तरफ बढ़ रहा था और जिसमें टलीविज़न चैनल सबसे बड़ा योगदान कर रहे थे. सोशल मीडिया में तीन हज़ार लोग जो कहीं से तनख्वाह पाते हैं और जो सरकार द्वारा उठाये गये हर क़दम को अतिरेक की सीमा तक ले जाते हैं, उन लोगों द्वारा बढ़ाया गया युद्धोन्माद अचानक आठ तारीख़ से ख़त्म हो गया है. ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान की सीमा पर सब शांति है और अब हमारा कोई सिपाही कहीं नहीं मर रहा.

इतना ही नहीं, हमारे विकास के पचास से ज्यादा वायदे सरकार ने किये थे. स्वच्छ भारत से लेकर के नोटबंदी तक ऐसा लग रहा है कि वो सब अपनी पूरी गति से चल रहे हैं. और हमारे दरवाज़े पर अच्छे दिन की ट्रेन आशाओं और ख़ुशियों से भरे हुये बैग जल्दी उतारने वाली है. इन सारी बातें जिनका ज़िक्र हम कर रहे हैं, इस आशा के साथ कर रहे हैं कि सरकार द्वारा करेंसी बदलने का अति बुद्धिमत्तापूर्ण फ़ैसला लिया गया, उस फ़ैसले के परिणामस्वरूप कहीं हम महंगाई या मंदी की चपेट में तो नहीं आ जाएंगे. दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं. लग ऐसा रहा है कि सरकार संसद में भी थोड़ी सी कलाबाज़ी दिखा रही है. इस दौरान अचानक एक बैंक ने जिसका नाम स्टेट बैंक है, सात हजार करोड़ से ज्यादा का उन लोगों का क़र्ज़ माफ़ कर दिया है जिनके बारे में ये माना जाता है कि वो देश के बड़े व्यापारी हैं और बैंकों का सारा पैसा जो भी जनता का पैसा है, हड़प चुके हैं. अगर सारे बैंकों का ये फिगर आएगा तो ये पैसा 60 हजार करोड़ से ज्यादा का निकलेगा.

आख़िर में एक और चिंताजनक बात कि क्या वो लोग जिनके ऊपर कालेधन चलाने का आरोप है, जिनके खाते विदेशी बैंकों में हैं, जिनको लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव जीता. क्योंकि उसने कहा था कि जब ये पैसा आएगा तो हरेक के खाते में 15 लाख रुपये जमा हो जायेंगे. या वो लोग देश में जो कालेधन की सत्ता के प्रधानमंत्री और वित्तमंत्री हैं क्या उन्हें कोई फ़र्क़ इस नोटबंदी के फ़ैसले से पड़ा है. वो तो कहीं चिंतित नहीं दिखाई दिये और फिल्मी दुनिया के लोग जिनके बारे में माना जाता है कि वो जितना चेक से पैसा लेते हैं उससे ज्यादा ब्लैक में लेते हैं. वो लोग इस क़दम की तारीफ़ कर रहे हैं. दरअसल, हर वो आदमी इस कदम की तारीफ़ कर रहा है, चाहे वो उद्योगपति हों या फिल्म स्टार हों या क्रिकेटर हों जिनके उपर आमतौर पर ये संदेह है कि ब्लैकमनी का व्यापार यही करते हैं और यही उस अर्थव्यवस्था के काली अर्थव्यवस्था के चलन के ज़िम्मेदार लोग हैं, वो सब तारीफ़ कर रहे हैं. और जो लाईन में लगा हुआ है जो मुश्किल से दो हज़ार, पांच हज़ार, दस हज़ार रुपये अपनी मुसिबत के वक्त के लिए घर में रखता है वो नोट बदलने के लिए लाईन में खड़ा है, लेकिन उसका नोट नहीं बदला जा रहा है. और ऊपर से अब उसके ऊपर ये संदेह हो गया कि असली कालाधन तो ये है, जो लोगों ने अपने घर में हारी-बिमारी, आना-जाना, लेन-देन, बच्चों की चिंताओं को दूर करने के लिए रखा हुआ था, वो कालेधन का फेस हो गया. और तभी शायद ये कहा गया कि जो चोर हैं, वो लाइनों में खड़े हैं और नोट बदलवा रहे हैं. ये चिंताएं हैं. इन चिंताओं का न सोशल मीडिया पर भड़ैती करने वाले लोगों के ऊपर असर पड़ेगा और न ही टेलीविज़न चैनल पर आकर सवाल और चिंता को मोड़ने में माहिर टेलीविज़न के पत्रकारों के ऊपर इन चिंताओं का असर पड़ेगा, क्योंकि दरअसल ये सब कालेधन की दुनिया के लठ्ठबाज़ हैं, लठैत हैं. इसका फ़र्क़ तो इस देश के किसान पर पड़ेगा, इस देश के मज़दूर पर पड़ेगा, उसका पैसा भी नहीं बदला जा रहा है और महंगाई की मार भी उसे ही झेलनी पड़ेगी. हमारी ये चिंताएं सच न हो बस ये ईश्वर से प्रार्थना है, अगर वो कहीं है तो. ■

editor@chauthiduniya.com

www.vastuvihar.org
वास्तु विहार®
एक विश्वस्तरीय टाउनशिप
AN ISO : 9001 : 2008 : 14001 : 18001 : 2007 COMPANY

बिहार, झारखंड, बंगाल, उड़ीसा एवं पूर्वी उत्तर प्रदेश के 63 शहरों में 117 आवासीय परियोजनाओं की श्रृंखला

Call : 95340 95340

तकरार छोड़ संवारनी होगी कोसी की सूरत

राजेश सिन्हा

बिहार की सूरत व सेहत संवारने का सेहरा चाहे जिसके सिर बंधे, लेकिन कोसी की किस्मत नदियां ही लिखती आयी हैं और शायद लिखती रहेंगी. कोसी की सेहत व सूरत विकृति के सवाल पर सियासी पारा न केवल चढ़ता-उतरता रहा है, बल्कि कुसहा त्रासदी के लगभग आठ वर्ष बाद अब लोगों के मुंह से यह बरबस निकलने भी लगा है कि केंद्र और राज्य सरकार के तकरार में कोसी का बंटाधार हो रहा है. हालांकि कुसहा त्रासदी के समय केंद्र में न ही भाजपा की सरकार थी और न ही नरेन्द्र मोदी प्रधानमंत्री की कुर्सी पर विराजमान थे. कांग्रेसनीत मनमोहन सिंह की सरकार के द्वारा कुसहा त्रासदी को राष्ट्रीय आपदा घोषित करते हुए कोसी पुर्नवास योजना के तहत कोसी के पुर्ननिर्माण की बात कही गई थी, जबकि बिहार के मुखिया नीतीश कुमार के द्वारा पहले से सुंदर कोसी निर्माण का सपना दिखाया गया था. नरेन्द्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद केन्द्र तथा राज्य सरकार के बीच कोसी नवनिर्माण के सवाल पर आरोप-प्रत्यारोप के आदान-प्रदान का सियासी खेल इस कदर चलता रहा कि कोसी नवनिर्माण का वास्तविक मसला धुंधला पड़ गया. न तो आशियाना गंवा चुके परिवारों के पुर्नवास की आस पूरी हो चुकी और न ही सुंदर कोसी का सपना ही साकार हो सका. यह बात अलग है कि कुसहा त्रासदी के पूर्व ही मोदी-नीकु के बीच खिंची राजनीतिक तलवार कोसी त्रासदी के बाद पूरी तरह से म्यान से बाहर आ गयी. कभी नरेन्द्र मोदी का खेमा नीतीश सरकार पर भारी पड़ा तो कभी नीतीश की टोली मोदी खेमे को आंख दिखाती नजर आई. कोसी की उपेक्षा के मामले में वास्तविक गुनाहगार कौन है, यह तो एक-दूसरे के सिर आरोप का ठीकरा फोड़ने वाले सियासतदान ही जानें. इससे बुरी स्थिति और क्या हो सकती है कि कोसी त्रासदी में अपनों को गंवा चुके कई परिवार के लोग मुआवजे की राशि से अब भी वंचित हैं. लापता हुए लगभग 3,500 लोगों में से अधिकांश का अब तक पता नहीं चल सका है. लापता लोगों के परिजन मुआवजे के लिए अब भी दर-दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं.

सरकारी आंकड़ों पर ही भरोसा करें तो कोसी त्रासदी में सुपौल, अररिया, पूर्णियां, मधेपुरा व सहरसा जिले के 412 पंचायतों के 993 गांव प्रभावित हुए और 352 लोगों को जान से हाथ धोना पड़ा था. तटबंधों के बीच कैद कोसी इस कदर कैद से निकली कि नेपाल में कुसहा के पास तटबंध को तोड़कर लाखों लोगों को तबाह कर दिया. दूधारू पशुओं सहित लगभग बारह हजार पशु पानी में बह गए, जबकि विभिन्न गांव के लगभग 2,36,632 आशियाने जमींदोज हो गए. 1100 पुल व कलवर्ट टूट गए और लगभग 1800 किमी रोड क्षतिग्रस्त हो गए. इस आपदा में अपना सब कुछ गंवाने वालों की हालात का अंदाजा खुद-ब-खुद लगाया जा सकता है. कहने को तो सभी सूचीबद्ध प्रभावित परिवारों के बीच मुआवजे की राशि का वितरण कर दिया गया है, लेकिन कई परिवारों के लोग अब भी मुआवजे के लिए अधिकारियों के चौखट का चक्कर लगाने को विवश हैं. प्रशासकीय नाकामी के कारण त्रासदी का दंश झेलने को विवश कई किसान, जमीन खो देने का दर्द सुनाते फिर रहे हैं, लेकिन आठ वर्षों से कई प्रभावित किसानों की फरियाद नक्कारखाने में तूती की आवाज साबित हो रही है. कहा जाता है कि बाढ़ के बाद पुर्नवास की प्रक्रिया इतनी मंथरगति से चलती रही कि यह धीरे-धीरे जटिल हो गई और लोग इसकी हकीकत जान कर अपनी किस्मत अपने दम पर संवारने की कोशिश में लग गए. बाढ़ के दौरान अपना सब कुछ गंवा चुके कई परिवारों के लोग दो जुन की रोटी की तलाश में दूसरे राज्यों का रुख करने लगे, जबकि नौकरशाहों व पंचायत प्रतिनिधियों की मिलीभगत से बिचौलियों ने जरूरतमंदों को मिलने वाली सहायता राशि को हड़प लिया. चार चरणों में संपन्न होने वाला पुर्ननिर्माण कार्य दूसरा चरण पूरा होने से पहले ही बंद होने की कगार पर पहुंच गया है.

दूसरे चरण की योजना के तहत नदी की मुख्यधारा में आकर विस्थापित हुए नदी के समीप स्थित गांव के लोगों को पुर्नवासित किया जाना था. बाढ़ के दौरान खेतों में जमा हुए बालू को निकालने का मसला भी जमींदोज होकर रह गया. कोसी विकास के नाम पर विश्व बैंक से दोबारा कर्ज लेकर कोसी बेसिन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत कोसी के नवनिर्माण की बात तो कही जा रही है, लेकिन पूर्व की योजनाओं का हश्र देखकर लोगों को विश्वास नहीं हो रहा कि कोसी का नवनिर्माण संभव हो सकेगा.

कोसी त्रासदी में बर्बाद हो चुके लोगों की जिंदगी संवारने के नाम पर विश्व बैंक से 220 मिलियन डॉलर का कर्ज भी लिया गया. लेकिन पूर्णिया, अररिया, सहरसा और सुपौल के प्रभावित परिवारों की जिंदगी संवर नहीं सकी. कहा जाता है कि केन्द्र तथा राज्य सरकार के बीच चली तकरार के कारण केन्द्र सरकार के द्वारा पुर्नवास के नाम पर मुंह मोड़ लिया गया. राज्य सरकार ने बिहार आपदा पुर्नवास एवं पुर्नवास सोसाइटी नामक अलग संस्था का गठन किया. विकास आयुक्त को इसका अध्यक्ष बनाया गया. विश्व बैंक से बाढ़ के दौरान सूचीबद्ध किए गए 2,36632 जमींदोज घरों के पुर्ननिर्माण का कार्य बीते 2010 के 31 जनवरी से शुरू किया गया लेकिन चार चरणों में सम्पन्न होने वाला यह कार्य दो चरण समाप्त होने से पहले ही अटक गया. यह बात अलग है कि कोसी बेसिन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के नाम पर फिर से विश्व बैंक से 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर बतौर कर्ज मिला है. लेकिन दुर्भाग्यवश कोसी त्रासदी के शिकार लोगों की जिंदगी संवारने के नाम पर इस योजना में कुछ नहीं है. वैसे योजना विकास विभाग के द्वारा पहले चरण में केवल 1,57,428 घरों के पुर्ननिर्माण का लक्ष्य रखा गया था. हास्यास्पद स्थिति तब हो गई जब प्रभावित घरों के आंकड़ों को बदलते हुए महज एक लाख घरों को ही पहले चरण में बनाने का निर्णय लिया गया. लेकिन वर्ष 2014 आते-आते लक्ष्य में कटौती हो गयी और महज 66 हजार 203 घर ही सूची में अपनी जगह कायम रख पाए. कोसी नवनिर्माण मंच के संस्थापक महेन्द्र यादव की अगर मानें तो विश्व बैंक से दो-दो बार कर्ज लिए जाने के आठ वर्ष बाद भी कोसी विकास के नाम पर नाटक होता रहा. सुपौल, मधेपुरा, सहरसा, पूर्णिया, अररिया सहित कुछ अन्य इलाकों में कोसी त्रासदी के कारण कोसी के रौद्ररूप का सामना लोगों को करना पड़ा. लेकिन पुर्नवास की आस में प्रभावित परिवार बिलखता रहा. इस घटना को याद्कर बीते आठ वर्षों से लोग बरसी तो मना रहे हैं लेकिन सरकार के द्वारा प्रभावित परिवारों की सुध तक नहीं ली जा रही है. मंच के अध्यक्ष रामजी दास सरकार की नियत पर सवाल खड़ा करते हुए कहते हैं कि कोसी त्रासदी के आठ वर्षों के बाद भी सरकार के द्वारा कोसी नवनिर्माण के लिए इमानदार प्रयास नहीं किया जाना राजनीतिज्ञों के कथनी व करनी में अंतर स्पष्ट करने के लिए काफी है. बिहारीगंज के लखन कुमार, विजेन्द्र दास, शिवनंदन मुखिया सहित अन्य लोगों का कहना है कि कुसहा त्रासदी के बाद आए सियासी तूफान में कोसी के नवनिर्माण का सवाल शायद दम तोड़ गया. नतीजतन 2008 के बाढ़ प्रभावित परिवारों को पुर्नवासित नहीं किया जा सका. कोसी त्रासदी की जांच रिपोर्ट जांच आयोग के द्वारा सौंपे जाने के बाद भी इसे सार्वजनिक नहीं किया जाना बहुत बड़े सवाल को जन्म देने के लिए काफी है. राजू खान, लालू ठाकुर, प्रभात कुमार भारतीय आदि का कहना है कि कुसहा त्रासदी के बाद भी विकास के मामले में हासिए पर खड़ा कोसी शायद राजनीतिक साजिश का शिकार हो गया. इधर मधेपुरा के जिलाधिकारी मोहम्मद सोहेल के साथ-साथ सहरसा, सुपौल, अररिया तथा पूर्णिया के जिलाधिकारियों का कहना है कि कोसी नवनिर्माण योजना के तहत बाढ़ प्रभावित परिवारों के बीच सरकारी दिशा-निर्देश के आलोक में राहत का वितरण किया गया था और घरों के निमार्ण के काम को द्रुतगति से अंजाम दिया जा रहा है. बहुत जल्द कोसी नवनिर्माण का सपना साकार होना तय है. बहरहाल, कोसी के नवनिर्माण का सपना साकार हो सकेगा अथवा अन्य योजनाओं की तरह यह योजना भी धूल फांकती रह जाएगी, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा. लेकिन कोसी नवनिर्माण की बात अगर महज लफ्फेबाजी साबित हुई तो कोसी का आंदोलन की आग में तपना तय है, ऐसा स्थानीय लोगों का कहना है.

इधर मधेपुरा जिले के रामस्वरूप पासवान तथा चन्द्रहास प्रसाद का कहना है कि कोसी नवनिर्माण के सवाल पर भले ही राजनीति तेज होती रही हो, लेकिन लगता नहीं है कि कोसी नवनिर्माण की बात सत्य साबित होने वाली है, क्योंकि आठ वर्ष बीत जाने के बाद अब कोसी बेसिन डेवलपमेंट के नाम से शुरू की गई योजना में कुसहा त्रासदी में प्रभावित हुए लोगों के पुर्नवास का जिक्र तक नहीं है. कृषि कार्यों को बढ़ावा दिए जाने की योजना के तहत खेतों में जमा बालू को निकालकर खेतों को उर्वरा बनाया जाने की बात तो लक्षित की गई है, लेकिन किसानों का आशियाना सजाने के सवाल पर कोई चर्चा नहीं है. बहरहाल, कोसी त्रासदी की बरसी मनाते आ रहे लोगों का कहना है कि इस घटना में मौत के शिकार हुए कुल 362 लोगों के लिए सच्ची श्रद्धांजलि कोसी का नवनिर्माण ही माना जा सकता है और अगर कोसी नवनिर्माण के नाम पर राजनीतिक ग्रहण लगाने की कोशिश हुई तो राजनीतिज्ञों का बेनकाब होना तय है.■

feedback@chauthiduniya.com

"टी.आई." ब्राण्ड शटरपत्ती
क्वालिटी में सर्वोत्तम

पीरमुहानी,जगत जननी माता मन्दिर के नजदीक, पटना-3
फोन : 0612-3293208, 6500301, Email : aligarhlocks@gmail.com
अपने क्षेत्र बिहार का प्रथम एवं एकमात्र TM प्रतिष्ठान ❖ नक्कालों से सावधान
कृपया हमारे इस नाम से मिलते-जुलते प्रतिष्ठान को देख भ्रमित न हों।

ईम्पोर्टेड केमिकल से तैयार, लैब टेस्टेड

पेन्ट डिस्टेम्पर
कोई भी हो
वॉल पुट्टी केवल ईटालियन वॉल पुट्टी

Laboratory Tested
Please Compare Lab Report
Laboratory Tested

Made from Imported Chemicals
ईटालियन
व्हाइट
वॉल पुट्टी
Slight Costly but Superior

लैब रिपोर्ट अवश्य चेक करें ।
लैब रिपोर्ट हमारे सभी डीलर्स के यहां उपलब्ध है

प्रखण्ड स्तर या अपने क्षेत्र हेतु सप्लायर / डीलरशिप के लिए सम्पर्क करें ।
Mob : 9431234022 / 9435040133 Mail ID : mcwaterproof@yahoo.com

सीमेन्ट की ताकत बढ़ाए, घर को मजबुत बनाऐ

सीमेन्ट
कोई भी हो परन्तु
वाटरप्रूफिंग केमिकल सिर्फ

मिस्टर केमिस्ट

सीमेन्ट कोई भी हो लेकिन वाटरप्रूफिंग केमिकल मिस्टर केमिस्ट ही हो, क्योंकि मिस्टर केमिस्ट वाटरप्रूफिंग केमिकल ईम्पोर्टेड केमिकल से बनाया गया है, प्रत्येक पैक पर नम्बर युक्त होलोग्राम से नकल से पूरी तरह सुरक्षित १, ५, १०, २० एवं २०० लीटर होलोग्रामिक पैक में अब आपके यहां भी उपलब्ध । मिस्टर केमिस्ट वाटरप्रूफिंग सीमेन्ट की ताकत बढ़ाए, घर को मजबुत बनाए ।

Mob : 9431234022 / 9435040133 Mail ID : mcwaterproof@yahoo.com

निश्चय यात्रा के दौरान चुनावी वादों के अमलीजामा की सच्चाई से अवगत होने नीतीश कुमार सीतामढ़ी व शिवहर पहुंचे. मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर एक तरफ जहां प्रशासनिक तंत्र सक्रिय रहा, वहीं चेतना सभा में सीएम के संबोधन को सुनने को लेकर लोगों में खूब उत्साह रहा. 12 नवंबर को आयोजित इस सभा में खासकर महिलाओं में सरकार के प्रति विशेष विश्वास देखने को मिला. शराब बंदी लागू होने के बाद के हालात पर सरकार व प्रशासनिक आलाधिकारियों के संबोधन से बेहतर बिहार के निर्माण की उम्मीदें जगी हैं. चेतना सभा में पहुंचे लोगों को उम्मीद थी कि सीएम प्रधानमंत्री के नये नोट प्रचलन की घोषणा पर अपना विचार रखेंगे. परंतु नीतीश ने सिर्फ और सिर्फ बिहार व बिहार सरकार तक ही लोगों को बांधे रखा. जीविका से जुड़ी महिलाओं का कहना था कि नीतीश सरकार ने जहां राज्य में पूर्ण शराबबंदी कानून को लागू कर परिवार व समाज में शांति कायम करने का काम किया है, वहीं केंद्र की सरकार के मुखिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गलत तरीका से अकूत कमाई कर तिजोरी भरने वालों को होश में लाने का काम किया है. शराबबंदी के बाद महिलाओं के पर्स में नकदी की बढ़ोतरी हुई, तो मोदी के फरमान से जमा पूंजी का महज चंद दिनों में ही खुलासा हो गया. बावजूद इसके वे यह सोचकर खुश हैं कि अब इन पैसों का उपयोग परिवार के कार्य में होगा न कि शराब और बर्बादी में.

मुख्यमंत्री के निश्चय यात्रा को लेकर जिले की राजनीति में सुगबुगाहट होने लगी है. पहले सीतामढ़ी का ही जिक्र करते है, जहां हाल ही में भाजपा का दामन छोड़कर जदयू के पाले में आने वाले एक स्थानीय पंचायत प्रतिनिधि को लेकर चर्चाओं का बाजार गरमाने लगा है. चर्चा है कि मुख्यमंत्री के चेतना सभा मंच पर सीतामढ़ी जिला परिषद उपाध्यक्ष को देख कुछ लोग सभा स्थल पर ही कानाफुसी करने लगे.

नीतीश की चेतना से बढ़ा महिलाओं में उत्साह

सीतामढ़ी-शिवहर

वाल्मीकि कुमार

अब तक एक कहावत प्रचलित रही है कि केंद्र सरकार व राज्य सरकार के विचारों में भिन्नता का खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ता है. परंतु आजादी के बाद पहली बार ऐसा मौका आया है, जब दोनों जगह अलग-अलग पार्टियों के गठबंधन की सरकारे हैं, मगर दोनों के कदमों को बिहार का जनमानस सराह रहा है. तकरीबन एक दशक से जहां बिहार में सुशासन की सरकार के कामयाबी का राग गाया जा रहा है, वहीं केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के कार्यों की भी सराहना की जा रही है. हालांकि ऐसा भी नहीं है कि दोनों सरकारों की आलोचना नहीं हो रही है. बावजूद इसके आम जनता दोनों को अबकी बार अलग-अलग नजरिये से देख रही है. पिछले 12 नवंबर को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पूर्व की यात्राओं की तरह एक बार फिर निश्चय यात्रा के दौरान सीतामढ़ी व शिवहर जिले में सरकारी घोषणाओं के तहत हो रहे कार्यों का अवलोकन किया. इस दौरान शिवहर जिले में जहां सीएम ने लोक शिकायत कार्यालय का निरीक्षण किया, वहीं सीतामढ़ी जिले के बेलसंड अनुमंडल में हर घर में नल से जल योजना का उद्घाटन किया. खुले में शौच मुक्त अनुमंडल बनाने को लेकर सीएम ने सीतामढ़ी स्टेडियम मैदान में आयोजित चेतना सभा में जिला पदाधिकारी राजीव रौशन एवं जिला के प्रशासनिक तंत्र के प्रयासों की सराहना की. सीएम ने कहा कि यह अनुमंडल सूबे के अन्य जिलों के लिए अनुकरणीय साबित होगा. मुख्यमंत्री ने बिहार में पहली अप्रैल 2016 से लागू पूर्ण शराब बंदी की सफलता का जिक्र करते हुए स्वीकार किया कि अभी कुछ और जागरूकता की आवश्यकता है. शराब बंदी से परिवार, समाज व राज्य के कोने-कोने में चारो ओर शांति ही शांति है. अब लोग शराब की जगह दूध का अधिक सेवन करने लगे हैं. शिक्षा के विकास को लेकर बेहतर माहौल बन रहा है और महिलाओं को सम्मान मिलने लगा है. मुख्यमंत्री के संबोधन के दौरान महिलाओं में खासा उत्साह देखने को मिला. पूछे जाने पर कुछ महिलाओं ने कहा कि शराब बंदी से मेरे परिवार का कल्याण हो गया है. 11 नवंबर की देर शाम को हीं डुमरा रोड स्थित परिसदन पहुंचे सीएम की आगवानी व स्वागत को लेकर पार्टी व गठबंधन दल के नेता व कार्यकर्ता जमने लगे. परिसदन के मुख्य द्वार से लेकर आसपास के क्षेत्र को बैनर व होर्डिंग से पाट दिया गया. मगर सुरक्षा कारणों से बहुत कम लोगों को ही सीएम का प्रथम दर्शन संभव हो सका. चर्चा यह भी रही कि सुरक्षा कर्मियों से उलझने के कारण कुछ नेताओं को वहां से भगाया भी गया था. पार्टी नेताओं में अबकी बार बेचैनी सा नजारा बना रहा, क्योंकि सरकारी कार्यक्रम होने के कारण इन्हे पूर्व की तरह राजनैतिक नारेबाजी का मौका नही मिला. वहीं आम कार्यकर्ताओं ने भी इस कार्यक्रम में बहुत अधिक भागीदारी से परहेज रखा. नतीजा रहा कि कुछ प्रतिनिधियों को अपना होर्डिंग व बैनर खुद लगवाते और इसे देखकर प्रसन्न होते देखा गया. कार्यक्रम को लेकर कुछ लोगों का कहना है कि राजनीति का ऑफ सीजन होने के कारण अबकी बार भाड़े के नारेबाजों को बुलाने से परहेज किया गया है, वहीं दूसरी ओर इसे प्रधानमंत्री के नोट बैन का भी असर बताया गया. 500-1000 के नोटों पर प्रतिबंध और सौ-पचास के नोटों की अनुपलब्धता ने नारेबाजों को निराश कर दिया.

अब एक नजर सीतामढ़ी व शिवहर जिले की राजनैतिक गतिविधियों पर भी डालना आवश्यक है. मुख्यमंत्री के निश्चय यात्रा को लेकर जिले की राजनीति में सुगबुगाहट होने लगी है. पहले सीतामढ़ी का ही जिक्र करते है, जहां हाल ही में भाजपा का दामन छोड़कर जदयू के पाले में आने वाले एक स्थानीय पंचायत प्रतिनिधि को लेकर चर्चाओं का बाजार गरमाने लगा है. चर्चा है कि मुख्यमंत्री के चेतना सभा मंच पर सीतामढ़ी जिला परिषद उपाध्यक्ष को देख कुछ लोग सभा स्थल पर ही कानाफुसी करने लगे. लोगों के चर्चा होती रही कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कार्य जनहीत में तो प्रशांसनीय है. परंतु दलगत निर्णय में कुछ लोगों की साजिशे इन्हें भ्रमित कर देती है. इसका खामियाजा जिला संगठन को भुगतना पड़ता है. इसी संदर्भ में भाजपा के पूर्व विधान पार्षद बैद्यनाथ प्रसाद का कहना है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अनिश्चितताओं के भ्रमजाल में हैं. इन्हें अब तक पूरा किये गये अपने वादों का रिपोर्ट कार्ड जारी करना चाहिए था. जहां तक भाजपा से जदयू में भागे लोगों का सवाल है, तो यह साफ है कि नेताओं को क्वालिटी नही क्वांटीटी चाहिए. संघर्षशील कार्यकर्ताओं की अनदेखी कर अकूत कमाई करने वालों को तरजीह दी गयी है. वहीं नाम ना उजागर करने की शर्त पर कुछ स्थानीय नेताओं का कहना है कि गलत कार्यों में संलिप्त लोगों को अब सत्ता संरक्षण मिल गया है. सच्चाई चाहे जो हो परंतु चर्चा का केंद्र फिलहाल यही है. वहीं सीएम के निश्चय यात्रा पर निशाना साधते हुए सीतामढ़ी के पूर्व भाजपा विधायक सह सूबे के पूर्व पर्यटन मंत्री सुनील कुमार पिंटू ने कहा कि पटना के गठबंधन में लठबंधन चल रहा है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लालू जी के डर से यात्रा पर निकले हैं. वहीं कुछ लोग अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करने को लेकर भाजपा का दामन छोडकर सत्ता की गलियों में अपना ठिकाना बनाने में कामयाब रहे हैं, ताकि सुरक्षित रहकर अपना लूट खसोट का कार्य कर सकें.

इधर शिवहर जिले में भी मुख्यमंत्री के निश्चय यात्रा पर प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हो गया है. भाजपा के नव निर्वाचित जिलाध्यक्ष संजीव कुमार पांडेय का कहना है कि मुख्यमंत्री ने शिवहर के जनता की उम्मीदों पर पूरी तरह से पानी फेर दिया है. लोग आस लगाये थे कि मुख्यमंत्री से जिले में परिवहन निगम की बसों का संचालन, पोस्टमार्टम हाउस, करोड़ों की लागत से निर्मित अस्पताल का उद्घाटन समेत अन्य मांगों को रखेंगे. परंतु स्थानीय विधायक व जिला प्रशासन की मिलीभगत से कुछ भी नहीं हो सका. सीएम लोक शिकायत कार्यालय का निरीक्षण कर लौट गये, परंतु प्रखंड कार्यालय पहुंच कर पूर्व से निर्धारित आरटीपीएस का उद्घाटन तक करना मुनासिब नही समझा गया. दोनों ही जिले में राजनीतिक चौपाल सजाने वालों का कहना है कि मुख्यमंत्री को शराब बंदी की सफलता पर प्रसन्न होने के साथ ही पार्टी व गठबंधन दल के कार्यकर्ताओं की भावना का सम्मान भी करना होगा. धनकुबेरों को अपनाने की बजाय समर्पित कार्यकर्ताओं को तरजीह देनी होगी. किसी कारण से अलग-थलग पड़ चुके पुराने साथियों को साथ लेना होगा. अगर ऐसा होता है, तो नीतीश कुमार के सात निश्चय की सफलता पर कहीं संदेह की गुंजाइश नही रहेगी. सूबे की आम जनता पूर्ण विश्वास के साथ मुख्यमंत्री का कदम दर कदम साथ देने को तैयार रहेगी. अगर नहीं, तो कुछ भी कहा नहीं जा सकता कि जनता कब किसके साथ हो जाए. ■

feedback@chauthiduniya.com

दाँतों के सड़ने से पहले रहें सचेत
ariskon Pharma Pvt.Ltd.
An ISO 9001 : 2008 Certified Co.
डॉ. देवव्रत (बीडीएस.) सदर अस्पताल खगड़िया
माँ गायत्री डेन्टल क्लीनिक रेड क्रॉस के सामने हॉस्पिटल रोड

खगड़िया के सदर अस्पताल में कार्यरत डॉ. देवव्रत ने दाँतों के सड़ने और गंदे होने से पहले ही उसकी सुरक्षा के प्रति जागरूक रहने के लिए अगाह किया और बताया कि दाँतों के सड़ने के चार स्टेज होते हैं उसी वक्त आप सचेत हो जायें। पहला स्टेज है जब दाँतों पर व्हाईटनेस आ जायें अर्थात चमकीलापन दूसरे स्टेज में दाँत पिला होना शुरू हो जाता है। तिसरे स्टेज में दाँतों में कैविटी या गढ्ढा होने लगता है। और चौथे स्टेज में दाँत सड़ जाते हैं इस स्टेज में आने से पहले आप सचेत हो जायें और समय-समय पर डॉक्टर से चेकअप करवाते रहें। आपको चाहिए कि फ्लोराइड वाला टूथपेस्ट इस्तेमाल तो करें ही साथ ही जब भी खाना खायें या नास्ता करें तो उसके बाद अपनी अंगूलियों से दांतों को साफ करें या मसूढ़ों की मसाज करें। दो टाईम ब्रशिंग हर किसी के लिए अनिवार्य होना चाहिए। अधिकतम छः महीने में ब्रश बदल लें। ब्रश को 360 डिग्री पर घुमाते हुए ब्रश करें उपर निचे की ओर घुमते हुए ब्रश करें। बाजार में माउथ वाश गरगेल आता है उसका भी प्रयोग करें। आईए जानते हैं कुछ और दाँतों के बारे में- हमेशा नरम ब्रिस्टल वाले टूथब्रश का प्रयोग करें। • भोजन के बाद कुल्ला करके मुंह को साफ कर लें। • दांतों के बीच फ्लॉस करके फंसे हुए खाद्य कणों को निकाल दें। • मुंह सूखने पर लार का प्रवाह बढ़ाने के लिये शक्कर रहित चुइंग गम खाएं। • लार का प्रवाह बढ़ाने और चबाने की पेशियों की कसरत के लिये कड़े नट खाएं। • शिशुओं को टूथपेस्ट मटर के आकार जितनी मात्रा में दें और उन्हें ब्रश करने के बाद पेस्ट को थूक देने के लिये प्रोत्साहित करें। ■ भारती

ACOBA CAP/SYP/INJ
Methylcobalmin, Lycopene, Multivitamin Multimineral, Ginseng & Antioxident
Carbo - XT
Ferrous Ascorbate with Folic Acid Tab.
AREX
Dextromethorphan, Guaiphenesine Ammonium chloride Cough Syp.
ASRFEN-P
Acedofenac+Paracetamol Serratiopeplidase Tab.
ECTALOPAM
Escilalopram oxalate & Clonazepam Tablets
SILIPLEX
Silymarin, Vitamin B-Complex & Lactic acid, Calcium, Bacillus Cap/Syp
NOKSIRA
NOKSIRA Pharma Pvt.Ltd.
A Division of AriskonPharma

यूपी के आदिवासियों का विरोध सोनभद्र से दिल्ली पहुंचा, जनसैलाब ने पूछा सवाल

क्यों छीन ली आदिवासियों की सीटें?

सूफी यायावर

उत्तर प्रदेश विधानसभा में आदिवासियों के लिए सीट आरक्षित करने के लिए आदिवासी अधिकार मंच ने पिछले दिनों दिल्ली के जंतर-मंतर पर धरना-प्रदर्शन किया. पिछले लंबे अर्से से उत्तर प्रदेश के सोनभद्र और अन्य आदिवासी बहुल इलाकों में चल रहे आंदोलन के क्रम में आदिवासी समुदाय के लोगों, किसानों, मजदूरों और महिलाओं ने बड़ी तादाद में राजधानी दिल्ली के धरना-प्रदर्शन में हिस्सा लिया.

उत्तर प्रदेश में आदिवासी समुदाय की आबादी 11 लाख से अधिक है. हाईकोर्ट ने 2012 में आदिवासी समुदाय को उनकी आबादी के अनुपात में विधानसभा में सीट आरक्षित करने का आदेश दिया था. इसके अनुपालन में तत्कालीन सरकार ने अध्यादेश और विधेयक के जरिए दुद्धी और ओबरा विधानसभा सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित करने की अधिसूचना जारी कर दी. लेकिन विडंबना यह रही कि केंद्र सरकार ने 4 जुलाई 2014 को राज्यसभा में विधेयक वापस ले लिया. इस वजह से अधिसूचना लागू नहीं हो पाई और उत्तर प्रदेश के आदिवासी राजनीतिक प्रतिनिधित्व से ही वंचित हो गए. राजधानी दिल्ली में आयोजित धरना-प्रदर्शन के माध्यम से उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के पूर्व केंद्र सरकार से अध्यादेश लाकर दुद्धी और ओबरा विधानसभा सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित करने की मांग की गई. इस संबंध में प्रधानमंत्री को ज्ञापन दिया गया. जंतर-मंतर पर ऑल इंडिया पीपुल्स फ्रंट (आइपीएफ) समर्थित आदिवासी अधिकार मंच की तरफ से आयोजित धरना और आमसभा का नेतृत्व पूर्व मंत्री विजय सिंह गोंड़ ने किया. आइपीएफ के प्रदेश महासचिव दिनकर कपूर ने सभा का संचालन किया.

आइपीएफ के राष्ट्रीय संयोजक अखिलेन्द्र प्रताप सिंह ने कहा कि मोदी सरकार संविधान द्वारा प्रदत्त दलित, आदिवासी और उत्पीड़ित समुदाय के अधिकारों को खत्म करने में लगी हुई है. किसानों, मजदूरों, आदिवासियों, दलितों व अल्पसंख्यकों के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया है. कारपोरेटपरस्त नीतियों के जरिए इन तबकों के अस्तित्व पर हमला किया जा रहा है. संविधान और उसमें दिए अधिकारों की रक्षा के लिए आदिवासी समाज का यह आंदोलन देश में चल रहे लोकतांत्रिक आंदोलनों की धुरी बनेगा और एक नई जन राजनीति को जन्म देगा. स्वराज इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष योगेन्द्र यादव ने आदिवासी आंदोलन का समर्थन करते हुए स्वराज अभियान के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रशांत भूषण का संदेश सुनाया, जो बीमारी की वजह से धरने में शामिल नहीं हो पाए थे. प्रशांत भूषण ने आश्वासन दिया है कि यूपी विधानसभा में आदिवासी समाज के राजनीतिक प्रतिनिधित्व के संवैधानिक अधिकार की रक्षा के लिए वे सर्वोच्च न्यायालय से अपील करेंगे. योगेंद्र यादव ने कहा कि मोदी सरकार के सबका विकास मॉडल में इस देश में रहने वाले आदिवासी, दलित, महिलाएं और अल्पसंख्यक नहीं हैं. भाजपा और उसकी सरकारों का एक ही मकसद है, आदिवासी समाज को खत्म करना. छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, असम, तेलंगाना, ओड़ीशा से लेकर देश के हर हिस्से में रहने वाले आदिवासी समाज के अस्तित्व और अस्मिता पर हमला हो रहा है. आदिवासियों के पक्ष में उठने वाली लोकतांत्रिक आवाज को खामोश करने की कोशिश हो रही है.

सीपीआई (एम) पोलित ब्यूरो की सदस्य वृंदा करात ने यूपी के आदिवासियों के सवाल को संसद में उठाने का आश्वासन देते हुए सीपीएम की तरफ से आदिवासी मांगों का समर्थन किया. करात ने कहा कि मोदी सरकार ने वृक्षारोपण के लिए कैम्पा कानून बनाकर वनाधिकार कानून को कमजोर कर दिया है और घने जंगलों में प्रतिबंधित मुख्य खनिजों के खनन की अनुमति प्रदान कर इन जंगलों में रह रहे आदिवासी, दलित व वनाश्रित जातियों की बड़े पैमाने पर बेदखली का रास्ता खोल दिया है. मोदी सरकार ने सत्ता में आते ही आदिवासियों और दलितों के विकास के लिए बजट में आवंटित होने वाली धनराशि में भी 32105 करोड़ रुपये की भारी कटौती कर दी. आदिवासियों के लिए वर्ष 2014-15 में आवंटित 26,714 करोड़ को घटाकर वर्ष 2015-16 में 19,980 करोड़ और वर्ष 2016-17 में 23,790 करोड़ रुपये कर दिया गया है. आदिवासियों के जीवन के लिए जरूरी मनरेगा, शिक्षा व स्वास्थ्य और छात्रवृत्ति के बजट में भी भारी कटौती की गई है.

पूर्व आईजी व आइपीएफ के राष्ट्रीय प्रवक्ता एसआर दारापुरी ने आदिवासी समाज को विकास की मुख्यधारा से काट दिए जाने के कुचक्र पर चिंता जताई और कहा कि यूपी के सोनभद्र का आदिवासी क्षेत्र ओड़ीशा के कालाहांडी से भी बदतर है, जहां गांवों में जाने को सड़क तक नहीं है. लोग चुआड़, नालों और बांध से पानी पीकर मरने के लिए अभिशप्त हैं. शिक्षा और इलाज की कोई व्यवस्था नहीं है.

पूर्व मंत्री विजय सिंह गोंड़ ने कहा कि उत्तर प्रदेश में आदिवासी समाज के साथ बड़ा अन्याय हुआ है. 2003 में गोड़, खरवार, चेरों, मांझी, पनिका, अगरिया, भुइंया, बैगा समेत जिन दस आदिवासी जातियों को आदिवासी का दर्जा दिया गया, उन्हें सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद भी आज तक विधानसभा और लोकसभा में राजनीतिक प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया. जबकि इन जातियों के राजनीतिक प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने 2012 में तत्कालीन केंद्र सरकार को निर्देश दिए थे. उसके अनुपालन में अध्यादेश और विधेयक लाया गया और चुनाव आयोग ने जनसुनवाई कर दुद्धी एवं ओबरा विधानसभा सीटों को आदिवासी समाज के लिए आरक्षित करने की अधिसूचना भारत सरकार को 13 जनवरी 2014 को भेज दी. लेकिन कांग्रेस सरकार ने इसे लागू करने के लिए जरूरी विधेयक को संसद से पारित नहीं किया और मोदी सरकार ने सत्ता में आते ही संसदीय और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति प्रतिनिधित्व का पुनः समायोजन विधेयक (तीसरा) 2013 वापस ले लिया. समाजवादी पार्टी और बसपा ने भी आदिवासी समाज के राजनीतिक प्रतिनिधित्व के लिए संसद में रखे विधेयक का समर्थन करने के बजाय इसका विरोध किया. यह भी विडंबना ही है कि उत्तर प्रदेश की कोल, धांगर जैसी आदिवासी जातियों को आदिवासी का दर्जा तक नहीं है. जिन गोड़, खरवार समेत दस आदिवासी जातियों को आदिवासी का दर्जा भी दिया गया उन्हें भी पूरे प्रदेश में आदिवासी नहीं माना गया. कुछ जिलों में वह अनुसूचित जनजाति में है तो प्रदेश के बड़े हिस्से में वह अनुसूचित जाति में है.

केंद्र सरकार से मांग की गई कि यूपी के विधानसभा चुनाव से पहले अध्यादेश लाकर दुद्धी व ओबरा विधानसभा सीट आदिवासी समाज के लिए आरक्षित की जाए. मंच ने यह भी मांग की कि उत्तर प्रदेश में सभी आदिवासियों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया जाए और वनाधिकार कानून के तहत आदिवासियों और वनाश्रितों को जमीन पर अधिकार दिए जाएं. आमसभा को दिल्ली विश्वविद्यालय की प्रोफेसर नंदिनी सुंदर, जेएनयू की प्रोफेसर अर्चना प्रसाद, दिल्ली के जोशी अधिकारी संस्थान के विनीत तिवारी, गांधी संस्थान की रजिस्ट्रार मुनीजा रफीक खान, पूर्व सांसद राम निहोर राकेश, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष अनीता राकेश, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के पूर्व छात्रसंघ अध्यक्ष लाल बहादुर सिंह, अखिल भारतीय गोंड़ महासभा के अध्यक्ष राजेश गोंड़, गोंड़वाना स्टूडेन्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष अरविन्द गोंड़, गोंड़वाना गणतंत्र पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अशर्फी सिंह पस्से, पूर्व प्रधान राम दुलारे गोंड़, प्रधान राजेन्द्र ओयमा, बबई मरकाम, ललित गोंड़, रमेश सिंह खरवार, रामेश्वर प्रसाद, रामजी गोंड़, नसीम खान, मुक्ति तिर्की, राजमंगल गोंड़, अजीत सिंह यादव, राजेश सचान, मनोज शाह, विजय सिंह मरकाम, सुरेन्द्र पाल, रवि कुमार गोंड़, अंजनी पटेल, परमेश्वर कोल, अरुण गोंड़ आदि ने भी संबोधित किया. ■

feedback@chauthiduniya.com

अपना दल की रैली ने गहरा किया मां-बेटी का मतभेद

बेटी के गढ़ में मां लगा रही सेंध

सन्तोष देव गिरि

अपना दल परिवार में मां-बेटी के बीच मची रार खत्म होने के बजाय बढ़ती ही जा रही है. अपना दल के 22वें स्थापना दिवस पर मीरजापुर में आयोजित व्यवस्था परिवर्तन रैली में पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्णा पटेल और उनकी बड़ी बेटी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पल्लवी पटेल ने मीरजापुर की सांसद और केन्द्रीय परिवार कल्याण राज्यमंत्री अनुप्रिया पटेल पर जिस तरह प्रहार किया उससे स्पष्ट हो गया कि परिवार और पार्टी का एक हो पाना मुश्किल है. रैली में उमड़ी भारी भीड़ से दोनों मां-बेटी काफी उत्साहित हुईं तो अनुप्रिया के माथे पर चिंता की लकीरें उभरीं.

अपना दल के 22वें स्थापना दिवस पर पार्टी संस्थापक स्व. सोनेलाल पटेल की पत्नी एवं पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्णा पटेल ने मीरजापुर के सीटी क्लब के मैदान में मतदाता पेंशन व व्यवस्था परिवर्तन रैली का आयोजन किया था. रैली का उद्देश्य कुर्मी बहुल मीरजापुर में पार्टी और उसके जनाधार का पता लगाना और अलग गुट लेकर चलने वाली सांसद व केन्द्रीय राज्यमंत्री अनुप्रिया पटेल को उन्हीं के गढ़ में हैसियत दिखाना था. रैली में उमड़ी भीड़ देख कर कृष्णा पटेल और पल्लवी पटेल के चेहरे पर प्रसन्नता के भाव देखे जा सकते थे. दोनों ने ही भाजपा के साथ-साथ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और सांसद अनुप्रिया पटेल पर निशाना साधा. कृष्णा पटेल ने भीड़ की ओर इशारा करते हुए कहा कि अब यह बताने की जरूरत नहीं है कि लोग किसके साथ हैं. उन्होंने स्पष्ट कहा कि उनकी बेटी बहक गई है. बहकाने वाले कौन हैं, यह भी सभी जानते हैं. लोकसभा चुनाव में भाजपा से अपना दल के हुए गठबंधन को उन्होंने दुर्भाग्यपूर्ण बताया और कहा कि गठबंधन का फल दुखदाई रहा, इसने परिवार में दरार डालने का काम किया.

पल्लवी पटेल ने मांग की कि सकल घरेलू आय का 50 प्रतिशत विकास और 50 प्रतिशत मतदाता पेंशन के नाम पर खाते में दिया जाए. उन्होंने केन्द्र और प्रदेश की सरकारों द्वारा चलाई गई योजनाओं को भ्रष्टाचार से घिरा बताया और कहा कि किसान आंदोलन से निकल कर देश की राजनीति के स्तम्भ बने लौह पुरुष सरदार बल्लभ भाई पटेल को सभी दलों द्वारा आदेश बनाने की होड़ तो लगी हुई है, लेकिन कोई उनके पग पर चलता नहीं.

कृष्णा पटेल ने दावा किया कि अपना दल के 80 फीसदी कार्यकर्ता उनके साथ हैं. आगामी विधान सभा चुनाव 2017 में वे इन्हीं कार्यकर्ताओं के बूते उत्तर प्रदेश की 150 सीटों पर उम्मीदवार खड़े करेंगी. बेटी अनुप्रिया पटेल के बारे में उन्होंने कहा कि बेटी के रूप में उनकी घर वापस हो सकती है, लेकिन मंत्री के रूप में नहीं. ■

feedback@chauthiduniya.com

किसानों में ख़ूनी कटुता बढ़ा रहा हरियाणा-यूपी सीमा विवाद

उधर पंजाब तो इधर तप रहा यूपी

उत्तर प्रदेश-हरियाणा सीमा पर दशकों पहले यमुना ने बदली थी धारा

निरंजन मिश्र

पता नहीं तीसरा विश्व युद्ध जल को लेकर कब और कैसे होगा, लेकिन जल या नदियों से उपजा विवाद जिस तरह से कई भारतीय राज्यों के बीच तनाव उत्पन्न कर रहा है, वह राज्यों के संघ वाले इस देश के लिए बेहद ही चिंतनीय है. हरियाणा पंजाब के बीच एसवाईएल को लेकर आए दिन विवाद होता है. हाल ही में कावेरी जल की आग में जलते कर्नाटक-तमिलनाडु की तस्वीर शायद ही किसी के जेहन से उतरी हो. इस बीच नदी के कारण उपजा सीमा विवाद दो और राज्यों के बीच तनाव का कारण बन रहा है. उत्तर प्रदेश और हरियाणा की सीमा पर यमुना के धारा बदलने के कारण दोनों राज्यों के बीच दशकों पहले विवाद शुरू हुआ था लेकिन चुनावी मौसम में यह मुद्दा फिर से गरमाने लगा है.

यमुना की धारा का रुख बदलने के कारण यूपी का कुछ हिस्सा हरियाणा में चला गया, तो हरियाणा का कुछ यूपी में आ गया. खेतीहर जमीन की इस भौगोलिक बदलाव ने दोनों राज्यों के किसानों के बीच विवाद को जन्म दिया, जो बाद में दोनों राज्यों के बीच टकराव का बड़ा कारण बन गया. यमुना नदी के साथ लगते करीब 10 हजार एकड़ भूमि को लेकर हरियाणा व यूपी के गांवों में पिछले करीब 40 साल से टकराव चला आ रहा है. उत्तर प्रदेश के टप्पल के किसानों की 2188 एकड़ भूमि हरियाणा सीमा में गई है, जबकि वहां की 1286 एकड़ जमीन अलीगढ़ सीमा में आई हुई है. हरियाणा के किसान यूपी में अपनी जमीन की फसल तो काट ले जाते हैं, लेकिन हरियाणा वाले यूपी के किसानों को फसल नहीं काटने देते. जाहिर है झगड़ा होता है, जो कई बार खूनी टकराव का रूप ले लेता है. करीब तीन-सीढ़े तीन दशक पहले केंद्र सरकार ने दखल देते हुए दीक्षित आयोग गठित किया और उसकी रिपोर्ट पर दोनों राज्यों को अमल करने को कहा था. इस विवाद में यमुना नदी से सटे हरियाणा के गांव खोजकीपुर और यूपी के गांव टांडा के किसान भी पीस रहे हैं. उनके 1698 एकड़ भूमि विवाद का स्थाई हल नहीं हो पा रहा है. पानी का स्तर कम होने पर नदी के अंदर खेती करने को लेकर भी दोनों प्रदेशों के किसानों के बीच विवाद होता है.

यूपी के किसानों की जमीन को हरियाणा के किसानों द्वारा कब्जा किए जाने का मामला हरियाणा हाईकोर्ट में भी चल रहा है. टांडा (यूपी) के कई किसानों का कहना है कि उनकी भूमि पर हरियाणा के गांव खोजकीपुर, रायमाल, संजोली और गोयला खुर्द के किसान कब्जा कर खेती करते हैं. इस विवाद में यूपी के किसानों की करीब 1698 एकड़ भूमि फंसी है, जो 618 किसानों के नाम है.

1995 में पांच राज्यों हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, उत्तरप्रदेश व हरियाणा के बीच यमुना जल पर समझौता हुआ था. इसके बावजूद इन राज्यों के बीच पानी के बंटवारे को लेकर कई बार विवाद हो जाता है. सैकड़ों किसानों के खिलाफ मामले लंबित पड़े हैं. पूर्वी उत्तर प्रदेश के बलिया और आरा जिले के 39 गांवों की 7062 एकड़ जमीन विवादित है. यूपी के बिलया और बिहार के छपरा, आरा, बक्सर और सीवान के 153 गांवों की 65 हजार एकड़ जमीन सीमा विवाद में उलझी है. राज्यों के बीच जो भी समस्याएं है, उनको सिर्फ किताबों या बहस तक सीमित नहीं रखना चाहिए. सरकारों और प्रशासनिक स्तर पर उनके निदान का प्रयास होना चाहिए. हरियाणा-यूपी विवाद सीधे तौर पर खेती किसानी से जुड़ा हुआ है, जो स्थानीय लोगों की जीविका का प्रमुख साधन है. फसलों की बुआई या कटाई के हर सीजन में यह विवाद एक नया रूप लेता है. झगड़ा कई बार लाठी-डंडों और बुदूकों तक पहुंच जाता है. यमुना के रास्ता बदलने से हुए विवाद को शांत कराने की सारी कवायद कई बार ध्वस्त हो चुकी है. वहां के किसान भी किसी का आदेश मानने को तैयार नहीं होते हैं. बंदूक के बल पर वह मनमानी कर तनाव की स्थिति पैदा करते हैं. एक बार फिर यहां तनाव की स्थितियां बन रही हैं. हरियाणा के हसनपुर इलाके में इसे लेकर सक्रियता है.

यूपी के किसानों की जमीन को हरियाणा के किसानों द्वारा कब्जा किए जाने का मामला हरियाणा हाईकोर्ट में भी चल रहा है. टांडा (यूपी) के कई किसानों का कहना है कि उनकी भूमि पर हरियाणा के गांव खोजकीपुर, रायमाल, संजोली और गोयला खुर्द के किसान कब्जा कर खेती करते हैं. इस विवाद में यूपी के किसानों की करीब 1698 एकड़ भूमि फंसी है, जो 618 किसानों के नाम है. इन किसानों की भूमि उन्हें नहीं मिली है, जो कि दीक्षित अवार्ड के तहत हरियाणा के रकबे में आई हुई है. उस भूमि को यूपी के किसानों को दिये जाने की मांग काफी अर्से से हो रही है. टांडा के किसानों ने हरियाणा हाईकोर्ट में शपथ पत्र दिया है कि उनकी भूमि उन्हें नहीं मिल रही है. इस भूमि पर हरियाणा के किसान खेती करते हैं. जबकि इसका रिकार्ड व असल मालिक यूपी टांडा के किसान हैं.

इस मामले का लब्बोलुबाव यह है कि हरियाणा और यूपी की सीमा को लेकर बीते करीब 40 साल से चला आ रहा विवाद किसी प्रकार से सुलझने का नाम नहीं ले रहा है. यूपी के किसान यमुना तट पर स्थित जमीन पर होने वाली खेती पर अपना अधिकार बताते हुए उसे काटने के लिए आ पहुंचते हैं तो दोनों ओर से हिंसक तनाव फैल जाता है. दोनों प्रदेशों की सरकार और प्रशासन द्वारा लाख कोशिशें कर लिए जाने के बाद भी आज हालात यह हैं कि यमुना तट पर स्थित दोनों प्रदेशों के गांवों के लोगों में टकराव की स्थिति बनी हुई है और अब यूपी विधानसभा चुनाव से पहले मामला फिर गरमाने लगा है. ■

नहीं सुलझ रहा सीमा विवाद

हरियाणा और उत्तर प्रदेश पड़ोसी राज्य हैं. दोनों राज्यों के बीच से यमुना नदी निकलती है. आम लोगों के लिए इसी यमुना से दोनों राज्यों के बीच सीमा का निर्धारण होता है. लेकिन नदी के किनारे बसे दोनों राज्यों के लोगों के लिए यही यमुना सबसे बड़ी परेशानी का कारण है. सितंबर-अक्टूबर के महीने में यमुना में बड़ी मात्रा में पानी छोड़ा जाता है. पानी के तेज बहाव को संभाल पाना किसी के भी बूते में नहीं होता और ऐसे में पानी कभी उत्तर प्रदेश की सीमा में अधिक बहता है तो कभी हरियाणा की सीमा से बहते हुए मिट्टी का कटाव करता जाता है. यही कारण है कि कभी भी इसका सीमा निर्धारण नहीं हो पाता है. जब यमुना की तलहटी सूख जाती है तब वहां के किसान इसमें खेती करते हैं.

तलहटी में गेहूं की बिजाई करने के साथ ही प्लेज की फसलें यानि पेठा, ककड़ी, घीया, तरबूज और खरबूजा इत्यादि की लगाई जाती हैं, जो बेल पर उगती हैं. सीमा निर्धारित नहीं है, ऐसे में यहां पर यह निश्चि त ही नहीं है कि जो किसान अपनी पूरी मेहनत से फसल की बिजाई कर रहा है, वहीं किसान फसल की कटाई भी करेगा. फसल के तैयार होने पर उत्तर प्रदेश के किसान ट्रैक्टर ट्रालियों में भरकर आते हैं और हथियारों के बल पर लोगों को डराते हुए फसल को काट कर ले जाते हैं. यह सिलसिला बीते एक-दो साल से नहीं बल्कि करीब 40 सालों से लगातार चला आ रहा है.

इस समस्या के स्थाई समाधान के लिए साल 1980 के दशक में दीक्षित अवार्ड घोषित किया था. जिसके तहत दोनों प्रदेशों की सीमाओं को निर्धारित करते हुए यहां पर पिलर लगवाए गए थे, लेकिन समय बीतने के साथ ही पिलर गायब हो गए जिससे समस्या फिर से पैदा हो गई. दोनों ही प्रदेशों के किसान दावा करते हैं कि जमीनें उनकी हैं और उनके पास इस बात के पुख्ता सुबूत भी मौजूद हैं.■

क्या है दीक्षित अवार्ड

यमुना के अनियंत्रित बहाव के चलते दोनों राज्यों के किसानों का विवाद सुलझाने के लिए केंद्र सरकार ने तत्कालीन केंद्रीय गृहमंत्री उमाशंकर दीक्षित को आरबीट्रेटर नियुक्त किया था. उन्होंने इस बाबत 14 फरवरी 1975 को अपना निर्णय दिया था. सर्वे आफ इंडिया द्वारा 1971-72 में यमुना बहाव की लाइन देखकर 1975 में किया गया सर्वे उनके निर्णय का आधार था. भारत सरकार के गृह विभाग ने 15 सितंबर 1975 को यह अवार्ड जारी किया. 1984 में दीक्षित अवार्ड के तहत फरीदाबाद के 14 गांवों की 4803 एकड़ जमीन का रिकार्ड यूपी शासन को सौंपा गया तथा यूपी के पांच गांवों की चक का 1861 एकड़ जमीन का रिकार्ड हरियाणा सरकार को मिला. यमुना नदी के बहाव के चलते न सिर्फ फसल बोने और काटने का विवाद प्रतिवर्ष होता है, बल्कि कई तो ऐसे मामले भी विभिन्न अदालतों में चल रहे हैं कि एक गांव की एक ही जमीन का राजस्व रिकार्ड यूपी और हरियाणा दोनों राज्यों के पास है. केजीपी के लिए जमीन अधिग्रहण के मुआवजे के लिए चांदपुर गांव के ही किसानों के आरोपों का यदि स्थायी समाधान नहीं हुआ तो केजीपी निर्माण में भी बाधा आ सकती है. क्योंकि हरियाणा के किसान अपने मुआवजे के लिए अदालत की शरण लेंगे. ■

विवाद के साये में ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस-वे

उत्तर प्रदेश और हरियाणा के किसानों के बीच विवाद के चलते ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस-वे भी संकट में है. ईस्टर्न एक्सप्रेस वे हरियाणा के पलवल से शुरू होकर ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद तक जाएगा. इसे कुंडली मानेसर-पलवल से जोड़ा जाएगा. पलवल से ग्रेटर नोएडा के बीच यमुना बह रही है, जिसे बॉर्डर भी माना जाता है. विवाद इसी यमुना से लगती जमीन को लेकर है. एक्सप्रेस-वे के लिए ली गई जमीन के मुआवजने को लेकर भी मसला फंसा है. हरियाणा के किसानों का कहना है कि जिस जमीन पर सालों से वे खेती कर रहे हैं उस जमीन का मुआवजा यूपी के किसानों ने ले लिया है जबकि यूपी के किसानों का कहना है कि उनके पास जमीन के कागजात मौजूद हैं. ■

feedback@chauthiduniya.com

आज़ादी की आड़ में अराजकता?

अनंत विजय

निजी न्यूज चैनल एनडीटीवी पर एक दिन की पाबंदी के दौरान अभिव्यक्ति की आज़ादी को लेकर खूब हो हल्ला मचा. देशभर में पत्रकारों के कई छोटे-बड़े संगठनों ने सरकार के इस फैसले को इमरजेंसी की याद दिलाने वाला करार दिया. करीब हफ्ते भर चले विरोध प्रदर्शन के बाद सरकार ने पाबंदी को स्थगित कर दी. इस पूरे घटनाक्रम के दौरान एक बार फिर से अभिव्यक्ति की आजादी को लेकर देशव्यापी गंभीर बहस की आवश्यकता महसूस की गई. आज जिस तरह से कई न्यूज चैनलों पर खबरों के नाम पर फिक्शन को बढ़ावा दिया जा रहा है या फिर कई बार तो अंधविश्वास के खिलाफ जागरूकता की आड़ में अंधविश्वास को बढ़ावा दिया जाता है, उसपर यह बहस होनी चाहिए कि मीडिया की अभिव्यक्ति की आजादी की सीमा कहां तक है या उसकी कोई सीमा नहीं है. अभिव्यक्ति की आजादी की सीमा तो संविधान के पहले संशोधन के वक्त बहुत साफ कर दी गई थी. आजादी के बाद जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी अखंड भारत को लेकर आंदोलनरत थे, तो उस वक्त उनके भाषणों को पाकिस्तान युद्धोन्माद बढ़ाने वाला मानते हुए आपत्ति जता रहा था. पाकिस्तान की शिकायत और नेहरू लियाकत समझौते के बाद तय हुआ कि अभिव्यक्ति की आजादी की सीमा तय की जाए और फिर संविधान का पहला संशोधन हुआ जिसमें इसकी सीमा तय कर दी गई तब बहाना बना था, मद्रास से निकलने वाली पत्रिका क्रासरोड और राष्ट्रीय संघ से जुड़ी पत्रिका आर्गेनाइजर में छप रहे लेख अब जमाना बहुत बदल चुका है. संविधान के संशोधन के वक्त टीवी माध्यम या तो था नहीं या फिर उसका जनमानस पर उतना प्रभाव नहीं था. टेलीविजन चैनलों के जोर के बाद अभिव्यक्ति की आजादी को लेकर इस वक्त सचमुच एक देशव्यापी बहस की जरूरत है. अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की आड़ में मीडिया को अराजक होने का लाइसेंस नहीं मिल जाता है. बहुधा यह देखा गया है कि इसकी आड़ में मशहूर शख्सियतों पर कीचड़ उछालने का काम भी किया जाता है. हालिया उदाहरण बिग बॉस के शो का है जहां क्रिकेटर युवराज सिंह के भाई जोरावर सिंह से अलग रह रही पत्नी को शो में प्रतिभागी बनाया गया और उसने जोरावर सिंह के खिलाफ बेहद संगीन इल्जाम लगाए, जबकि ये पूरा मामला अदालत में विचाराधीन है. सवाल यह है कि अभिव्यक्ति की आजादी की आड़ में क्या मीडिया किसी की इज्जत उछालने के लिए मंच दे सकता है या आरोपों में मिर्च मसाला लगाकर पेश करने की इजाजत दी जा सकती है. लोकप्रिय टीवी शो बिग बॉस में जिस तरह से मशहूर क्रिकेटर युवराज सिंह के भाई जोरावर सिंह पर इल्जाम लगे और उनकी तरफ से ना तो कोई पक्ष सामने आया उसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं. शो में जब जोरावर सिंह की अलग रह रही पत्नी आकांक्षा शर्मा का परिचय करवाया जा रहा था, तो लग रहा था कि जैसे उन्होंने कितने जुल्म सहे हैं और जोरावर कितने निर्दयी हैं. दोनों के बीच अदालतों में मामला विचाराधीन है और सवाल यही है कि अदालतों में चल रहे मामलों के एक पक्ष को चैनल आरोप लगाने के लिए मंच मुहैया करवा सकता है. क्या ये अदालत की कार्रवाई में दखल का मामला नहीं है.

जोरावर सिंह उसी युवराज सिंह के भाई हैं जिन्होंने कैंसर जैसी बीमारी को मात देते हुए देश को क्रिकेट का वर्ल्ड कप दिलाने में केंद्रीय भूमिका निभाई थी. शो के आगाज के वक्त आकांक्षा ने सलमान खान के सामने मंच पर खड़े होकर जोरावर की प्रतिष्ठा को तार-तार कर दिया. जोरावर को इस तरह से पेश किया गया जैसे उसने एक लड़की की जिंदगी बरबाद कर दी. आकांक्षा के परिवार वाले भी नाटकीय ढंग से सामने लाए गए और आकांक्षा को उसके कथित संघर्ष में साथ देने का वादा किया गया. इस पूरे मामले में अदालतों में चल रहे केस से कुछ अलहदा तस्वीर सामने आती हैं. जब आकांक्षा शर्मा ने जोरावर सिंह पर आरोप लगाए थे और काफी हो हल्ला मचाया था तब भी जोरावर ने आकांक्षा पर किसी तरह का इल्जाम नहीं लगाया और एक मर्यादा में रहे थे. अगर सोशल मीडिया पर इस पूरे विवाद की तफ्तीश करेंगे तो कई तरह के किस्से वहां मौजूद हैं, जिसमें आकांक्षा के उपर भी ड्रग्स आदि के संगीन इल्जाम हैं. लेकिन सोशल मीडिया पर जो अराजकता है, वो मुख्यधारा की मीडिया को नहीं दी जा सकती है और उनसे एक खास तरह की जिम्मेदारी की अपेक्षा की जाती है. टेलीविजन के कार्यक्रमों को बनाने वालों को या फिर उनके कर्ताधर्ताओं को ये लगता है कि दर्शक संख्या

बढ़ाने के लिए सेलिब्रिटी से जुड़े विवादों को हवा दी जा सकती है.

दरअसल, अगर भारतीय समाज के मानस का विश्लेषण करें तो लोगों को दूसरे के परिवारों में क्या चल रहा है, ये जानने की आकांक्षा होती है. इसी चाहत को भुनाने में टीवी चैनल बहुधा लक्ष्मण रेखा पार कर जाते हैं. हालांकि शोज के दौरान होनेवाले सर्वेक्षणों या वोटिंग से ये अवधारणा निगेट ही होती है. अगर इस तरह का आंकलन सही होता, तो बिग बॉस के दर्शक आकांक्षा शर्मा को बनाए रखते और जोरावर के कथित जुल्म के किस्सों में उनकी रुचि होती तो दर्शक आकांक्षा को शो में बनाए रखते ना कि दूसरे ही सप्ताह में चलता कर देते. सवाल फिर वही कि संविधान की कौन सी धारा या केबल या टेलीविजन रेगुलेशन एक्ट का कौन सा सेक्शन इस तरह के कारनामों की इजाजत देता है. कोई महिला किसी पर भी उलजलूल आरोप लगाएगी और एक प्रतिष्ठित चैनल बगैर दूसरे पक्ष को जाने उसका टेलीकास्ट कर देगा, तो ये अभिव्यक्ति की कौन सी आजादी है. अगर सरकार इसको आधार बनाकर किसी तरह का कोई नोटिस जारी कर देती है, तो फिर देश में इमरजेंसी जैसे हालात का रोना शुरू हो जाएगा. इसी शो में जिस तरह से एक कथित बाबा और कई केस में नामजद ओम जी का मजाक बनाया जा रहा है, उसपर भी आपत्ति होनी चाहिए. एक विशेष धर्म के चोगे में मौजूद शख्स जिस तरह की हरकतें कर रहा है, उससे धर्मगुरुओं के बारे में गलत संदेश जा रहा है. क्या दर्शकों की संख्या बढ़ाने के लिए किसी की छवि धूमिल की जा सकती है. क्या टीआरपी हासिल करने के लिए किसी की इज्जत उछालने की इजाजत दी जा सकती है.

अगर आपको याद हो, तो अभिषेक बच्चन की शादी के वक्त भी एक महिला सामने आ गई थी और उसने अभिषेक की पत्नी होने का दावा किया था. उसको टीवी चैनलों पर घंटों तक दिखाया गया था. एक तरफ अभिषेक बच्चन के घर में शादी की शहनाई बज रही थी, ऐश्वर्या के हाथों में मेंहदी रचाई जा रही थी तो दूसरी तरफ वो महिला न्यूज चैनलों में लाइव होकर ये बता रही थी कि उसने कहां और कब अभिषेक बच्चन से कथित तौर पर शादी की थी. उसके जो मन में आ रहा था वो आरोप अभिषेक बच्चन पर लगा रही थी और बगैर किसी फिल्टर के वो एयर पर जा रहा था. इसी तरह का केस युवराज के भाई जोरावर के मामले में भी दिखाई दिया कि जो भी आकांक्षा इल्जाम लगा रही थी वो एयर पर जा रहा था, संभव है कि चैनल ने कुछ संपादन किया हो लेकिन दर्शकों को ऐसा प्रतीत नहीं हुआ था. इस तरह के सैकड़ों उदाहरण हैं. टेनिस स्टार सानिया मिर्जा की शादी के वक्त भी जमकर तमाशा हुआ था और न्यूज चैनलों ने इस तमाशे को जमकर भुनाया था. सानिया के पति शोएब के निकाहनामे तक दिखाए गए थे, पता नहीं ये किस तरह की अभिव्यक्ति की आजादी है. सानिया की शादी के वक्त तो उसके घर वाले काफी परेशान भी हुए थे, लेकिन अभिव्यक्ति की आजादी जैसे बड़े मुद्दे के सामने एक परिवार की परेशानी की क्या बिसात.

दरअसल न्यूज चैनलों और अन्य टीवी चैनलों के स्वनियमन का जो मैकेनिज्म है वो बहुत कारगर नहीं है. उसको और मजबूत किए जाने की जरूरत है. मुंबई पर हुए आतंकी हमले के वक्त न्यूज चैनलों के कवरेज को लेकर सवाल उठे थे, जिसके बाद सरकार ने आतंकवादी हमले के दौरान कवरेज को लेकर एक गाइडलाइन बना दी थी लेकिन बहुधा उत्साह और न्यूज चैनलों के सबसे पहले की आपाधापी में गड़बड़ी हो जाती है. इसी तरह से अगर देखें तो हमारे चैनलों ने इस्लामिक स्टेट के बगदादी को कई बार मारा और फिर कई बार जिंदा कर दिया. उससे जुड़ी वारदातों को इस तरह से मिर्च मसाला लगाकर पेश किया जाता है जैसे लगता है कि कोई क्राइम थ्रिलर चल रहा हो. वीभत्स वीडियो को बार बार दिखाया जाता है और कई बार तो उसके कारनामे उसको समर्थकों के बीच हीरो भी बना देते हैं. अभिव्यक्ति की आजादी संविधान हमें देता है लेकिन वही संविधान कुछ जिम्मेदारियां भी तय करता है. हम सबको उसका गंभीरता से पालन करना चाहिए वर्ना सरकार को मौके मिलते रहेंगे. ■

(लेखक IBN7 से जुड़े हैं)
anant.tfm@gmail.com

कम्पिल्लक

परिचय

कबीला एक सुन्दर हल्के लाल रंग का गन्धहीन और स्वादहीन पदार्थ है. यह ठण्डे पानी में नहीं घुलता है. यह उबलते हुए पानी में थोड़ा घुलता है और एल्कोहल तथा ईथर में पूरी तरह से घुल जाता है. चरक तथा सुश्रुत आदि आयुर्वेद की प्राचीन संहिताओं में अधोभागहर गणों में इसकी गणना की गई है. यह विश्व में उत्तरी भारत से श्रीलंका, दक्षिण-पूर्वी एशिया में पूर्व की ओर चीन तक, मलाया द्वीप, ताईवान, म्यान्मार, सिंगापुर, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया एवं प्रशांत द्वीप में पाया जाता है. भारत के उष्णकटिबंधीय भागों में यह शुष्क स्थानों को छोड़कर 1500 मी तक की ऊंचाई पर, हिमालय से कश्मीर, पूर्व की ओर बंगाल, अंडमान द्वीप, सिंध से दक्षिण एवं पश्चिमी घाटों में पाया जाता है.

औषधीय प्रयोग मात्रा एवं विधि

- **कर्ण रोग-** टंकण, कम्पिल्लक तथा हरीतकी चूर्ण को समान मात्रा में मिलाकर, हरीतकी क्वाथ की भावना देते हुए 125 मिग्रा की वटी बना लें, अब इस वटी को घी में घिसकर लेप करने से कान के घाव जल्दी ठीक होता है.
- **प्रतिश्याय-** कम्पिल्लक के फल एवं पत्तों का क्वाथ बनाकर 10-20 मिली मात्रा में पीने से सर्दी व जुकाम में लाभ होता है.
- **कण्ठ रोग-** काले जीरे के सूक्ष्म चूर्ण में कम्पिल्लक चूर्ण तथा घी मिलाकर गले की गांठों पर लेप करने से गण्डमाला में लाभ होता है.
- **पसली का दर्द-** एक ग्राम कबीला में 125 मिग्रा हींग मिलाकर, पानी में पीसकर 125 मिग्रा की गोलियां बना लें. नित्य एक गोली को गुनगुने पानी के साथ सेवन करने से पसली के दर्द में लाभ होता है.
- **उदर रोग-** तीन ग्राम कम्पिल्लक चूर्ण में मधु मिलाकर सेवन करने से, अथवा दही के साथ भी ले सकते हैं.
- **कृमिरोग-** एक ग्राम कबीला चूर्ण को शहद के साथ मिलाकर चाटने से उदर-कृमि नष्ट हो जाते हैं.
- **रक्तगुल्म-** एक से दो ग्राम कम्पिल्लक चूर्ण में शर्करा अथवा मधु मिलाकर सेवन करने से गुल्म में लाभ होता है.
- कम्पिल्लक पुष्प, सप्तवर्ण, साल, विभीतक, रोहितक, कुटज तथा कपित्थ की छाल को समान मात्रा में लेकर चूर्ण बना लें, पांच ग्राम चूर्ण को मधु या आमलकी स्वरस के साथ सेवन करने से कफज तथा पित्तज प्रमेह में शीघ्र लाभ होता है.
- **त्वचा रोग-** कम्पिल्लक से पकाए हुए तेल को घाव में लगाने से घाव जल्दी भर जाता है.
- **कुष्ठ रोग-** कम्पिल्लक चूर्ण को लगाने से कुष्ठ में लाभ होता है.
- कम्पिल्लक को पीसकर लेप करने से त्वचा के रोगों में लाभ होता है.
- कम्पिल्लक को पानी या तेल में पीसकर लगाने से त्वचा पर रूक्ष या ठण्डी हवा का असर नहीं होता. ■

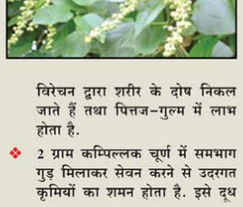

विरेचन द्वारा शरीर के दोष निकल जाते हैं तथा पित्तज-गुल्म में लाभ होता है.

- 2 ग्राम कम्पिल्लक चूर्ण में समभाग गुड़ मिलाकर सेवन करने से उदरगत कृमियों का शमन होता है. इसे दूध

प्रयोज्यांग : फल तथा पत्र.
मात्रा : चूर्ण एक से दो ग्राम.

आचार्य बालकृष्ण

साईं वंदना

बाबा का भक्त-प्रेम

डॉ. चन्द्रभानु सतपथी

भक्तों द्वारा अक्सर यह कहते हुए सुना गया है कि श्री साईंनाथ महाराज या बाबा पता नहीं क्यों उनसे रूठ गये हैं और अब पहले की भांति उन पर कृपालु नहीं हैं. उनकी इस प्रकार की विचारधारा उनके बहुत ही भावात्मक एवं वैयक्तिक दृष्टिकोण को दर्शाती है. श्री साईं के प्रति आस्था एवं विश्वास की यह बहुत ही अनोखी विशेषता है कि (यद्यपि आज बाबा शरीर-रूप में नहीं हैं, फिर भी) भक्त अतिशय भावुकता-पूर्वक उन्हें चाहते हैं. बाबा के ज्यादातर भक्त आत्मिक शांति, आध्यात्मिक मार्गदर्शन और सबसे बढ़कर दैनन्दिन जीवन की सांसारिक समस्याओं के निदान के लिए श्री साईं महाराज पर अत्यधिक निर्भर करते हैं. बहुत से भक्तों के जीवन का भी बाबा जैसे एक अभिन्न अंग हैं. वे उनकी उपासना करते हैं. उनके विषय में पढ़ते हैं, उनका चिन्तन करते हैं, उनके नाम का जाप करते हैं, उनके विषय में चर्चा करते हुए नहीं थकते, उनके नाम से लंगर लगाते हैं और उनके नाम पर दान-पुण्य करते हैं. बहुत से निष्ठावान भक्त कुछ भी खाने-पीने के पहले मानसिक रूप से उसे बाबा को अर्पित करते हैं. ये भक्त छोटे बच्चों के समान बाबा की भांति-भांति की फोटो, सस्ते आभूषण (छल्ले, अंगूठी, लॉकेट आदि) और बाबा से सम्बन्धित अन्य वस्तुएं एकत्रित करते रहते हैं. भक्तों का इस प्रकार का क्रिया-कलाप यह सूचित करता है कि वे मानसिक एवं आत्मिक रूप से सदैव बाबा को ढूंढ रहे हैं तथा वे बाबा से दृढ़ और गहन आत्मीय सम्बन्ध स्थापित करने की कामना करते हैं.

प्रायः यह देखा गया है कि जब भी कोई भक्त श्री साईं बाबा के पास आता है (ऐसा कहा जा सकता है कि बाबा के दिव्य एवं महिमामय व्यक्तित्व के प्रभामंडल में आता है) तो वह बहुत जल्दी उनके प्रति आकर्षित हो जाता है. ऐसे अप्रत्याशित आकर्षण के कारण को सामान्य मानवीय तार्किक बुद्धि से समझा पाना कठिन है. यह सतपुरुषों का आध्यात्मिक आकर्षण ही है. बाबा शिरडी में जब सशरीर थे तो बहुत से भक्त बाबा को देखते ही आध्यात्मिक उन्माद या एक प्रकार के भावावेश की स्थिति में आ जाते थे. श्रीसाईं सच्चरित्र एवं श्री श्री खापर्डे द्वारा लिखित डायरी तथा अन्य पुस्तकों में इस प्रकार के उदाहरण देखने को मिलते हैं. अवतार, सद्गुरु या सतपुरुषों का आकर्षण अत्यंत प्रबल होता है. उदाहरण के तौर पर बाबा के प्रति आस्था न रखने वाले बाला साहेब भाटे जब पहली बार बाबा से मिले, तो उन्होंने शिरडी में ही रुकने का निर्णय लिया और सदैव के लिए वहीं बस गये और जीवन-पर्यन्त केवल बाबा की सेवा करने के लिए अपनी सरकारी सेवा से भी त्यागपत्र दे दिया.

बहुत से भक्त श्री साईं जैसे गुरु के साथ संबंध को जीवन की सबसे अधिक बहुमूल्य निधि मानते हैं. अपनी स्थूल देह त्यागने के पूर्व बाबा ने अपने भक्तों को यह आश्वासन दिया था कि वे सूक्ष्म रूप से सदैव अपने भक्तों की रक्षा करते रहेंगे. उन्होंने यहां तक कहा था कि जब भी उनके भक्त सच्चे मन से उन्हें पुकारेंगे, तो वे किसी-न-किसी रूप में अपनी उपस्थिति का अनुभव अवश्य करायेंगे और उनके कष्ट दूर करने में सहायता करेंगे. आज भी भक्तों के जीवन में होने वाली घटनाएं यह सिद्ध करती हैं कि समाधि लेने के उपरान्त बाबा भक्तों को दिए अपने वचन को निभा रहे हैं.

जारी...

चौथी दुनिया स्पूल feedback@chauthiduniya.com

साईं भक्तों! आप भी चौथी दुनिया को साईं से जुड़ा लेख या संस्मरण भेज सकते हैं. मालूम, साईं से आप कब और कैसे जुड़े, साईं की कृपा आपको कब से मिलनी शुरू हुई. आप साईं को क्यों पूजते हैं. कैसे बने आप साईं भक्त. साईं बाबा का जीवन और चरित्र आपको किस तरह से प्रेरित करता है? साईं बाबा के बारे में अनेक किंवदंतियां हैं, क्या आपके पास भी कुछ कहने के लिए है? अगर हां, तो केवल 500 शब्दों में अपनी बात कहने की कोशिश करें और नीचे दिए गए पते पर भेजें.

फॉर्म में लौटे पुजारा-मुरली

- इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने भी दिया करारा जवाब
- विराट की सेना को मिल रही है कुक की टीम से कड़ी टक्कर
- पहले टेस्ट में दिखा बल्लेबाजों का जलवा

सैयद मोहम्मद अब्बास

भारत और इंग्लैंड के बीच टेस्ट सीरीज शुरू हो गई. टीम इंडिया ने हाल में टेस्ट क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन किया है. विराट की सेना ने न्यूजीलैंड को भारतीय सरजमीं पर करारी शिकस्त दी थी. अब उसके सामने इंग्लैंड की टीम है. इंग्लैंड की टीम का प्रदर्शन बांग्लादेश के खिलाफ उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा है. ऐसे में भारतीय टीम को थोड़ा फायदा मिलता दिख रहा है लेकिन इंग्लैंड की टीम भारतीय पिचों पर हमेशा बेहतर प्रदर्शन करती रही है. पांच टेस्ट मैचों की सीरीज के पहले टेस्ट में मेहमान टीम ने भारतीय टीम को कड़ी टक्कर देकर टीम इंडिया को थोड़ा चौंका दिया है. कुक की टीम में कई ऐसे खिलाड़ी हैं जो स्पिन विकेट पर खेलने में माहिर हैं. मेहमान टीम के तीन बल्लेबाजों ने पहली पारी में शतक जड़कर भारतीय गेंदबाजों के नाक में दम कर दिया. राजकोट टेस्ट में इंग्लैंड ने पहली पारी में शानदार बल्लेबाजी की. रूट, मोइन अली और स्टोक्स ने शतक जड़कर भारतीय कैम्प में थोड़ी चिंता बढ़ा दी. इंग्लैंड ने इसके साथ ही 537 रन का बड़ा स्कोर खड़ा कर भारतीय बल्लेबाजों पर अच्छा खासा दबाव डाल दिया लेकिन मुरली व पुजारा ने इंग्लैंड के गेंदबाजों का डटकर मुकाबला किया. भारत ने पहली पारी में मुरली व पुजारा के जोरदार शतक की बदौलत 488 रन बनाने में कामयाबी हासिल की, लेकिन दूसरी पारी में उसकी बल्लेबाजी बिखरती हुई दिखायी पड़ी. आलम तो यह रहा कि टीम इंडिया ने किसी तरह से राजकोट टेस्ट बचा लिया. राजकोट टेस्ट में टीम इंडिया ने गम्भीर को अंतिम एकादश में शामिल करने का फैसला किया लेकिन उनका बल्ला एक बार फिर खामोशी की चादर ओढ़े रहा. अब यह देखना होगा कि गम्भीर को और कितने मौके कप्तान विराट देते हैं.

दूसरी ओर पुजारा व मुरली विजय ने अपने बल्ले से आलोचकों को करारा जवाब दिया है. बात अगर पुजारा की कि जाये तो वह भारतीय पिचों पर शेर की तरह बल्लेबाजी करते हैं लेकिन विदेशी पिचों पर उनका खेल उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा है. खैर राजकोट टेस्ट में उन्होंने बड़े धैर्य के साथ बल्लेबाजी की. पुजारा ने अपने करियर का नौवां शतक अपने घरेलू मैदान पर जड़ा. पुजारा ने 169 गेंदों का सामना करते हुए यह शतक लगाया है. उन्होंने इस पारी के दौरान 15 चौके भी लगाये. पुजारा के करियर पर नजर दौड़ायी जाये तो इतना साफ है कि वे लम्बी रेस के घोड़े साबित हो सकते हैं. उनकी बल्लेबाजी में राहुल द्रविड़ की झलक दिखती है. दरअसल राहुल को टीम इंडिया की दीवार कहा जाता था. उनके संन्यास के बाद पुजारा को टीम इंडिया की अगली दीवार की तरह देखा जाने लगा है. पुजारा ने अब तक 39 टेस्ट में 2997 रन बनाये हैं. उनका औसत भी बेहद शानदार है. उन्होंने 49.95 औसत से नौ शतक लगाये हैं. पुजारा इससे पहले घरेलू मैदान पर रणजी के रण में कई बार रंग जमा चुके हैं लेकिन अबकी बार वह अंतरराष्ट्रीय मैच में अपने बल्ले से घरेलू दर्शकों को भी अपना मुरीद बना लिया है. हाल के दिनों में कई मौकों पर पुजारा का बल्ला रूठा दिख रहा था लेकिन भारतीय पिचों पर वह फॉर्म पाने सफल रहे. भारत के बाहर उनका प्रदर्शन बेहद कमजोर रहा है. उन्होंने साल 2014 में इंग्लैंड व ऑस्ट्रेलिया जैसी पिचों पर उनका बल्ला रनों के लिए संघर्ष करता दिखा है. उन्होंने ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच खेले गये कुल आठ टेस्ट मैचों में केवल 423 रन बनाये हैं. ऐसे में उनकी तुलना राहुल द्रविड़ जैसे बड़े बल्लेबाज से करना अभी जल्दीबाजी होगी. राहुल द्रविड़ के बल्ले ने विदेशी पिचों पर भी अपना लोहा मनवाया था. पुजारा को अभी लम्बा सफर तय करना है.

राजकोट टेस्ट में मुरली विजय ने भी अपने बल्ले की ताकत दिखायी है. टीम इंडिया में इस समय सलामी बल्लेबाजों की भरमार देखी जा सकती है. विजय ने इंग्लैंड के खिलाफ शतक जड़कर टीम में अपनी जगह को और मजबूती दी है. सलामी बल्लेबाजों की लिस्ट में एक ओर गम्भीर अभी अपनी जगह पक्की नहीं कर सके जबकि शिखर धवन व केएल राहुल जैसे बल्लेबाज बतौर सलामी बल्लेबाज के रूप में अपना दावा ठोक रहे हैं. ऐसे में विजय का शतक उनके करियर को एक नई राह प्रदान करेगा. दरअसल न्यूजीलैंड के खिलाफ उनका प्रदर्शन खराब रहा है. अब तक के 43 टेस्ट में विजय ने 40.82 की औसत से 2980 रन बनाये हैं. इस दौरान उन्होंने सात शतक जमाये हैं. कुल मिलाकर विजय हों या फिर गम्भीर दोनों को अपनी बल्लेबाजी में और सुधार करना होगा ताकि वह अपनी जगह टीम में पक्की कर सकें.

दूसरी ओर भारतीय टीम को इंग्लैंड के खिलाफ अच्छा प्रदर्शन करना होगा क्योंकि इंग्लैंड की टीम लय में लौटती दिख रही है. उसके पास स्पिनरों के खिलाफ खास योजना दिख रही है. अश्विन व जडेजा को भी उनके बल्लेबाज आसानी से खेल रहे हैं. भारत को अगर इंग्लैंड को धूल चटानी है तो टीम को हर विभाग में सुधार करना होगा. विराट की टीम में कई धाकड़ बल्लेबाज शामिल हैं जो लम्बी पारी खेलने में माहिर हैं. विराट और रहाणे से भी टीम को अच्छी खासी उम्मीद है. दोनों ही बल्लेबाज इस समय शानदार फॉर्म में दिख रहे हैं. विराट बतौर कप्तान भी चमक रहे हैं लेकिन इंग्लैंड जैसी मजबूत टीम के सामने उनकी कप्तानी की असली परीक्षा होगी. अब यह देखना रोचक होगा कि मेहमान टीम को टीम इंडिया कैसे रोकती है. ■

सायना को फिटनेस ने किया बेहाल

सर्जरी के बाद पुरानी लय हासिल करने का दबाव

हाल के दिनों में सायना की खराब फिटनेस के चलते उनकी साख पर असर पड़ा है. रियो ओलम्पिक में उनकी हार को लेकर भी कई सवाल उठाये गये. इसके बाद उनकी गिरती फिटनेस ने उन्हें काफी समय से कोर्ट से दूर रखा. सायना अब अपनी फिटनेस को लेकर काफी समय से काम कर रही हैं. देखना है कि घुटने की सर्जरी के बाद वह कोर्ट पर कैसा प्रदर्शन करती हैं.

सायना नेहवाल को भारत में बैडमिंटन का सबसे बड़ा सितारा माना जाता है, लेकिन हाल के दिनों में सायना का जादू कम हो गया है. उनकी खराब फिटनेस और फॉर्म दोनों ही उनके करियर में अब सबसे बड़ा रोड़ा साबित हो रहे हैं. एक दौर ऐसा भी था जब सायना लगातार नये प्रतिमान स्थापित कर रही थी. उनकी हर जीत पर पूरे विश्व में चर्चा होती थी. आलम तो यह था कि चीनी खिलाड़ी भी उनके सामने आने से कतराते थे. सायना ने अपने खेल की बदौलत रैंकिंग में टॉप टेन में जगह भी बनायी. लंदन ओलम्पिक में उनको किसी तरह से पदक मिल गया लेकिन रियो के खेल में वह नाकाम रहीं. इसके बाद उनकी खराब फिटनेस ने उनके खेल पर ब्रेक लगा दिया. अभी हाल में उन्होंने सर्जरी करायी है. सर्जरी के बाद वह दोबारा कोर्ट पर लौटने का दम भर रही हैं. जानकारों की मानें तो सायना को अपनी फिटनेस पाने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी. उनकी खराब फिटनेस के चलते प्रो बैडमिंटन लीग की नीलामी में कोई खरीददार नहीं मिल रहा था. किसी तरह से अवध वॉरियर्स ने 33 लाख की रकम पर खरीदा. बैडमिंटन लीग के पहले सीजन में सायना को हाथों-हाथ लिया गया था लेकिन इस बार उनकी चोट के चलते फ्रैंचाइजियों ने उनको शामिल करने में कोई खास रुचि भी नहीं दिखायी. दरअसल सायना के खेल में अब पहले जैसी बात नहीं दिखती है. सायना की जगह अब पीवी सिंधु का नाम सबसे ज्यादा सुर्खियों में बना रहता है. यह कोई आम बात नहीं है, हर खिलाड़ी का बुरा वक्त आता है. क्रिकेट से

लेकर फुटबॉल के नामी गिरामी सितारों का करियर कभी एक जैसा नहीं रहा है. बड़े से बड़ा खिलाड़ी अपनी खराब फिटनेस के चलते बेहाल रहता है.

सायना के करियर पर नजर दौड़ायी जाये तो इतना तो साफ है कि वह आसानी से हार मानने वाली नहीं हैं. अपनी चोट को ध्यान में रखकर सायना ने अभी हाल में बड़ा बयान भी दिया. उनके अनुसार उनका करियर चोट के चलते खतरे में पड़ गया है. सायना को अब उम्मीद है कि वह इस साल वापसी करने में सफल रहेंगी. सायना ने अपने जानदार खेल की बदौलत देश का गौरव बढ़ाया है. जूनियर स्तर से लेकर सीनियर स्तर पर सायना भारतीय बैडमिंटन की रोल मॉडल बन गयीं. सायना अपने करियर में अब तक 22 खिताब अपने नाम कर चुकी हैं. इसमें सुपर सीरीज जैसी बड़ी प्रतियोगिता शामिल है. सायना ने जूनियर स्तर पर भी कई बड़ी प्रतियोगिता अपने नाम की है. जूनियर स्तर पर साल 2003 से लेकर 2008 तक तीन बड़े खिताब जीतकर सबको अपने बैडमिंटन का लोहा मनवाया. इतना ही नहीं नेशनल लेवल पर 12 खिताब भी जीते. सायना के सफर पर एक नजर डाली जाये तो साफ है कि यहां तक पहुंचने के लिए उन्होंने कड़ी मेहनत की है. शुरुआती दौर में सायना कराटे जैसे खेल में अपनी प्रतिभा को निखारने में लगी थीं, लेकिन भगवान को कुछ और ही मंजूर था. उनके पिता को यकीन था कि सायना कराटे में नहीं बल्कि बैडमिंटन में अपनी प्रतिभा के साथ न्याय कर सकेंगी. उस दौर में हैदराबाद जैसे शहर में गोपीचंद की खूब तूती बोलती थी. शायद पिता ने इसी को ध्यान में रखकर सायना को बैडमिंटन अकादमी डाल दिया. उनके इस हुनर को तब और बल मिल गया जब गोपीचंद ने उनको कोचिंग देना शुरू कर दिया. सायना आज भी गोपीचंद की तारीफ करती हैं कि उनके सहयोग से उनके खेल को एक नई दिशा मिली. गोपीचंद की स्पोर्ट्स अकादमी से निकलने वाली यह नायाब खिलाड़ी अपनी बैडमिंटन की कला से हर किसी को प्रभावित और चकित करने में सफल रही. बैडमिंटन के तमाम बड़े खिताब अपने नाम करने वाली सायना के प्रदर्शन को देखकर भारत में बैडमिंटन की शक्ल बदलते हुए देर नहीं लगी. एकाएक गोपीचंद को भारत के सबसे बड़े कोच के रूप में देखा जाने लगा. सायना ने इंडोनेशिया ओपन जीतकर विश्व बैडमिंटन पटल पर एक अलग पहचान बना डाली. उस दौर में बैडमिंटन की कई नयी प्रतिभाएं गोपीचंद की अकादमी में सामने आने लगी. इसी दौर में पीवी सिंधु ने भी अपने खेल की बदौलत देश का मान बढ़ाया. सायना के बाद सिंधु भी बहुत बड़ी स्टार के रूप में सामने आयीं. गोपीचंद के सहारे सायना लगातार आगे बढ़ रही थीं. विश्व रैंकिंग में उनका जलवा देखने को मिला. हालांकि बाद में वह गोपीचंद से अलग होकर विमल कुमार से कोचिंग लेने लगीं. इसको लेकर मीडिया में भी काफी चर्चा रही. गोपीचंद ने सायना को लम्बे अरसे से कोचिंग दी. लंदन ओलम्पिक में अगर सायना को पदक मिला तो इसमें गोपीचंद का खास योगदान था. साल 2014 में उन्होंने गोपी का साथ छोड़कर विमल कुमार से कोचिंग लेने का फैसला कर लिया. हालांकि गोपी से अलग होने को लेकर सायना ने कभी कोई ठोस जवाब नहीं दिया. हाल में शिक्षक दिवस के दिन भी वह गोपीचंद को भूल गई थीं. इसको लेकर भी उनकी कड़ी आलोचना की गई थी.

हाल के दिनों में सायना की खराब फिटनेस के चलते उनकी साख पर असर पड़ा है. रियो ओलम्पिक में उनकी हार को लेकर भी कई सवाल उठाये गये. इसके बाद उनकी गिरती फिटनेस ने काफी समय से कोर्ट से दूर रखा. सायना अब अपनी फिटनेस को लेकर काफी समय से काम कर रही हैं. देखना है कि घुटने की सर्जरी के बाद वह कोर्ट पर कैसा प्रदर्शन करती हैं. ■

feedback@chauthiduniya.com

जल्द चार फिल्में साइन करेंगी प्रियंका चोपड़ा!

बॉ जीराव मस्तानी के बाद से प्रियंका चोपड़ा के फैंस उनकी फिल्मों का इंतज़ार बड़ी बेसब्री से कर रहे हैं, पर प्रियंका बॉलीवुड में नहीं हॉलीवुड में इस समय ज्यादा व्यस्त है. लेकिन हाल ही में प्रियंका के फैंस को ये जानकर खुशी होगी कि प्रियंका जल्द ही भारत आएंगी और वह एक नहीं, दो नहीं बल्कि चार फिल्में साइन करेंगी. रिपोर्ट्स की मानें तो प्रियंका के पास अंग्रेज़ी और हिंदी प्रोजेक्ट्स के ढेर सारे ऑफर हैं. दिसंबर में यहां आने के बाद प्रियंका एक नहीं बल्कि चार फिल्में फाइनल करेंगी. आपको बता दें कि प्रियंका दिसंबर के पहले सप्ताह में यहां आएंगी और करीब तीन सप्ताह के लिए रुकेंगी. इस बीच सभी अंग्रेज़ी और हिंदी स्क्रिप्ट को पढ़ने के लिए पूरा समय लेंगी, जिसके बाद चार फिल्में फाइनल करेंगी. हालांकि वो फिल्में हिंदी होंगी, अंग्रेज़ी होंगी या मिली-जुली होंगी, इसकी जानकारी नहीं है.

बस सभी को प्रियंका से उम्मीद है कि वो हिंदी फिल्म ज़रूर साइन करेंगी. फिलहाल प्रियंका अभी हॉलीवुड में अपना करियर बना रहीं है.■

रियल लाइफ में कठोर पिता नहीं हैं आमिर ख़ान

आ मिर खान की बहुचर्चित फिल्म *दंगल* जिसका दर्शकों को बड़ी बेसब्री से इंतेजार है, दिसंबर में रिलीज होने को तैयार है. फिल्म दंगल का गाना *बापू तू तो सेहत के लिए हानिकारक है*, जबसे रिलीज़ हुआ है तभी से ही लोगों के ज़बान पर चढ़ गया है. ये गाना वाकई में लोग काफी पसंद कर रहे हैं. गाने में आमिर बिल्कुल एक कठोर पिता लग रहे हैं जो अपनी दोनों बेटियों के साथ काफी स्ट्रिक्ट हैं और उन्हें पहलवानी के लिए प्रेरित कर रहे हैं.

इस पर आमिर खान ने कहा है मैं असल जिंदगी में हानिकारक बापू नहीं हूं. आमिर ने कहा कि मैं असल जिंदगी में काफी कूल हूं और बिल्कुल भी स्ट्रिक्ट नहीं हूं. आमिर ने बताया कि फिल्म *तारे ज़मीन पर* के समय काफी रिसर्च की थी, तब उन्होंने पाया कि बच्चों को सिर्फ प्यार चाहिए. उन्हें सिर्फ अपने माता-पिता का सपोर्ट चाहिए. आपको बता दें कि फिल्म दंगल में आमिर एक पिता का किरदार निभा रहे हैं.

फिल्म *दंगल* महावीर सिंह फोगट की सच्ची कहानी पर आधारित है, जिन्होंने अपनी बेटियों गीता और बबीता को कुश्ती सिखाई और उन्होंने राष्ट्रमंडल खेलों में पदक जीते.■

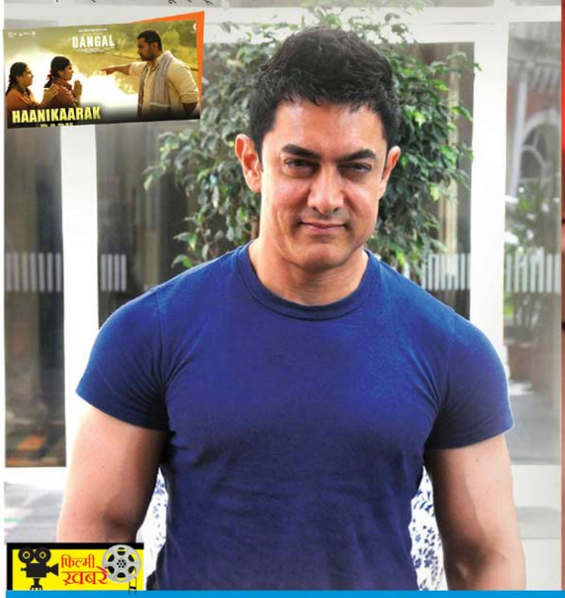

विदेश में दीपिका की हुई बेइज़्ज़ती

दीपिका पादुकोण हमेशा ही अपने स्टाइल स्टेटमेंट के लिए चर्चा में रही हैं, लेकिन अचानक उनके स्टाइल स्टेटमेंट को लेकर कुछ ऐसे ब्लंडर हो गये कि दीपिका काफी दुखी हो गयीं और अब उन्होंने एक बड़ा फ़ैसला लिया है.

दीपिका पादुकोण बॉलीवुड की उन अभिनेत्रियों में से एक हैं, जो खुद की फिल्में अपने दम पर हिट करवाना जानती है. खूबसूरती के साथ-साथ दीपिका का अभिनय करने में भी कोई सानी नहीं है.

दीपिका पादुकोण हमेशा ही अपने स्टाइल स्टेटमेंट के लिए चर्चा में रही हैं, लेकिन अचानक उनके स्टाइल स्टेटमेंट को लेकर कुछ ऐसे ब्लंडर हो गये कि दीपिका काफी दुखी हो गयीं और अब उन्होंने एक बड़ा फ़ैसला लिया है.

दरअसल, हाल ही में एमटीवी के यूरोप म्यूज़िक अवॉर्ड के दौरान उन्होंने मोनिषा जैसिंग की स्टाइल की गयी ड्रेस को कॉपी किया. दीपिका को उनके इस स्टाइल के लिए अपने देश में तो काफी लोकप्रियता मिली, लेकिन एक इंटरनेशनल डेली ने उनका जमकर मज़ाक़ उड़ाया और वो इस बात को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पायीं. उन्हें बॉलीवुड के अब तक के सबसे वर्स्ट ड्रेस्ड सेलेब्स में शामिल कर लिया गया और इसकी वजह से दीपिका ने अपना पूरा गुस्सा अपनी स्टाइस्टि पर निकाल दिया.

अब सुनने में यह आ रहा है कि ऐसा पहली बार हो रहा है, जब दीपिका ने अपनी स्टाइलिस्ट पर गुस्सा निकाला हो. उनकी स्टाइलिस्ट भी चुपचाप इन बातों को सुन रही हैं, क्योंकि आमतौर पर दीपिका को अपने स्टाफ पर गुस्सा करने की आदत नहीं है. ऐसे में इस बार उन्हें स्टाइल को लेकर काफी आलोचना सहनी पड़ी है, इसलिए वो गुस्से में आ गयीं. ख़बर यह भी है कि यह अपने इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स के लिए दीपिका किसी इंटरनेशनल स्टाइलिस्ट को हायर कर सकती हैं, ताकि उनके ड्रेसिंग सेंस पर कोई कमेंट ना कर सके. ■

चौथी दुनिया ब्यूरो

feedback@chauthiduniya.com

मेरी देशभक्ति से विरोधियों को दिक़्क़त होती है: अनुपम खेर

राजधानी के विधानसभा परिसर में तीन दिनों से चल रहे लोक-मंथन के समापन समारोह में पहुंचे खेर ने कहा कि देशभक्ति हमें न सिखाओ. यह सही है कि कोई किसी को देशभक्ति नहीं सिखा सकता, यह तो भीतर से आती है. देशभक्ति हमारे ख़ून में है. जब भी अवसर आता है, यह प्रकट होती है.

बॉलीवुड में एक लंबे अरसे से हम अनुपम खेर को देखते आ रहें है. इसमें कोई शक नहीं है कि जब वह एक्टिंग करते है, तो अच्छे से अच्छे कलाकार को मात देने की ताकत रखते हैं. हाल ही में कुछ दिनों पहले अनुपम खेर का एक बयान सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि वह जब देशभक्ति की बात करते हैं तो कुछ लोगों को परेशानी होने लगती है. राजधानी के विधानसभा परिसर में तीन दिनों से चल रहे लोक-मंथन के समापन समारोह में पहुंचे खेर ने कहा कि हमें देशभक्ति न सिखाओ. यह सही है कि कोई किसी को देशभक्ति नहीं सिखा सकता, यह तो भीतर से आती है. देशभक्ति हमारे खून में है. जब भी अवसर आता है, यह प्रकट होती है. देशभक्ति की बात से अगर किसी को पीड़ा होती है तो होने दीजिए, हम तो अपना काम करेंगे.

उन्होंने कहा कि पिछले दो-तीन सालों में असहिष्णुता और देशभक्ति के विषय जान-बूझकर उठाए गए हैं. जब असहिष्णुता की बहस शुरू की गई, तब मेरे भीतर का भारतीय जागा और उसने कहा कि यह चुप रहने का समय नहीं है. इस कारण मैंने असहिष्णुता पर सवाल उठाने वालों का खुलकर विरोध किया. खेर ने कहा कि वह कश्मीरी पंडित हैं, इसलिए उनकी रगों में देशभक्ति है. अपने ही देश में निर्वासित होने के बाद भी कश्मीरी पंडितों ने कभी भी देश के ख़िलाफ कोई बात नहीं कही. उन्होंने कहा कि देश में प्रदूषण का बोलबाला है, स्वच्छ पानी नहीं है. गति की शीघ्रता और स्थिति की स्थिरता ने विचित्र परिस्थिति पैदा कर दी है. हर व्यक्ति चुनौतियों की चर्चा करता है. समाधान किसी के पास नहीं है. उन्होंने आगे कहा कि हिंसा की अत्यधिक वृद्धि, युद्ध और आतंकवाद के रूप में दिखाई देती है. मनुष्य कहीं भी स्वयं को सुरक्षित महसूस नहीं करता है. महाभारत का युद्ध 18 दिन में समाप्त हो गया, लेकिन वियतनाम का 18 वर्ष चला. अपना शख बाजार बनाए रखने के लिए तब भी हिंसा हुई, जो आज तक जारी है.■

परिणीति चोपड़ा करेंगी गोलमाल

अरे रूकिए, हम यहां किसी तरह की हेरा फेरी की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि रोहित शेट्टी की सुपरहिट सीरीज फिल्म गोलमाल का अगला पार्ट *गोलमाल 4* की बात कर रहें हैं. जिसकी शूटिंग जल्द ही शुरू होने जा रही है. इस फिल्म में अभिनेत्रियों को लेकर पिछले कुछ समय से काफी अफवाहें फैल रहीं थी. करीना प्रेगनेंट होने की वजह से पहले ही इस फिल्म को मना कर चुकी थी. लेकिन बाद में इस फिल्म में अभिनेत्रियों को लेकर लगातार अफवाहें सामने आती रहीं, जिनमें श्रद्धा कपूर, दीपिका पादुकोण से लेकर आलिया भट्ट तक शामिल थी. लेकिन अब फिल्म की हीरोइन को लेकर लगाई जा रहीं अटकलें साफ हो गई हैं और यह फाइनल हो चुका है कि इस फिल्म की हीरोइन परिणीति चोपड़ा होंगी. बता दें कि परिणीति काफी लंबे से बॉलीवुड से बाहर हैं, उनकी शुरूआत तो बॉलीवुड में अच्छी हुई थी पर वह इस सफलता को ज्यादा आगे नहीं ले जा सकीं. रोहित शेट्टी की अगली फिल्म गोलमाल-4 में वह फाइनल की गई हैं जिससे वह बहुत खुश है? ■

जब हुआ करीना-शाहिद का सामना !

प्रवीण कुमार

feedback@chauthiduniya.com

शाहिद और करीना एक समय में बॉलीवुड के काफी चर्चित कपल थे. लेकिन कहते है ना कि जोड़ियां ऊपर से बनकर आती हैं, इनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ और इस जोड़ी को किसी की नज़र लग गई. आपको बता दें कि शाहिद और करीना पहले रिलेशन में थे, लेकिन बाद में दोनों अलग हो गए.

शाहिद और करीना का ब्रेकअप भी ऐसा हुआ कि इन दोनों ने फिर कभी एक दूसरे का चेहरा नहीं देखा. करीना ने इसके बाद सैफ अली खान को डेट किया फिर बाद में शादी कर ली. अब करीना प्रेग्नेंसी पीरियड एंजॉय कर रही हैं. करीना और शाहिद ने काफी लंबे समय तक एक साथ काम नहीं किया लेकिन किसी तरह यह दोनों इसी साल फिल्म *उड़ता पंजाब* में काम करने को तैयार हो गए. हालांकि फिल्म में दोनों का एक सीन भी साथ में फिल्माया नहीं गया था और ना ही दोनों ने कभी फिल्म प्रमोशन के दौरान एक दूसरे से बात की. लेकिन अब इनके फैंस को जानकर खुशी होगी कि अब इन दोनों के बीच सभी गिले-शिकवे दूर हो गए हैं. जी हां, फाइनली करीना कपूर और शाहिद कपूर के बीच की दूरियां अब ख़त्म हो गई हैं और दोनों ने एक-दूसरे को गले लगा ही लिया. आप सोच रहे होंगे कि ये कब कहां कैसे हुआ और क्यों हुआ...तो चलिए हम आपको पूरा किस्सा बताते हैं कि आखिर ये हुआ कैसे.

दरअसल, ये सब हाल ही में हुए लक्स गोल्डन रोज़ अवॉर्ड फंक्शन में हुआ. इस फंक्शन के दौरान शाहिद अपनी स्टेज परफॉर्मेंस के लिए इंतज़ार कर रहे थे. बस वहीं करीना और शाहिद का एक-दूसरे से सामना हो गया. अब इसके बाद जो हुआ वो वाकई में कमाल का था. शाहिद और करीना ने एक-दूसरे को हग किया और बधाई दी. एक ओर जहां शाहिद ने करीना को आने वाले बच्चे की शुभकामनाएं दीं, वहीं दूसरी ओर करीना ने भी फिल्म उड़ता पंजाब की सफलता और हाल ही में पिता बनने के लिए बधाई दी. करीना और शाहिद ने कई फिल्मों में साथ काम भी किया है. जिनमें से *जब वी मेट* काफी हिट हुई.■